प्रभात

इस अंक में .....

★ सी-कम्पोसा के तीसरे सम्मेलन की रपट... 7
★ सीपीएन(एम) का दस्तावेज अन्तरविरोधों का सही ढंग से हल करते हुए ... 8
★ कॉमरेड गौरव से मिलने आए जर्मन प्रतिनिधिमण्डल के साथ दुरव्यवहार... 13
★ दण्डकारण्य के संघर्षों की रपटें... 14
★ माओ के लेख ... 25

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्स वार] दण्डकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

वर्ष - 17 अंक - 2 अप्रैल-जून 2004 सहयोग राशि - 10 रुपए

14वीं लोकसभा चुनावों पर रिपोर्ट

गठबन्धन चाहे जो भी आए पर सरकार की बुनियादी नीतियों में कोई फर्क नहीं !

जनयुद्ध के रास्ते पर लड़ना ही आज का एक मात्र विकल्प

14वीं लोकसभा को समय से पहले हुए चुनावों के नतीजों ने भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (राजग) को गद्दी से उतार दिया। 22 पार्टियों के गठजोड़ से सत्तारूढ़ हुए राजग के घटक पक्षों की संख्या चुनाव के पहले तक 16 तक गिर गई। इन चुनावों के प्रचार के तहत भाजपा ने जो नीतियां सामने लाईं और जो लोकलुभावन नारे लगाए, उन्हें चुनावी तिकड़मबाजी ठहराते हुए मतदाताओं ने उसे कड़ा सबक सिखा दिया। 'फील गुड', 'भारत उदय', 'अटल फैक्टर', फिल्मी सितारों के दौरे, भाजपा के 'टाप टेन' की देखरेख में चलाया गया हाई-टेक प्रचार आदि मतदाताओं को लुभाने में नाकाम हो गए। सोनिया के विदेशी मूल, राम मन्दिर निर्माण का मुद्दा, पांच सालों में हासिल विकास आदि इस गठबन्धन के मुद्दों को मतदाताओं ने सिरे से नकार दिया। चुनावी नतीजों ने यह साबित किया कि गुजरात के कत्लेआम, शिक्षा का भगवाकरण, साम्प्रदायिक उन्माद, लगातार पड़ रहे अकाल के प्रति सरकार की लापरवाही, लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को हल करने में सरकार की नाकामी, लाभ कमाने वाले सरकारी उद्योगों की सस्ती बिक्री, मजदूरों की छंटनी, किसानों में बढ़ती आत्महत्याओं के प्रति सरकार की घोर उपेक्षा आदि समस्याओं को मतदाताओं ने गंभीरता से लिया है। अलग-अलग राज्य सरकारों और राजग की केन्द्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुके मतदाताओं ने उन सरकारों और राजग के खिलाफ वोट डाला जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) सत्ता में आ गई। 14 पार्टियों के मेल से बने इस गठबन्धन का नेतृत्व सोनिया गांधी (!) कर रही है जबकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गया। जो भी पार्टी चाहे जिस गठबन्धन में भी शामिल हो जाए ये सब पिछले 52 सालों से किसी न किसी रूप में देश पर शासन करती ही रही हैं। आमतौर पर ये पार्टियां जहां केन्द्र में गठबन्धन बना रही हैं, वहीं राज्यों में अपने बल बूते पर शासन कर रही हैं। ये जहां भी शासन करें जनता की एक भी बुनियादी समस्या हल नहीं हुई। ये कर भी नहीं सकतीं। कोई भी गठबन्धन जीत जाए जनता को अतिरिक्त करों का बोझ, महंगाई, बेरोजगारी में वृद्धि, कर्जों का बोझ, भूख, गरीबी, मुफ्त शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं का अभाव आदि समस्याओं से दो-चार होना ही पड़ेगा।

देश में किसी एक बुर्जुवाई या संशोधनवादी पार्टी अपने बल बूते पर शासन नहीं कर सकेगी, इसकी पुष्टि इन पार्टियों के पतनशील तौर-तरीकों से ही हो जाती है। पिछले एक दशक के दौरान यह रुझान बढ़ गया है। देश में आज मान्य छह राष्ट्रीय पार्टियों में किसी एक की भी यह स्थिति नहीं है कि वह अकेले अपने दम पर सरकार बना सके। लेकिन इस बात का एहसास कांग्रेस को काफी देर से हुआ तभी उसने अपने 'पचमढ़ी' सम्मेलन के फैसलों को त्याग दिया। दस सालों से सत्ता के सुख से दूर रही कांग्रेस ने किसी भी तरीके से केन्द्र में सत्ता पाने की लालसा से अनिवार्य रूप से गठबन्धन बनाया। राष्ट्रीय जनतादल (आरजेडी), लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी), राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), द्रविड मुन्नेट्र कजगम (डीएमके), तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), इत्यादि पार्टियों से चुनाव के पहले बनाए गठबन्धन के परिणामस्वरूप कांग्रेस ने 145 सीटें जीत लीं। उसके गठबन्धन को कुल 220 सीटें मिलने से वह बहुत बड़े गठबन्धन के रूप में उभरा। इसके बावजूद उसे आवश्यक बहुमत नहीं मिल सका। ऐसी परिस्थितियों में भाकपा, माकपा, आदि संशोधनवादी पार्टियों ने कांग्रेस के प्रति पूरी वफादारी दिखाई। कुछ राज्यों में कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल करने वाले संशोधनवादियों ने इस बार अभूतपूर्व तरीके से 62 सीटें हासिल कीं। कांग्रेस में जो गुण नहीं हैं उनके उसमें होने का

28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद - सप्ताह मनाओ !

प्रचार करते हुए वे कांग्रेस को मुश्किलों से उबारने में लगे हुए हैं। ऐसा उन्होंने पहली बार भी तो नहीं किया, बल्कि 1969 से वे लगातार करते आ रहे हैं। गौरतलब है कि अब तक विरोधी खेमों में रहने वाली भाकपा और माकपा अब धर्मनिरपेक्षता के नाम से एक जगह आ गईं। कांग्रेस पार्टी के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थन से सरकार का गठन करके चलाने में यूपीए को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि संशोधनवादी पार्टियों के एजेन्डे में और कांग्रेस के एजेन्डे में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। यह है संशोधनवादी पार्टियों की असलियत।

सत्ता पर काबिज होने के बाद यूपीए सरकार नित नए वादे करती जा रही है। याद रहे कि इसके पहले राजग ने भी इससे बढ़कर वादे किए थे। अब यूपीए पोटा को रद्द करने की बात कर रहा है। लेकिन गृहमंत्री का कहना है कि इसके स्थान पर एक दूसरे कानून की जरूरत तो है। सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत शिक्षा पर और 3 प्रतिशत चिकित्सा पर खर्च करने की बात की जा रही है। आगामी पांच सालों में राजस्व घाटा कम करने की बात कर रहे हैं। आगामी तीन सालों में ग्रामीण इलाकों को दोगुना कर्ज देकर किसानों को मदद देने की बात कर रहे हैं। बेरोजगारों को सालाना 100 दिन रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कर रहे हैं। विकासोन्मुख, रोजगारोन्मुख और पूंजीनिवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से आम आदमी के विकास को ही अपना मकसद कहकर यूपीए ने उदारवादी नीतियों की अपनी दिशा स्पष्ट कर दी है। यही असली विषय है। कांग्रेस आज भी गर्व से कहती है कि देश में नई आर्थिक नीतियों पर अमल उसी ने शुरू किया है। नई आर्थिक नीतियों का मतलब साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों के अलावा कुछ नहीं है। जो भी सरकार इन नीतियों के तहत काम करेगी तो अगर कोई फर्क होगा तो सिर्फ उनके अमल की रफ्तार में ही होगा। इन्हीं नीतियों से जनता की जिन्दगी बदतर होती जा रही है। देश में अभूतपूर्व तरीके से 5 हजार किसानों द्वारा खुदकुशी इन्हीं नीतियों की बदौलत है। नए-नए तरीकों से मजदूरों को नौकरियों से हटाया जा रहा है तो यह इन्हीं नीतियों का नतीजा है। इन्हीं नीतियों के नतीजतन आम आदमी को शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा नकली बीज, नकली दवाएं बिकवाते हुए, किसानों को समर्थन मूल्यों से वंचित करके किसानों को डब्ल्यूटीओ की नीतियों के चक्कर में पिसाने वाली नीतियां इन्हीं नीतियों का हिस्सा है। इनके दुष्परिणामों के खिलाफ जनता ने हड़ताल, धरना, जुझारू संघर्ष आदि छेड़ दिया तो उनका दमन भी इन्हीं नीतियों के तहत होता रहा है। ये नीतियां नागरिक व जनवादी अधिकारों के खिलाफ हैं। एक शब्द में कहें तो ये नीतियां जन विरोधी और साम्राज्यवाद के अनुकूल हैं। जो भी सरकार इनके तहत काम करेगी तो वह जो निर्णय लेती और जो कार्यवाही करती है अन्ततः वह जनता पर बोझ ही साबित होगा।

'आजादी' के बाद से अब तक कांग्रेस ने ही ज्यादा समय देश पर शासन चलाया। लेकिन 1990 के दशक के आते-आते वह पतन की स्थिति में पहुंच गई। पार्टी को चलाने के लिए सक्षम नेतृत्व के अभाव की समस्या से वह ग्रसित है। हमने ऊपर देखा है कि इस स्थिति से उबरने की कवायद के तहत ही उसकी अगुवाई में यूपीए का आविर्भाव हुआ है। केन्द्र में यह स्थिति है जबकि अधिकांश प्रदेशों में अभी भी कांग्रेस ही सत्तारूढ़ है। लेकिन केन्द्र में भी या प्रदेशों में भी जब वह सत्तारूढ़ थी तब लोगों की जिन्दगी में कोई बदलाव नहीं आया। दिन-ब-दिन जनता की जिन्दगी बद से बदतर होने, देश के कर्जों में डूब जाने, जनता के गरीबी, अशिक्षा और भुखमरी से पीड़ित होने के लिए वही नीतियां जिम्मेदार हैं जो वह शुरू से लागू करते आ रही थी। इन्हीं नीतियों के अमल में तेजी लाकर राजग ने स्थिति को और भी बिगाड़ा था। अब कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए के सत्तारूढ़ होने के बाद से एक माह के दौरान उसने जो-जो निर्णय लिए उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह अपने अतीत से अलग कुछ भी नहीं करने जा रहा है। पोटा के स्थान पर यूपीए दूसरा कानून लाने की बात कर रहा है। पेट्रोल, डीजिल, रसोई गैस आदि की कीमतों को उसने बढ़ा ही दिया है। कोल इंडिया में 80 हजार मजदूरों को, एसईसीएल में 10 हजार मजदूरों को तथा बीसीसीएल में हजारों मजदूरों को काम से निकालने की योजनाएं तैयार हो रही हैं। संशोधनवादियों की राजनीति पर यकीन करने वाले लोग यह मान रहे हैं कि इस सरकार के जनोन्मुखी नीतियां अपनाने के आसार ज्यादा हैं क्योंकि इसे संशोधनवादियों का समर्थन हासिल है। लेकिन अगर वे केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में दशकों से संशोधनवादियों के द्वारा जारी जन विरोधी नीतियों को देखेंगे तो सचाई को समझ सकेंगे। वे यह भी समझ सकेंगे कि बुर्जुवाई और संशोधनवादी पार्टियों में बुनियादी मुद्दों पर सहमति है और इसीलिए वे गठबन्धन बना रही हैं। यह भी याद रखना होगा कि जनता को धोखा देने में संशोधनवादी काफी चतुराई बरतते हैं।

राजग का नेतृत्व करने वाली भाजपा अब अपनी पराजय के कारणों का पता लगाने में माथापच्ची कर रही है। लम्बे अरसे से उसके अन्दर जारी अन्दरूनी झगड़े अब खुलकर सामने आ रहे हैं। अब यह झगड़ा भाजपा के अन्दर उदारवादियों और कट्टरवादियों के बीच टकराव के रूप में सामने आ रहा है। अब तक ये सारे झगड़े सत्ता के परदे के पीछे रहे थे। संघ परिवार से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच द्वारा राजग की आर्थिक नीतियों की आलोचना, विश्व हिन्दू परिषद के प्रमुख अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया द्वारा राम मन्दिर के मामले में वाजपेयी की निंदा, पाकिस्तान के साथ दोस्ती के मुद्दे पर शिवसैनिकों द्वारा विरोध का परचम बुलन्द किया जाना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा वाजपेयी सरकार की नीतियों को लेकर समय-समय पर चुटकी लेते रहना – इन सभी की पराकाष्ठा के तौर पर अब ये झगड़े खुलकर सामने आ गए। 20 जून से मुम्बई में

होने जा रही भाजपा के कार्यकारिणी की बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। गुजरात नरमेध और नरहंतक नरेन्द्र मोदी सहज ही चर्चा के केन्द्र में आ गए। चुनावों के नतीजे निकलने के बाद आरएसएस प्रवक्ता राम माधव ने कहा कि "संघ के मूल सिद्धांतों से भटक जाने के कारण ही भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा।" संघ परिवार से जुड़े लगभग सारे संगठन इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हुए बयान जारी कर रहे हैं। आडवाणी ने साफ तौर पर कहा कि अयोध्या और हिन्दुत्व को त्यागने के कारण ही यह पराजय हुई है। इनके बयानों से यह स्पष्ट होता है कि अब वे देश में बड़े पैमाने पर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिशें करने वाले हैं। इनके प्रति भारतवासियों को सचेत रहना होगा। वे यह भी कह रहे हैं कि वे विपक्ष में पांच साल तक बैठ नहीं सकते। इससे यह समझ में आता है कि वे फिर से सत्ता में आने के लिए कमीनेपन की किसी भी हद तक जा सकते हैं। मूल समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने में माहिर भाजपा नेता अब पोटा को जारी रखने और दागी मंत्रियों की बरखास्तगी मांग से आन्दोलन करने जा रहे हैं ताकि जनता को यूपीए की जन विरोधी नीतियों और फैसलों के खिलाफ लड़ने से रोका जा सके। वे अब हिन्दुत्व और अयोध्या मुद्दों को सामने लाने की बात कर रहे हैं। इनके छलपूर्ण प्रचार और जन विरोधी आन्दोलनों का पर्दाफाश करना चाहिए और इनके खतरे के खिलाफ जनता को संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए।

14वीं लोकसभा के चुनावों के साथ आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और सिक्किम राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी सम्पन्न हुए। उड़ीसा को छोड़ बाकी तीन राज्यों में नतीजे वहां की सत्तारूढ़ पक्ष के खिलाफ आए। खासतौर पर आन्ध्रप्रदेश में पिछले नौ सालों से सत्ता पर रही तेलुगुदेशम पार्टी का लगभग सफाया हो चुका है। 'साइबर जार' कहलाने वाले चन्द्रबाबू ने आस्ट्रेलिया की माकिनसे एण्ड कम्पनी के सुझाव पर ढेर सारे कर्ज लाकर दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर 'विजन-2020', 'स्वर्णान्ध्रप्रदेश', आदि का ढिंढ़ोरा पीट-पीटकर प्रचार किया था। विश्व बैंक के सुधारों के एजेन्डे से उसके नमकहलाल सेवक की तरह काम किया। आन्ध्रप्रदेश का वह सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) कहलाता रहा। सूचना प्रौद्योगिकी को

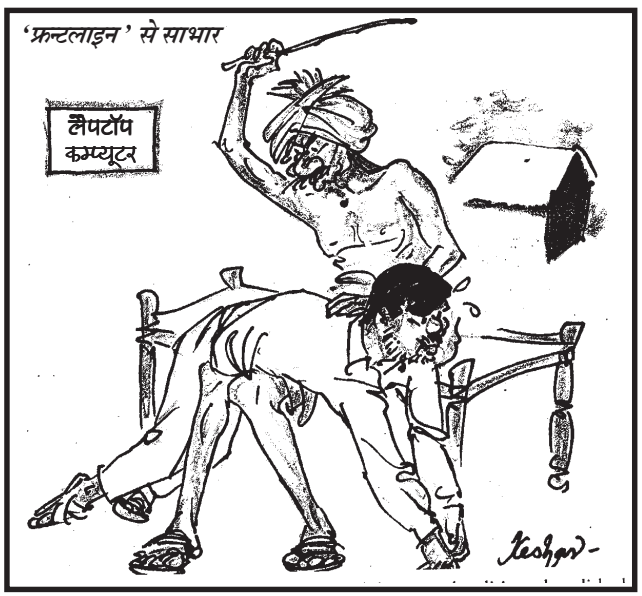

बढ़ाने में ध्यान देकर वह राज्य की जनता की समस्याओं को हल करने में बुरी तरह विफल हुआ जिससे सभी तबकों की जनता उसका विरोध करने लगी थी। किसानों की आत्महत्याओं के मामले में आन्ध्रप्रदेश सबसे पहले स्थान पर रहा। फसलें चौपट होने से और कर्ज के बोझ से दबकर 3 हजार किसानों ने आत्महत्या की। लेकिन पंचायतराज विभाग मंत्री नागम जनार्धनरेड्डी ने इस पर प्रतिक्रिया वक्त करते हुए कहा कि परिवारों को सरकार से मिलने वाले मुआवजे (भीख) के लालच में किसान इस तरह आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के प्रति सरकार के अड़ियल और उपेक्षापूर्ण रवैए का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं के पास गिरवी रखकर कर्ज लाकर सिंगापुर, मलेशिया और चीन की तर्ज पर राज्य का विकास करने का दावा करते हुए जनता का शोषण करने वाले और आन्ध्रप्रदेश को जन आन्दोलनों के दमन की प्रयोगशाला में तब्दील करने वाले चन्द्रबाबू पर भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] की अगुवाई में पीजीए की एक टीम ने एक जबर्दस्त हमला किया था, लेकिन उसमें वह बाल-बाल बच गया था। इससे बौखलाए चन्द्रबाबू ने नक्सलवादियों पर रेफरेन्डम बताते हुए समय से पहले चुनाव का बिगुल बजाया। लेकिन जनता ने नक्सलवादियों का पक्ष लेते हुए तेलुगुदेशम को हरा दिया।

सभी तबकों की जनता में बढ़ चुके असन्तोष का फायदा उठाकर कांग्रेस ने केन्द्र की तरह राज्य में भी गठबन्धन बनाकर दो तिहाई से ज्यादा बहुमत से चुनाव जीता। एक दशक तक सत्ता से दूर रही कांग्रेस ने चुनाव के पहले लोगों से कई वायदे किए। इसलिए जनता को मांग करनी चाहिए कि वह अपने किए वायदों को पूरा करे। उसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दृढ़ता से लड़ना चाहिए। कांग्रेस की पुरानी नीतियों से परिचित आन्ध्रप्रदेश की जनता को उसके लोकलुभावन नारों और वायदों से धोखा नहीं खाना चाहिए। कांग्रेस से गठबन्धन करने वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति सम्भवतः भौगोलिक रूप से एक अलग राज्य हासिल करे, पर खून बहा रहे तेलंगाना के साथ वह कोई इन्साफ नहीं कर सकती। देश के किसान संघर्षों के लिए प्रेरणा स्रोत बने तेलंगाना और आन्ध्र की जनता को जनयुद्ध की दिशा में ही अपनी समस्याओं को हल करना चाहिए।

जनता के जनयुद्ध की राह पर अपनी समस्याओं को हल करने का सिलसिला देश भर में दिनोंदिन बढ़ रहा है। देश के अधिकांश राज्यों में जनयुद्ध मजबूती से आगे बढ़ रहा है और उसका फैलाव हो रहा है। जहां तक जनयुद्ध का विस्तार हो रहा है वहां तक चुनाव बहिष्कार का नारा जनता को जागरूक बना रहा है। कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता अपनी राष्ट्रीय मांगों को उठाते हुए चुनावी नौटंकी का लगातार बहिष्कार करती आ रही है। दूसरी तरफ, मतदान प्रतिशत के घटते आंकड़े यह दर्शा रहे हैं कि इन लुटेरे वर्गों के प्रति और उनके फर्जी चुनावों के प्रति देशवासियों का विश्वास कम होता जा रहा है। मतदान में 35-40 प्रतिशत से ज्यादा मतदाता भाग नहीं ले रहे हैं। कई जगहों पर जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुनाव बहिष्कार को संघर्ष के एक स्वरूप के बतौर इस्तेमाल कर रही है। ऐसी स्थिति में फर्जी मतदान, मतदान केन्द्रों का कब्जा और अन्य धांधलियों के सहारे मतदान प्रतिशत बढ़ाना शासक वर्गों का रिवाज सा बन गया है। मीडिया की खबरों से यह स्पष्ट होता है कि इस बार चुनावों में हिंसा कितना व्यपक स्तर पर हुई है। आन्ध्रप्रदेश में चुनावी

पार्टियों ने अभूतपूर्व पैमाने पर हिंसा मचाई। कश्मीर में आतंकवादियों के नाम पर खुद चुनावी पार्टियों की गुण्डावाहिनियों ने पुलिस कैम्पों पर गोलीबारी करके मतदान केन्द्रों पर कब्जा किया, यह बात अखबारों ने लिखी है। इस तरह देश भर में देखें तो यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि चुनावों की प्रक्रिया फर्जी और गैर-जनवादी थी। आम मतदाताओं में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं देखी गई। दूसरी तरफ उनकी समस्याएं दिन-प्रतिदिन उन्हें जुझारू संघर्षों की तरफ बढ़ा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें कृषि क्रान्ति की राजनीति से जागरूक बनाने का कर्तव्य क्रान्तिकारी पार्टियों पर ही है। लोगों को यह अवगत कराना चाहिए कि दीर्घकालिक जनयुद्ध की दिशा असली विकल्प है। देशवासियों को यह समझाना चाहिए कि जैसा कि आन्ध्र, बिहार, झारखण्ड, बालाघाट-गोंदिया और दण्डकारण्य की जनता क्रान्तिकारी जन कमेटियों का चुनाव करके ग्राम स्तर पर अपनी सरकार चला रही है, उसी को नमूने के तौर पर लेकर संघर्ष करना चहिए। आज की सभी संसदीय पार्टियां सामन्ती, बड़े पूंजीवादी और साम्राज्यवादी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी लूट-खसोट के लिए रास्ता साफ कर रही हैं। इसलिए इन तीनों ताकतों को उखाड़ फेंकने से ही जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हो सकता है।

आइए, अब 14वीं लोकसभा चुनावों के मौके पर दण्डकारण्य की जनता के अनुभव पर रोशनी डाली जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के मौके पर चलाया गया पुलिसिया दमन से जनता अभी उबर ही नहीं पाए कि उस पर लोकसभा चुनाव टूट पड़े। जनता को आतंकित करने में बदनाम पंजाब कमाण्डो बलों को इस बार दण्डकारण्य में उतारा गया। सीमा सुरक्षा बल उतारे गए। आसमान में मशीनगनों से लैस तीन दर्जन हेलिकाप्टर चक्कर लगाते रहे। विधानसभा चुनावों के मुकाबले कई गुना ज्यादा दमन इस बार चलाया गया। दण्डकारण्य में चुनाव बहिष्कार को विफल करने की मंशा से पुलिस बलों ने इसे जंगे मैदान में तब्दील किया। 28 फरवरी से 25 अप्रैल तक (यहां 20 अप्रैल तक मतदान और 23 अप्रैल तक पुनरमतदान समाप्त हुआ) कुल 112 मुठभेड़ें हुई हैं, ऐसा पुलिस खुद कह रही है। इससे यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण रही होगी। (विधानसभा चुनावों के मौके पर 33 मुठभेड़ें हुई थीं)। इस बार गोलीबारियों में चार पुलिस वाले मारे गए और 18 घायल हुए। (जबकि विधानसभा चुनावों के मौके पर हुई गोलीबारियों में 12 पुलिस वाले मारे गए और चार घायल हुए थे)। इस बार पुलिस ने चुनावों के मौके पर चार कथित इनामी संगठन नेताओं और अन्य 320 आम सदस्यों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, केन्द्रीय बलों ने आते ही जनता में आतंक का तांडव मचाना शुरू किया। इन्द्रावती एरिया में उन्होंने धर्मा गांव की दो शादीशुदा महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसके बाद इनमें से बुधरी नामक युवती की हत्या करके बाद में मुठभेड़ में महिला नक्सली के मारे जाने की घोषणा की। पल्ली गांव के एक निरीह किसान चैतू को पुलिस ने पीट-पीटकर मार डाला। दक्षिण बस्तर डिवीजन में संतोष नामक एक छात्र संगठक को पुलिस ने झूठी मुठभेड़ में मार डाला। इस प्रकार पुलिस व अर्ध सैनिक बलों ने तीन लोगों की हत्या की। सभी तबकों के लोगों को इनके जुल्म और अत्याचारों का शिकार होना पड़ा। महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, कर्मचारी, छात्र, व्यापारी, ठेकेदार आदि सभी लोगों को दमन की कहर झेलनी पड़ी। सरकार ने एक तरफ पुलिसिया दमन को बड़े पैमाने पर चलाते हुए ही दूसरी तरफ क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान भी जारी रखा। मीडिया के जरिए यह प्रचार करवाया गया कि नक्सली जनता को वोट नहीं डालने की धमकियां दे रहे हैं और गांव खाली करवा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने ग्राम सुरक्षा समितियों को भी सक्रिय किया जिनका उसने पहले से गठन कर रखा है। इन लोगों ने कुछ जगहों पर पार्टी और पीजीए के कार्यकर्ताओं की हत्या करने की कोशिश भी की। इस तरह दण्डकारण्य भर में सरकार का चौतरफा हमला चला था। इसके बावजूद जनता ने चुनावों का बहिष्कार किया।

14वीं लोकसभा चुनावों के एक माह पहले से ही सभी डिवीजनों में जन संगठन कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, पीजीए सैनिकों और जनताना सरकारों (क्रान्तिकारी जन कमेटियों) ने चुनाव के बहिष्कार का प्रचार किया। पर्चे और पुस्तिकाओं को लोगों में बड़े पैमाने पर बांटे गए। पोस्टर चस्पा कर दिए गए। बैनर बांधे गए। गांवों और जंगलों में चुनाव बहिष्कार का नारा गूंजता रहा। कई सभाओं और बैठकों का आयोजन हुआ। इस बार 'चेतना नाट्य मंच' द्वारा जारी विशेष ऑडियो कैसेटों, गीतों और अन्य कला विधाओं ने जनता को बेहद आकर्षित किया। जन मिलिशिया समेत पीजीए के प्रधान व माध्यमिक बलों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनता की रक्षा में खड़े होकर चुनाव बहिष्कार को सफल बनाया। प्रचार के लिए संसदीय पार्टियों को गांवों में कदम रखने से पूरी तरह रोक दिया। 98 जगहों पर बारूदी सुरंगें विस्फोट करके हत्यारे पुलिस बलों को सबक सिखाया और जनता का ढाढ़स बंधाया। उनसे कुछ हथियार भी छीन लिए। 22 इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों को भी जब्त कर लिया। व्यापक पुलिस बंदोबस्त से मतदान केन्द्र खोलकर मतदान कर्मियों को हेलिकाप्टरों में भेजने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं रहा। इससे कई जगहों पर पुलिस बलों ने ही बटन दबा-दबाकर मतदान किया। इनके बन्दोबस्त में आए पुलिस वालों ने चलते समय बेकसूर आदिवासियों को हाथ पीछे से बांधकर अपने सामने रखकर मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। इसके बावजूद इनकी कोशिश पिट गई। कई गांवों में जनता ने यह ऐलान करते हुए कि "हमारे वोटों से अपनी सरकार का चुनाव करेंगे न कि तुम्हारी" चुनावों का बहिष्कार किया। अकेले डौला इलाके में 80 गांवों के लोगों ने मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, जिससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि पूरे दण्डकारण्य में कितने सैकड़ों गांवों ने चुनावों का बहिष्कार किया होगा।

सड़कों के किनारे वाले गांवों में तथा शहरों में 35 प्रतिशत मतदान बताया गया। यह बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि अगर पुलिसिया दमन न होता तो यहां पर 5 प्रतिशत भी मतदान न हुआ होता। फिलहाल ग्रामीण इलाकों में यही हुआ। चुनाव बहिष्कार के आह्वान को दृढतापूर्वक सफल बनाने वाली क्रान्तिकारी जनता को पार्टी की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी लाल अभिनन्दन करती है। कमेटी आशा करती है कि दण्डकारण्य की लड़ाकू जनता अपने-अपने गांवों में जनताना सरकार का गठन करते हुए अपने बहादुराना संघर्षों के जरिए दण्डकारण्य को आधार इलाके में तब्दील करेगी और खुद को भारत की जनता के सामने एक आदर्शवान मिसाल के तौर पर पेश करेगी। ★

प्रेस वक्तव्य

लोकसभा चुनावों के दौरान दण्डकारण्य की जनता पर पुलिस एवं अर्ध सैनिक बलों द्वारा अमल किए गए भारी दमन की निंदा करो !

दिनांक : 01-05-2004

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्सवार] की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी हाल के लोकसभा चुनावों के दौरान दण्डकारण्य की जनता पर छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र की सरकारों के पुलिस बलों के अलावा अर्ध सैनिक बलों द्वारा अमल किए गए भारी दमन की तीव्र भर्त्सना करती है। "शान्तिपूर्ण" ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के नाम पर सीआरपीएफ, बीएसएफ एवं पंजाब कमाण्डो फोर्स के बलों को हजारों की संख्या में तैनात करके जनता को आतंकित किया गया था। बच्चों, बूढ़ों एवं महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों को बेरहमी से पीटा गया। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में बन्द किया गया। घरों को ध्वस्त किया गया एवं लोगों को पीट-पीटकर मार डाला गया। दण्डकारण्य के उत्तर बस्तर, माड़, पश्चिम बस्तर, दक्षिण बस्तर एवं गड़चिरोली इलाकों की जनता पर अमानवीय अत्याचार करने वाले अर्ध सैनिक बलों की घिनौनी कार्यवाहियों का विरोध करने एवं संघर्ष इलाकों की जनता के जनवादी अधिकारों का समर्थन करने की हमारी पार्टी तमाम जनवादी ताकतों से अपील करती है।

ढोंगी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने के हमारे पार्टी के आह्वान के मुताबिक दण्डकारण्य की जनता ने वोटबाज नेताओं एवं पार्टियों को संघर्ष इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए घुसने नहीं दिया। पिछले विधानसभा चुनावों में जनता के द्वारा बड़े पैमाने पर चुनावों का बहिष्कार किया गया था। लोकसभा चुनावों के बहिष्कार के हमारे आह्वान को असफल बनाने के लिए केन्द्र के द्वारा हजारों की संख्या में अर्ध सैनिक बल तैनात करके फासीवादी दमन चलाया गया एवं लोगों के चुनाव बहिष्कार करने के जनवादी अधिकार को कुचलने का प्रयास किया गया।

स्थानीय पुलिस की मदद से सीआरपीएफ, बीएसएफ एवं पंजाब कमाण्डो बलों ने गांवों पर हमले करके, रास्तों में छिपकर आने-जाने वालों पर हमले करके सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके बुरी तरह पीटा और कइयों को जेलों में ठूंस दिया। माड़ क्षेत्र में 76, उत्तर बस्तर में 43, दक्षिण बस्तर में 6, पश्चिम बस्तर में 30 एवं गड़चिरोली में 296 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

गांवों में फ्लैग मार्च करते हुए घरों में घुसकर सामानों को नष्ट किया गया और घरों को ध्वस्त किया गया। कीमती सामानों को, रुपए-पैसों को, मुरगी-बकरियों को उठाकर ले जाया गया। माड़ के कोह्कामेट्टा में 2, सोनपुर में 30, कुंदला में 2, कीहकाड में 1 कुल 35 घरों में तोड़फोड़ किया गया। एवं सामान फेंका गया। कोह्कामेट्टा आश्रम के दरवाजे तोड़ दिए एवं छात्र-छात्राओं के सामान नष्ट किए। माड़ में 7 साल के बच्चे से लेकर बूढ़ों तक 85 लोगों को पीट-पीट कर अधमरा किया गया। कोह्कामेट्टा गांव के आश्रम को पायखाने में तब्दील किया गया।

मतदान सामग्रि को लाते-ले जाते वक्त जबरन बच्चों और महिलाओं को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया। इनमें से कइयों को अभी तक नहीं छोड़ा गया। मतदान के दिन गांवों में घूम-घूम कर जो भी नजर आया पीटते गए। वोट नहीं डालने पर मार डालने की धमकी दी गई और पीटा गया। पुलिस बलों की दहशतगर्दी से लोग घरों और गांवों को छोड़कर जंगल की तरफ तथा दूर-दराज के गांवों की ओर पलायन कर गए। इस सचाई पर परदा डालकर सरकार ने हमारी पार्टी पर झूठा आरोप लगाया है कि हमने गांवों को खाली कराया और हमारे डर से लोगों ने गांव छोड़ दिए। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बहाने पुलिस एवं अर्ध सैनिक बलों ने संघर्ष इलाकों में गश्त अभियानों के दौरान रास्तों में आते-जाते अपने डेरों से गांवों और घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की एवं गोलाबारी की जिससे घरों की छतों, दीवारों को ही नहीं, बल्कि खेत-खलिहानों को भी नुकसान पहुंचा। खेतों में आग लगने से फसलें जलकर राख हो गईं।

सीआरपीएफ बलों ने माड़ के इन्द्रावती इलाके में अपने वहशीपन को उजागर करते हुए तीन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया एवं एक को गोली मार दी। कोह्कामेट्टा की एक महिला के साथ तब सामूहिक बलात्कार किया गया जब वह पेशाब करने रात में अपने घर से बाहर आई थी। बड़े पल्ली गांव पर हमला करके दो महिलाओं को गिरफ्तार करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। एक महिला पुलिस के चुंगल से भाग निकलने में कामयाब हुई जबकि दूसरी महिला बुधरी को गोली मारकर यह घोषणा की कि एक महिला नक्सली मुठभेड़ में मारी गई। लाश को पुलिस ने दफना दिया। बुधरी के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या के खिलाफ भैरमगढ़ में आवाज उठाने वाले हजारों ग्रामीणों को डरा-धमकाकर, फायरिंग का आतंक दिखाकर खदेड़ दिया गया। ढोंढरीवेडा की 20 साल की युवती को सीआरपीएफ बलों ने उठा लिया जिसका अभी तक अता-पता नहीं है। आदेर निवासी टोक्काल को जानवर की तरह पीट-पीटकर अधमरा करके पुलिस अपने साथ ले गई जिसे अभी तक नहीं छोड़ा गया।

भैरमगढ़ के छोटे पल्लि के चैतू कोपाल, मंगडू एवं बुधराम को गिरफ्तार करके अमानवीय यातनाएं दी गईं। चैतू को पीट-पीटकर मार डाला गया एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दबाकर उलटी-दस्त से चैतू की मौत होने की खबर फैलाई गई। चैतू की लाश को पुलिस ने ही जला दिया। 5,000 ग्रामीणों ने भैरमगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया एवं

लाश की मांग की। बाकी दोनों ग्रामीणों को फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया।

अर्ध सैनिक बलों ने आम जनता पर ही नहीं बल्कि व्यापारियों पर भी कहर बरपाया। हाटबाजारों पर हमले करके व्यापारियों को पीटा गया एवं दुकानों में तोड़फोड़ की गई। नारायणपुर शहर में भी दुकानदारों को मारा-पीटा गया। पुलिस जुल्म की खबर छापने के कारण नारायणपुर के पत्रकार (दैनिक भास्कर) शीतल प्रकाश के कार्यालय पर हमला किया गया एवं तोड़फोड़ की गई। इसकी हमारी पार्टी कड़ी निंदा करती है। चुनावों के दौरान एसपी के आदेश से माड़ के ऊपर पत्र-पत्रिकाओं को पहुंचाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया। हमारी पार्टी दैनिक समाचार पत्रों के मालिकों एवं सम्पादकों से अपील करती है कि वे इस तानाशाही फरमान का विरोध करें एवं प्रेस की आजादी के लिए आवाज उठाएं। पुलिस बलों के भारी दमन, दबाव एवं आतंक के बावजूद दण्डकारण्य की जनता ने बड़े पैमाने पर मतदान का बहिष्कार किया। जन विरोध के चलते दसियों मतदान केन्द्रों तक मतदान दल पहुंच भी नहीं सका। मिसाल के तौर पर बस्तर जिले के आदेर, मुरुमवेडा, गट्टाकाल, जाटलूर, डुंगा, कुम्मम, कच्चापाल, वाडापेन्दा, गुम्मरका, गोमांगाल, कल्लाजा, पल्ली और पोल्लेवाया मतदान केन्द्रों में कोई नहीं पहुंचा। जहां कहीं पहुंचे भी तो वहां लोगों ने वोट नहीं डाला। लेकिन पुलिस बलों के द्वारा रिग्गिंग के जरिए मतदान के प्रतिशत बढ़ा दिया गया।

हमारी पार्टी पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पीयूसीएल के कार्यकर्ताओं, जनवाद के प्रेमियों एवं बुद्धिजीवियों से अपील करती है कि वे दण्डकारण्य के संघर्ष इलाकों का दौरा करें, सचाई को सामने लाएं। चुनाव के दौरान पुलिस एवं अर्ध सैनिक बलों द्वारा अमल किए गए अमानवीय अत्याचारों, जुल्म एवं दमन का पर्दाफाश करें। सरकार की जन विरोधी एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ में आवाज उठाएं। संघर्ष इलाकों की जनता के जनवादी अधिकारों के समर्थन में उठ खड़े होवें और जेलों में बन्द तमाम लोगों की निशर्त रिहाई की मांग करें। सरकार से यह सवाल करें कि बस्तर जिले में किस देश का बार्डर है कि केन्द्र सरकार ने बीएसएफ को तैनात किया। दण्डकारण्य से अतिरिक्त बलों को तुरन्त हटाने की मांग करें।

(कोसा)

सचिव,

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार]

बिहार में नक्सली बन्दियों पर पाशविक हमला

2 मार्च 2004 की सुबह। बन्दियों से मुलाकात का समय। विशेष बेऊर जेल। जेल में बन्द सगे-सम्बन्धियों से मुलाकात करने आए लोग जेल परिसर में खड़े इधर-उधर घूम रहे थे। इतने में जेल के अंदर घंटी बजी। सोची-समझी साजिश के तहत बाहर से बिहार मिलिटरी पुलिस की मदद से जेल अधिकारी बंदियों पर लाठियां लेकर पिल पड़े। इस पाशविक लाठीचार्ज के खास शिकार थे बन्दी संघर्ष मंच के नेता, जो जेल अधिकारियों के द्वारा मुलाकातियों से वसूली का विरोध कर रहे थे। जेल पुलिस के इस क्रूर हमले में तीन दर्जन कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए जिनमें से अधिकांश पीपुल्सवार, एमसीसीआई और सीपीएन (माओवादी) से सम्बद्ध हैं। इस लाठीचार्ज में कइयों के हाथ-पैर टूटे और कइयों के सिर फूटे। गंभीर रूप से घायलों को बन्दी संघर्ष मंच के अध्यक्ष एवं पीपुल्सवार के नेता कॉमरेड रवि कुमार, पीपुल्सवार की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य अरविंद कुमार और नेपाल के माओवादी नेता देवनाथ प्रसाद यादव, रोशन कुमार यादव, विनोद थापा आदि शामिल हैं।

जेल अधिकारियों की घूसखोरी तथा जेल की बदतर परिस्थितियों के खिलाफ बन्दी संघर्ष मंच के द्वारा जारी संघर्ष का ही परिणाम था, बन्दियों पर हमले की कार्रवाई। बन्दियों का संघर्ष जेल मंत्री पासवान भगत का यह आश्वासन कि कैदियों की मांगें पूरी की जाएंगी, के बाद ही समाप्त हुआ। साथ ही कुछ सुधारों को भी लागू किया गया। इससे जेल अधिकारी आग-बबूला हो गए और बदला लेने के लिए 2 मार्च की कार्रवाई की साजिश रची। बन्दी संघर्ष मंच ने माओवादी नेताओं को खासतौर पर निशाना बनाने के पीछे यही कारण है।

तब से घायलों को न केवल चिकित्सा सुविधा से वंचित किया गया, बल्कि उन्हें एक-दूसरे से दूर रखने अलग-अलग बैरकों में रखा गया। सगे-संबंधियों से मुलाकातें बंद कर दी गईं। लाठीचार्ज के खिलाफ जेल के अंदर बुद्ध की मूर्ति के सामने रोज धरना जारी है। 3 मार्च के धरना में 300 लोगों ने भाग लिया, जबकि 4 मार्च को धरना में भाग लेने वालों की संख्या 450 तक पहुंच गई। यह धरना आन्दोलन बन्दी संघर्ष मंच के बैनर तले आयोजित था और कॉ. अरविंद, कॉ. रवि तथा अन्य कॉमरेडों ने धरना में शामिल लोगों को सम्बोधित किया। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक जारी धरना में उपस्थित लोगों ने खासतौर पर मुख्य जेलर प्रदीप कुमार झा एवं कैदियों पर हमले में शामिल जेलरों पर कार्यवाही की मांग की। उन्होंने घायल कैदियों की उचित चिकित्सा सुविधा की मांग के अलावा अपनी पुरानी मांगों को भी दोहराया। मांगें पूरी होने तक धरना जारी रखने का उन्होंने संकल्प लिया। 4 मार्च को जब पी.के. झा जेल निरीक्षण के लिए गया तब पीपुल्सवार के समर्थकों ने गगनभेदी नारों के साथ उसका घेराव कर दिया। कई घंटों बाद ही वह भागने में कामयाब हो सका। इस बीच में जेल आन्दोलन जेल के अन्दर से पटना की सड़कों तक फैल गया। 5 मार्च को 500 से ज्यादा लोगों ने अखिल भारतीय जन प्रतिरोध मंच, जन प्रतिरोध संघर्ष मंच एवं छात्र संगठन डीएसयू के नेतृत्व में जाक्सन चौक से जिला मुख्यालय तक जुलूस निकाला। यह समाचार लिखे जाने तक जेल के अन्दर एवं बाहर संघर्ष जारी है। ★

दक्षिण एशिया के माओवादी पार्टियों एवं संगठनों की समन्वय समिति (CCOMPOSA) का तीसरा सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न

दक्षिण एशिया के माओवादी पार्टियों एवं संगठनों की समन्वय समिति का तीसरा सम्मेलन 16 से 18 मार्च, 2004 के बीच सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में, भागीदार संगठनों में से सात तथा दो पर्यवेक्षकों ने शिरकत की। सम्बन्धित देशों में जनयुद्ध को तेज करने एवं विकसित करने के संकल्प के साथ सम्मेलन समाप्त हुआ।

यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था, जब नेपाल में जनयुद्ध अपने रणनीतिक प्रत्याक्रमण की तैयारी कर रहा है और 80 प्रतिशत भूभाग पर माओवादियों के नियंत्रण से एक नई दुनिया जन्म ले रही है। यह ऐसे समय में हो रहा था, जब भारत में जनयुद्ध तेजी से आगे बढ़ रहा है, दो बड़ी माओवादी पार्टियां एमसीसीआई और भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] महान एकता की ओर अग्रसर हैं। यह और ऐसे समय में हो रहा था, जब बंगलादेश में माओवादी पार्टियां अपने जनयुद्ध को नए इलाकों में विस्तारित कर रही हैं और भूटान में एक माओवादी पार्टी का गठन हुआ है।

सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य संगठन हैं : पीबीएसपी (सीसी) (बंगलादेश); सीपीईबी (एमएल) (लाल तारा) (बंगलादेश); एमसीसीआई (भारत); भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] (भारत); भाकपा (मा-ले) (नक्सलबाड़ी) (भारत); आरसीसीआई (एमएलएम) (भारत); सीपीएन (एम) (नेपाल)। तकनीकी कारणों के चलते बंगलादेश की दो पार्टियां एवं श्रीलंका की एक पार्टी सम्मेलन में हाजिर नहीं हो सकीं। पीबीएसबी (एमबीआरएम) (बंगलादेश) तथा भूटान की नवगठित भूटान कम्युनिस्ट पार्टी (एमएलएम) ने पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय गीत एवं अगस्त 2002 में आयोजित प्रथम सम्मेलन से लेकर अब तक जनयुद्ध में जान कुरबान करने वाले तमाम शहीदों को श्रद्धांजली के साथ सम्मेलन प्रारंभ हुआ।

नेपाल के जनयुद्ध में आखिरी दौर की बातचीत की समाप्ति के बाद से लेकर अब तक 1,500 से ज्यादा कॉमरेडों ने अपनी शहादत दी। इन शहीदों में रीजिनल ब्यूरो के सदस्य एवं बटालियन कमिस्सार कॉमरेड बिवेक और बटालियन कमाण्डर कॉमरेड प्रहार जैसे वरिष्ठ कॉमरेड शामिल थे। भारत में पिछले सम्मेलन के बाद पीपुल्सवार के 375 एवं एमसीसीआई के 134 कॉमरेड शहीद हुए। पीपुल्सवार ने राज्य कमेटी स्तर के 8 कॉमरेडों को खोया जिनमें कॉ. रामकृष्ण (वरंगल); कॉ. पद्मा (करीमनगर); कॉ. प्रसाद (अनन्तपुर); कॉ. अनपुरम कोमुरय्या (करीमनगर); कॉ. असीमदाज (मिडनापुर, पं. बंगाल), दो जिला कमेटियों के सचिव कॉ. ललिता (आदिलाबाद) और गंगन्ना (अनन्तपुर) शामिल हैं। सीपीआईबी (एमएल) (लाल तारा) ने एक जिला कमेटी सदस्य कॉ. नासिर सहित 15 कॉमरेडों को खोया। जबकि पीबीएसपी (एमबीआरएम) के चार कॉमरेडों ने अपनी जान की कुरबानी दी।

बैठक की शुरूआत में CCOMPOSA के संयोजक, नेपाल के कॉ. किशोर ने समिति की गतिविधियों की रपट पेश की। इसके बाद प्रतिनिधियों ने अपने-अपने देशों में जारी जनयुद्ध के विकास से संबन्धित या जनयुद्ध को तेज करने की तैयारियों से सम्बन्धित विस्तृत रपटें पेश कीं। आखिर में, दुनिया की वर्तमान परिस्थिति एवं दक्षिण एशियाई देशों की मौजूदा स्थिति पर सम्मेलन ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया।

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए सम्मेलन ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा आर्थिक संकट और गहराता जा रहा है जिसके फलस्वरूप दुनिया भर में साम्राज्यवाद, खासकर युद्ध पिपासू अमेरिका और आक्रामक हो गया है। इससे विश्वव्यापी प्रतिरोध लगातार बढ़ रहा है।

दक्षिण एशिया में भी साम्राज्यवाद, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद क्षेत्र के अलग-अलग देशों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अपने अधिकारियों को नेपाल भेजने के जरिए वहां सैनिक हस्तक्षेप, पाकिस्तान के सैनिक मामलों में गंभीर दखलंदाजी और भारतीय विस्तारवादियों के साथ रणनीतिक गठजोड़ आदि के द्वारा साम्राज्यवादी ताकतों ने अपना शिकंजा और मजबूत कर लिया है।

दक्षिण एशिया के देशों में आगे बढ़ते जनयुद्धों पर सम्बन्धित देशों की सरकारें पाशविक राजकीय दमन अमल कर रही हैं। नृशंस ज्ञानेन्द्र शासन अपने आतंकी हमलों में लोगों का कत्लेआम कर रहा है। भारतीय शासकों ने खतरनाक पोटा कानून को जनता पर थोप दिया। इसके तहत एमसीसीआई, पीपुल्सवार तथा अन्य संगठनों को प्रतिबन्धित किया। सैकड़ों फर्जी मुठभेड़ों को अंजाम दिया। 75 नेपाली माओवादियों को अवैध रूप से नेपाल सरकार को सौंपा। नेपाल के वरिष्ठ माओवादी नेताओं कॉ. किरण और कॉ. गौरव को जेल में बन्द किया है।

प्रस्ताव ने यह स्पष्ट किया कि साम्राज्यवाद, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके पिट्ठू भारतीय विस्तारवाद दक्षिण एशियाई जनता का सांझा दुश्मन है।

भारत एंव बंगलादेश के कुछ कॉमरेडों को दी गई मौत की सजा, कॉ. किरण एवं कॉ. गौरव को नजायज तरीके से गिरफ्तार करके जेल में बन्द करने, 75 से अधिक नेपाली माओवादी नेताओं तथा कैडरों की धरपकड़ एवं उन्हें नेपाल सरकार को सौम्पने एवं सम्बन्धित देशों में बढ़ते राजकीय दमन के खिलाफ नक्सलबाड़ी सप्ताह के दौरान समूचे दक्षिण एशिया में संयुक्त अभियान चलाने का सम्मेलन ने आह्वान किया।

आखिर में, राजनीतिक प्रस्ताव ने क्षेत्र की तमाम माओवादी ताकतों को मजबूती से एकजुट करने, संघर्षरत ताकतों के साथ जबर्दस्त एकता कायम करने और दक्षिण एशिया के सम्बन्धित देशों को विश्व क्रान्ति के मजबूत केन्द्रों में तब्दील करने का संकल्प लिया।

हस्ताक्षरित –

1) पीबीएसपी (सीसी) (बंगलादेश)
2) सीपीईबी (एमएल) (लाल तारा)
3) एमसीसीआई (भारत)
4) भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार]
5) भाकपा (मा-ले) (नक्सलबाड़ी)
6) आरसीसीआई (एमएलएम) (भारत)
7) सीपीएन (एम) (नेपाल)

सीपीएन (एम) का दस्तावेज

आइए, अन्तरविरोधों को सही ढंग से हल करते हुए हम समूची ताकतों को केन्द्रित करें ताकि (रणनीतिक) आक्रमण की तैयारियों को नई बुलन्दियों तक ले जाया जा सके !

["मौजूदा परिस्थिति और हमारा ऐतिहासिक कार्यभार" का अनुबन्ध प्रस्ताव जिसे अक्टूबर 2003 में सीपीएन (माओवादी) के अध्यक्ष कॉमरेड प्रचण्ड ने पेश किया और केन्द्रीय कमेटी के पोलिट ब्यूरो ने स्वीकृत किया।]

पोलिटब्यूरो की यह बैठक इस लिए बुलाई गई ताकि आने वाले दिनों के लिए नीति और योजना में आवश्यक सुधार किया जा सके। इसके लिए आमतौर पर केन्द्रीय कमेटी की पिछली प्लीनम के बाद, खासतौर पर युद्ध-विराम टूटने के बाद की राजनीतिक व सैन्य परिस्थिति का आम विश्लेषण किया जाए।

1. विश्व की परिस्थिति का विश्लेषण

विश्व की परिस्थिति के बारे में केन्द्रीय कमेटी (बैठक) के विश्लेषण और निष्कर्ष आज भी लागू होने वाले और सही हैं। इराक युद्ध के बाद अमेरिकी साम्राज्यवाद दिन-ब-दिन राजनीतिक तौर पर अलग-थलग पड़ता जा रहा है और फौजी तौर पर जबर्दस्त संकट में गले तक डूबता जा रहा है। इसकी पुष्टि हाल ही में सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र की आमसभा में तथा मैक्सिको के कानकुन शहर में सम्पन्न डब्ल्यूटीओ के विश्व सम्मेलन में सामने आए अन्तरविरोधों से ही नहीं, बल्कि इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य बलों के खिलाफ बढ़ रहे प्रतिरोध से तथा मध्य-पूर्व में शान्ति के लिए तथाकथित 'रोड मैप' के दिवालिएपन से भी हो रही है। इस संकट की पृष्ठभूमि में, दक्षिण एशिया पर पकड़ मजबूत बनाने की अमेरिका की रणनीति भी नई समस्याओं का सामना कर रही है। इस सन्दर्भ में, यह बात शानदार ढंग से साबित हो चुकी है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके टुकड़ों पर पल रही शाही फौजी तानाशाही के खिलाफ विचारधारात्मक, राजनीतिक और फौजी हमले केन्द्रित करने की हमारी नीति वास्तविक है। इस नीति की बुनियाद पर हमारे (पार्टी) केन्द्र की पहलकदमी की बदौलत न सिर्फ दुनिया भर के कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों और साम्राज्यवाद-विरोधी जन समुदायों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत और व्यापक हुए हैं, बल्कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ विभिन्न स्तरों पर अन्तरविरोध रखने वाली प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ कूटनीतिक रिश्ते भी व्यापक बन रहे हैं।

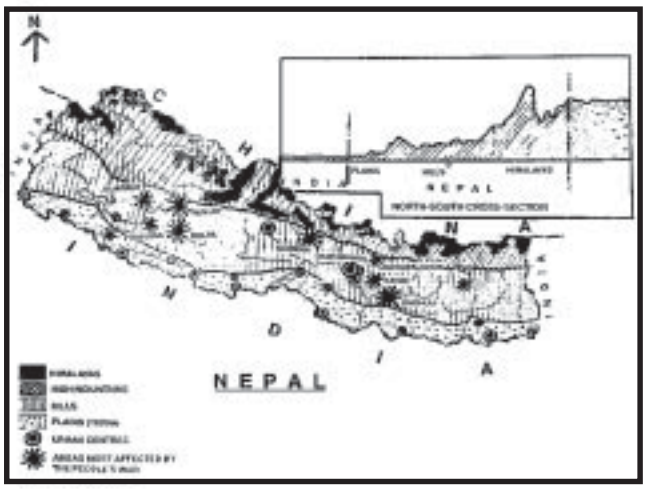

2. घरेलू राजनीतिक परिस्थिति की समीक्षा

एक संविधान-सभा के जरिए जनता को सम्प्रभु बनाने के लचीले कार्यनीतिक रवैये के चलते और इसके लिए बातचीत की पूरी प्रक्रिया के दौरान ली गई पहलकदमी के चलते पार्टी ने राजनीतिक तौर पर नई आक्रामक स्थिति हासिल की है। बातचीत के तीसरे दौर में पुरानी सरकार द्वारा पश्चगामी "धारणा पत्र" लाए जाने और उसी समय दोराम्बा में हुए कत्लेआम के बाद संघर्षविराम और बातचीत की प्रासंगिकता से खुद को अलग करते हुए की गई घोषणा से पार्टी की राजनीतिक महत्ता देश के अन्दर ही नहीं, बल्कि बाहर भी कायम हो चुकी है। इस समूची प्रक्रिया के दौरान रणनीतिक दृढ़ता और कार्यनीतिक लचीलापन को एक नई बुलन्दी से लागू करने में पार्टी कामयाब हुई है।

पुरानी सरकार, जोकि अब पश्चिमी साम्राज्यवाद, खासतौर पर अमेरिकी साम्राज्यवाद की कठपुतली बनी है, के राजनीतिक अस्तित्व का अब जनता के खिलाफ शाही सैन्य आतंक के रूप में पतन हो चुका है। पार्टी का यह विश्लेषण और निष्कर्ष कि शाहीमहल कत्लेआम के बाद पुरानी सरकार साम्राज्यवाद द्वारा निर्देशित सैन्य फासीवाद के रूप में पतन कर चुकी है, अब साफ तौर पर सही साबित हो चुका है। पुरानी सरकार में भागीदारी की मांग से गिड़गिड़ाने वाली संसदीय राजनीतिक पार्टियों को भी सरकार में शामिल करने में अनिच्छा से इस बात का भण्डाफोड़ हो गया है कि बहुदलीय लोकतंत्र के प्रति इन सामन्ती तत्वों की तथाकथित प्रतिबद्धता महज ढोंग है। पुरानी सरकार साम्राज्यवादी व सामन्ती जिद का नंगा प्रदर्शन करते हुए अब तथाकथित स्थानीय इकाइयों के लिए बेहद बेतुका नामांकन करने में लगी हुई है और संसदीय चुनावों के आयोजन के पक्ष में बकवास कर रही है। संसदीय राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व तक को मिटाने वाली पुरानी सरकार अपने सैन्य फासीवाद पर वैधता का परदा चढ़ाने की चतरतापूर्ण साजिशें रच रही है, यही इस प्रक्रिया में छुपा हुआ है। प्रमुख संसदीय पार्टियों की राजनीतिक निष्क्रियता उन्हें धीरे-धीरे खुद के अन्त की ओर ले जा रही है। ऐसे तत्त्वों का राजनीतिक अन्त होना बेहद सहज है जो 21वीं सदी की वर्तमान ठोस विश्व परिस्थिति में संवैधानिक राजशाही की असम्भवता और देश में गृहयुद्ध के विकास का अन्दाजा नहीं लगा सकते। यह समझने में कि नेपाल में बुर्जुवाई जनवादी

क्रान्ति को सफल बनाने के लिए सर्वहारा के नेतृत्व में लामबन्द होने या सामन्तवाद व साम्राज्यवाद गठबन्धन पर आधारित सैन्य फासीवाद के सामने घुटने टेक देने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, संसदीय ताकतों की असमर्थता उनकी नियति बन गई है। केन्द्रीय कमेटी की पिछली बैठक का यह निर्णय कि हालांकि यह दिखने में त्रिकोणीय लग सकता है, पर सार में और वर्गीय शब्दावली में देश में राजनीतिक संघर्ष दो-ध्रुवीय है, सही साबित हुआ है।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट है कि संसदीय समझौतापरस्ती का मध्य-मार्गी बताकर पर्दाफाश करते हुए तथा विशाल जन समुदायों और वर्गों के साथ एकजुट होते हुए सैन्य फासीवाद पर हमले केन्द्रित करने की पार्टी की नीति को दृढ़ता से जारी रखना जरूरी है।

3. युद्धविराम के टूटने के बाद सैन्य परिस्थिति की समीक्षा

रणनीतिक आक्रमण और आम बगावत की तैयारियों के तहत केन्द्रीय कमेटी की पिछली बैठक द्वारा तैयार की गई रणनीतिक योजना को लागू करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसलिए उसकी व्यापक समीक्षा तत्काल सम्भव नहीं है। फिर भी, चूंकि इस योजना के तहत शुरूआती चरण समाप्त हो चुका है, इसलिए इसका शुरूआती जायजा लेना और भविष्य के लिए योजना को बेहतर और ठोस बनाना मुमकिन भी है और जरूरी भी।

याद रहे कि केन्द्रीय कमेटी द्वारा तैयार की गई योजना का अहम बिन्दु यह था कि पहले चरण में विकेन्द्रीकृत कार्यवाहियां, दूसरे चरण में अपेक्षाकृत केन्द्रीकृत कार्यवाहियां और तीसरे चरण में बड़ी केन्द्रीकृत कार्यवाहियां की जाएं। पहले चरण में विकेन्द्रीकृत कार्यवाहियों के तहत जोर इस बात पर था कि ग्रामीण इलाकों में छोटे या बड़े ऐम्बुश तथा शहरों और मधेश (मैदानी इलाकों) में छोटी या बड़ी रेडें, कमाण्डो हमले और छोटी या बड़ी विध्वंसक कार्यवाहियां की जाएं ताकि दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सके और उसकी रफ्तार पर अंकुश लगाया जा सके।

नई पहलकदमी के पहले चरण के तौर पर तय की गई कार्यवाहियों के स्वरूपों और लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया, योजना का यह भाग पूरी तरह सफल रहा। विकेन्द्रीकृत पर देशभर में की गई विविध, तीव्र और वीरतापूर्ण कार्यवाहियों की शृंखला ने दुश्मन को दिग्भ्रमित और अव्यवस्थित करके उसे रक्षात्मक स्थिति में धकेल दिया। राजधानी, मधेश और छोटे व बड़े शहरों में किए गए सफल और बहादुराना कमाण्डो हमले, रेडें और विध्वंसकारी हमले नई पहलकदमी के सबसे महत्वपूर्ण व लाभकारी पहलू थे। इन तीव्र कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप, यह बात अच्छी तरह साबित हो गई है कि दुश्मन राजधानी, अन्य शहरों और तेराई (मैदानी इलाके) के ग्रामीण इलाकों में भी सुरक्षित नहीं है, जबकि पहाड़ों में तो (पुरानी सरकारी यंत्र का) सफाया ही हो चुका है। नई पहलकदमी का यह नतीजा बगावत के लिए जमीन तैयार करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धी है।

संख्या की दृष्टि से सड़कों पर बारूदीसुरंग विस्फोट और ऐम्बुश आशा के अनुरूप ही किए गए। हालांकि सेति-महांकाली इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों में कुछ आशान्वित गुणात्मक ऐम्बुश नहीं हो पाए। जहां तक अचानक हुई स्थाई भिड़ंतों का सवाल है, रोलपा के हांडिंग और कोर्चावांग में हुई मुठभेड़ें उल्लेखनीय हैं।

कुल मिलाकर देखा जाए तो, नई रणनीतिक योजना के तहत नई पहलकदमी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। चूंकि अतीत में हर नई योजना की शुरूआत में केन्द्रीकृत पद्धति में धक्का देने वाले बड़े हमले किए जाते थे और यहां तक कि दुश्मन और जनता भी इसके आदि हो चुके थे, इसलिए इस नई रणनीतिक योजना ने सभी को अचरज में डाल दिया। दुश्मन ने खुद को हुए भारी नुकसानों के बावजूद इस नई प्रक्रिया पर यह गलत प्रचार किया कि जन मुक्ति सेना (पीएलए) 'कमजोर' हो रही है और उसकी खुद की (शाही) सेना को 'सफलता' मिल रही है। दूसरी ओर, दुश्मन द्वारा जानबूझकर किए गए गलत प्रचार और हमारी योजना के सारतत्व के बारे में जानकारी के अभाव के परिणामस्वरूप जनता का एक तबका, खासतौर से शहरी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी कुछ गड़बड़ और आशंकाओं में पड़ गए जान पड़ता है। यहां तक कि कुछ क्रान्तिकारी काडर भी धक्का लगाने वाली बड़ी कार्यवाहियों के अभाव से नाराज हैं लगता है।

इस तरह के भ्रम और गड़बड़ जो भी रहें, हमें इस बारे में स्पष्टता होनी चाहिए कि युद्धविराम के टूटने के बाद समूचा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ, हमारी अपनी राजनीतिक पहलकदमी, दुश्मन की एक निश्चित किस्म की तैयारी और हमारे राष्ट्रव्यापी जवाबी आक्रमण के लिए अपनी तैयारियों की रणनीति – इन सभी को देखते हुए पहले चरण में विकेन्द्रीकृत कार्यवाहियां करने की हमारी नीति बिल्कुल सही और वस्तुगत थी। हमें यह स्पष्टता होनी चाहिए कि इन हालात में अगर हम पुरानी किस्म की कार्यवाहियां कर चुके होते तो राजनीतिक व फौजी तौर पर नकारात्मक परिणाम का खतरा होता था। दुश्मन का यह उलटा प्रचार कि वह "जीत रहा है" और "आक्रमण" में है, जबकि वह पराजय और आत्मरक्षा की प्रक्रिया में है, आखिरकार जनयुद्ध को ही लाभ पहुंचाएगा।

फिर भी, नए संदर्भ में मौजूदा तरीकों में कार्यवाहियां जारी रखी जानी चाहिए और केन्द्रीकृत बड़ी कार्यवाहियों को संगठित करने पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि वह जवाबी आक्रमण और बगावत की तैयारियों में एक गुणात्मक भूमिका अदा कर सके।

4. फौजी कार्यवाहियों के व्यवहार में बेहतरी

पहाडों में ही नहीं, बल्कि मधेश के मैदानी इलाकों में भी पुरानी राजसत्ता देश के समूचे देहाती इलाकों में बुनियादी तौर पर तबाह हो चुकी है। इस तरह के सभी इलाके पार्टी के नेतृत्व और प्रभाव में आ गए। यह सचाई न सिर्फ हम बल्कि देश के अन्दर और बाहर हमारे दुश्मन भी कबूल चुके हैं।

महान जनयुद्ध के विकास से उपजी इस किस्म की स्थिति में सहज ही आम जनता हमसे ज्यादा गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना की उम्मीद रखती है। लेकिन कुछ संदर्भों में हमारी फौजी कार्यवाहियों के कुछ स्वरूप अब आन्दोलन के विकास के स्तर, (हमारी) जिम्मेदारी और जनता की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे हैं। अगर हमने समय रहते अपनी फौजी कार्यवाहियों के स्वरूपों के व्यवहार में बेहतरी नहीं की, तो आखिरकार नकारात्मक नतीजे ही

निकल आएंगे। इसलिए, फौरी फौजी कार्यवाहियों के संदर्भ में यह जरूरी है कि हमें अपनी धारणा और व्यवहार को निम्न प्रकार स्पष्ट कर लें :

अ) तबाही और निर्माण के बारे में

क्रान्ति का अहम मकसद पुरानी राजसत्ता को तबाह करना और एक नई राजसत्ता का निर्माण करना है। जब तक पुरानी राजसत्ता पूरी तरह तबाह नहीं होती या जब तक क्रान्ति कामयाब नहीं होती, रणनीतिक तौर पर तबाही ही अहम (पहलू) रहेगा। फिर भी, कार्यनीतिक और व्यावहारिक तौर पर उन इलाकों और स्तरों में जहां पुरानी राजसत्ता तबाह हो चुकी हो, निर्माण (का पहलू) अहम बन जाता है। आमतौर पर निर्माण की प्रक्रिया तबाही से शुरू होती है और इन दोनों के बीच एक द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध होता है। लेकिन हमारे व्यवहार में फौजी कार्यवाहियों के कुछ स्वरूपों में तबाही और निर्माण के बीच यह द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पर, ग्रामीण इलाकों में जो अब हमारे नियंत्रण और प्रभाव में आ चुके हैं, पुराने ग्राम विकास कमेटी (वीडीसी) भवनों को जलाने जैसी गतिविधियों को जारी रखना; पुलिस बलों द्वारा खाली किए गए भवनों को उड़ाना जबकि उनके वापिस आने के कोई आसार नहीं है; व्यापारियों, छोटे उद्योगपतियों और दूसरे लोगों के, जो हमारी नीतियों और नियमों का पालन करने के इच्छुक हैं, आर्थिक सुविधाओं को तबाह करना; पूरी तरह तबाह कर देना। इससे जनता में हमारे खिलाफ असंतोष बढ़ने और उसका दुश्मन द्वारा फायदा उठाए जाने का खतरा बढ़ेगा।

इसलिए यह जरूरी है कि ग्रामीण इलाकों में जहां पुरानी राजसत्ता तबाह हो चुकी हो, विकास और निर्माण की गतिविधियों की जिम्मेदारी तथा भौतिक आधारभूत सुविधाओं और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम ले लें एवं इसके लिए जनता को लामबन्द करें। हमें नए किस्म के विकास और निर्माण के क्रियाकलापों पर जोर देना चाहिए। अतीत में पुरानी राजसत्ता और उसके अमले द्वारा इस्तेमाल किए गए भवनों, जमीन, जंगल और अन्य आर्थिक सुविधाओं का हमें उपयोग करना चाहिए और उन्हें तबाह करने की दुश्मन की संभावित कोशिशों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। आने वाले दिनों में ग्रामीण इलाकों में हमें अपनी कथनी और करनी से यह जरूर साबित करना चाहिए।

आ) वर्ग दुशमनों और जासूसों के सफाए के बारे में

वर्ग दुश्मनों और जासूसों के भौतिक सफाए के सम्बन्ध में हमारी पार्टी की नीति यह रही है कि सिर्फ चुने हुए और कम से कम लोगों को, जनता को बताकर और जहां तक सम्भव हो उनकी सहमति लेकर करना चाहिए और कोई क्रूर तरीका नहीं अपनाना चाहिए। आन्दोलन के मौजूदा विकास की जरूरत ने खासतौर पर देहाती इलाकों में इस तरीके में भी बेहतरी करना आवश्यक बनाया। इसका यह मतलब नहीं है कि भौतिक उन्मूलन के सम्बन्ध में दुश्मन द्वारा किए जा रहे जहरीले प्रचार में हमें बह जाना चाहिए। फिर भी, किसी का सफाया करते समय अगर हम वर्ग विश्लेषण, उसके अपराध का स्वभाव, अपराध को साबित करने के लिए जनवादी कानूनी प्रक्रिया और सफाए के तरीके के मामलों में ठोस नीति को विकसित करने और उसका पालन करने में विफल हो जाते हैं तो नकारात्मक नतीजे ही मिल सकते हैं। इस बात को दुश्मन और अवसरवादियों का बेबुनियाद इलजाम कहकर ठुकराया नहीं जा सकता कि अतीत में सफाए की कुछ कार्यवाहियां पर्याप्त चंदे नहीं देने, आश्रय व भोजन नहीं देने, हमारे आन्दोलन का राजनीतिक तौर पर विरोध करने, जासूस होने के शक पर या हमारे स्थानीय दस्ता सदस्यों से दुश्मनी होने आदि गलत कारणों से हुई थीं। इसलिए, आइंदा ग्रामीण इलाकों में अगर किसी का सफाया करना है तो वह कार्यवाही किसी विशिष्ट दस्ता या उसके कुछ निश्चित सदस्यों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि एक निश्चित न्यूनतम कानूनी तरीके के अनुसार ही की जानी चाहिए। हमारी नीतियों और व्यवहार में इसकी अभिव्यक्ति कड़ाई से की जानी चाहिए कि लाल आतंक का मतलब अराजकता नहीं है।

इ) शत्रु सैनिकों और पुलिस बलों के खिलाफ कार्यवाही पर

इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी क्रान्ति का केन्द्रीय व सर्वोच्च काम जनयुद्ध के जरिए हथियारबन्द बलों को सफाया करना है जो पुरानी सरकार के मुख्य अंग हैं। फिर भी, जब हम सैन्य कार्यवाहियों के आम और बूझ स्वरूपों को लागू कर रहे होते हैं, हम अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग तरीके लागू करते हैं और करना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऐम्बुशों, बारूदी सुरंग हमलों, रेडों, कमाण्डो हमलों आदि कार्यवाहियों में मुठभेड़ों के दौरान हम दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर उसे हराने पर जोर देते हैं और देना चाहिए। लेकिन समर्पित शत्रु सैनिकों और पुलिस वालों के प्रति हमारी परिचित नीति यह है कि युद्धबन्दियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए और उन्हें यह समझाया जाए एवं यह मौका दिया जाए कि वे या तो लड़ाई में हमारा साथ दें या फिर घर चले जाएं। अकेले मिलने पर या छुट्टी पर घर आने से, या कहीं भी किसी भी मौके पर सिर्फ इसलिए कि वह शत्रु सेना या पुलिस बल में रहकर रोटी कमाता है, किसी का सफाया करना जनयुद्ध के उसूल और व्यवहार के खिलाफ है। आखिरकार इसके नतीजे में दुश्मन में बिखराव की बजाए एकजुटता ही पैदा होगी। इसलिए, मुख्य रूप से देहाती इलाकों में, जब दुश्मन की सेना या पुलिस बलों में कार्यरत कोई व्यक्ति छुट्टी पर अपने घर आता है तो उसे आतंकित या उसका सफाया नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे अपना सिद्धांत समझाना चाहिए और उसे प्रेरित करना चाहिए कि वह दुश्मन का काम छोड़ दे। हम शुरू से इस सही नीति पर जोर देते आ रहे हैं कि दुश्मन की सेना और पुलिस बल में काम करने वालों के परिवार जनों को समझाना-बुझाना चाहिए, उन्हें गोलबन्द करना चाहिए और उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। अबसे हमें उन्हें आश्वस्त और अवगत कराना चाहिए कि वे चाहे शत्रु सेना में काम करते रहें या चाहे छोड़कर वापिस आ जाएं, उनके परिवार सदस्य सुरक्षित रहेंगे।

जो लोग अनगिनत और अमानवीय अपराध कर चुके हैं, या शत्रु सेना में या पुलिस बल में उच्च अफसर रह चुके हैं, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और धारा 'आ' में बताए मुताबिक कार्यवाही करनी चाहिए।

ई) विपक्षी राजनीतिक नेताओं और काडरों के साथ व्यवहार के बारे में

आमतौर पर विभिन्न प्रतिक्रियावादी और अवसरवादी राजनीतिक पार्टियों के प्रति हमारी नीति राजनीतिक तौर पर उनका पर्दाफाश करने की रही है। हम यह मानते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भौतिक कार्यवाही उसकी किसी खास राजनीतिक पार्टी में सदस्यता के कारण नहीं, बल्कि जनता और जनयुद्ध के खिलाफ उसके अपराध के कारण की जानी चाहिए। और चूंकि सत्तारूढ़ या विपक्षी पार्टियां अलग-अलग तात्कालिक कार्यनीतिक बरताव रखती हैं, हम इसके मुताबिक ही उनके साथ व्यवहार करते आ रहे हैं और इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। हमें उन राजनीतिक पार्टियों के साथ, जो तात्कालिक और कार्यनीतिक अर्थ में ही सही हमारे साथ वस्तुगत रूप से निकट रहती हैं, समुचित रिश्ते कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए।

अतीत में हमारी कुछ कार्यवाहियां अन्तविरोधों के सही और सम्पूर्ण मूल्यांकन के खिलाफ तथा पार्टी की नीति के खिलाफ की गई थीं। इस नई परिस्थिति में हमें जहां एक ओर उपरोक्त नीति का कड़ाई से पालन करना चाहिए और वहीं दूसरी ओर, अगर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई सजा या भौतिक कार्यवाही जरूरी हुई तो ऊपर बताई जनवादी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो जनता को बिना देर उसके कारणों का खुलासा कर देना चाहिए।

उ) चंदा वसूली के बारे में

चंदा वसूली के हमारे तरीके को दुश्मन ने बहस का एक बड़ा मुद्दा बनाया ताकि मध्यम वर्गों में भ्रम फैलाया जा सके। हमारी चंदा वसूली की नीति को ज्यादा व्यवस्थित और बेहतर बनाना जरूरी है ताकि दुश्मन को हमारे खिलाफ यह कोई हथियार न बन सके और मध्यम वर्गों को गलतफहमी व आतंक से मुक्त किया जा सके। अतीत में, चंदा वसूली करते समय सम्बन्धित व्यक्तियों और संगठनों का पर्याप्त वर्ग विश्लेषण करने तथा उनकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करके उसके अनुसार बरताव करने में खामियां होती रहीं। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक उगाही के क्षेत्र में काफी अरजकता बढ़ी थी। इसलिए भविष्य में यह अराजकता समाप्त होनी चाहिए। जनता से वर्ग आधार पर चंदा इकट्ठा करने के लिए आर्थिक उगाही प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित बनाना है जिसके लिए एक ठोस मापदण्ड जरूरी है। दूसरी ओर दुश्मन को दण्डित करने और उससे टैक्स वसूलने का एक तरीका विकसित कर लेना चाहिए।

यह जरूरी है कि (पार्टी) रीजनल ब्यूरों को चन्दा और टैक्स वसूलने की गतिविधियों पर अपना नियंत्रण कायम करना चाहिए।

ऊ) विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों पर

हालांकि अतीत में देहाती इलाकों में पुरानी सरकार के प्रभुत्व को खत्म करने के संदर्भ में हमने कुछ फर्क रखा था, फिर भी आमतौर पर सभी किस्म के एनजीओ और आईएनजीओ के खिलाफ हमारी नीति आक्रामक ही रही। लेकिन इस बदली हुई मौजूदा परिस्थिति में इस नीति में भी बेहतरी लाने की जरूरत है।

उन गैर सरकारी संगठनों के साथ सकारात्मक बरताव करना चाहिए जो पुरानी सरकार के साथ सीधे तौर पर राजनीतिक जुड़ाव नहीं रखते हैं और जो देहाती इलाकों में हमारी नीतियों और योजनाओं के साथ काम करने का इच्छुक हैं। इसी तरह, उन अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों को छोड़कर जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनयुद्ध के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखने वाले अमेरिकी साम्राज्यवाद से सीधे तौर पर वित्तीय मदद मिलती है, तटस्थ देशों या जनयुद्ध के साथ शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं रखने वाले यूरोपियन यूनियन व दूसरे देशों से जुड़े हुए अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों पर हमें कोई भौतिक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए या धमकियां नहीं देनी चाहिए। समस्या को बातचीत, आपसी सहयोग और तालमेल के द्वारा हल करने की कोशिश करनी चाहिए।

5. भावी सैन्य योजना के बारे में

यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि हमारी केन्द्रीय कमेटी द्वारा अपनी पिछली बैठक में तैयार की गई सैन्य योजना सही थी और उस पर अमल की प्रक्रिया अभी जारी है। चूंकि 'अपेक्षाकृत केन्द्रीकरण' शब्द से कुछ भ्रम और पीएलए पर दबाव उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इस योजना में बेहतरी करते हुए अपेक्षाकृत केन्द्रीकृत कार्यवाहियों की नीति को कुछ समय के लिए छोड़ना चाहिए। हमें यह स्पष्टता होनी चाहिए कि वस्तुतः अपेक्षाकृत केन्द्रीकरण विकेन्द्रीकृत कार्यवाहियों में खुद ब खुद मौजूद है। इसलिए, आगामी योजना में विकेन्द्रीकृत कार्यवाहियों को बिना किसी दबाव के दृढ़तापूर्वक जारी रखना चाहिए और केन्द्रीकृत व निश्चित बड़ी कार्यवाहियों के लिए तैयारियां करनी चाहिए।

6. जनता की राजसत्ता की प्रस्तुति के बारे में

मौजूदा परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में जबकि देश के देहाती इलाके जनयुद्ध के प्रभाव और नियंत्रण में आ चुके हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, निम्न लिखित कदम उठाने होंगे ताकि पुरानी सरकार के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप को नई ऊंचाई तक उभारा जा सके।

अ) संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से जनता की सत्ता को प्रतिनिधित्व देने की अपील करना जबकि सैन्य फासीवादी पुरानी सरकार के तथाकथित प्रतिनिधित्व का विरोध करना।

आ) संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए दुनिया के सभी देशों से औपचारिक सूचना के जरिए यह आग्रह करना कि पुरानी सरकार के खिलाफ नई राजसत्ता का समर्थन और सहयोग किया जाए।

इ) नई राजसत्ता की नीति, योजना और कार्यक्रम को व्यवस्थीकृत बनाना जरूरी है ताकि देश के तमाम देहाती इलाकों की जिम्मेदारी ले ली जा सके। इसके लिए, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में जन सरकार का एक ठोस कार्यक्रम लागू करना चाहिए तथा अन्तिम बगावत के लिए तैयारियों में तेजी लानी चाहिए। ★

कॉमरेड गौरव से मिलने आए जर्मन प्रतिनिधिमण्डल के साथ दुरव्यवहार

सितम्बर 2004 में तमिलनाडु पुलिस ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड गौरव को चेन्नई हवाई अड्डे में फर्जी पासपोर्ट रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। तबसे वे चेन्नई जेल में बन्द हैं। मार्च महीने में उनसे मिलने जर्मनी से एक प्रतिनिधिमण्डल आया था। इस प्रतिनिधिमण्डल में विश्व जन प्रतिरोध आन्दोलन (डब्ल्यूपीआरएम) के अधिवक्ता शामिल थे। इस प्रतिनिधिमण्डल के साथ भारतीय अधिकारियों के द्वारा किया गया दुरव्यवहार की कोई सीमा नहीं रही।

24 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमण्डल चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरा। कॉ. गौरव का प्रधान अधिवक्ता राहुल, नेपाली जन अधिकार सुरक्षा समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण पंत, डब्ल्यूपीआरएम - दक्षिण एशिया के रावुन्नि तथा कुछ अन्य लोगों ने हवाई अड्डे पर प्रतिनिधिमण्डल का स्वागत किया। कुछ ही घंटों के बाद प्रतिनिधिमण्डल कॉ. गौरव से मिलने की अनुमति पाने के लिए कोशिशों में जुट गया। बाद में वे तमिलनाडु सरकार के गृह सचिव स्टेड मुनिर होडा से मिलने गए। प्रतिनिधिमण्डल ने उसे कॉ. गौरव से मिलने की अनुमति देने ज्ञापन सौंपा। होडा ने यह दावा किया कि भारत एक जनवादी देश है, अतः बन्दियों से कोई भी मिल सकते हैं। लेकिन जेल अधीक्षक ने यह कहते हुए कि जर्मन अधिवक्ता विदेशी है, प्रतिनिधिमण्डल को कॉ. गौरव से मिलने की अनुमति देने से इंकार किया था। प्रतिनिधिमण्डल ने जब इस बात की ओर होडा का ध्यान आकृष्ट किया, तो उसने 'आश्चर्य' व्यक्त किया और तुरन्त जेलों के अतिरिक्त माहा निदेशक से टेलीपोन पर बात की और प्रतिनिधियों को सूचित किया कि वे कोई भी समय कॉ. गौरव से मिल सकते हैं। कॉ. गौरव से मिलने की कवायद होडा के आश्वासन से भी खत्म नहीं हुई। जैसे ही प्रतिनिधिमण्डल गृह सचिव के कार्यालय से बाहर निकला और अपने वाहन की ओर बढ़ रहा था, वैसे ही राहुल को मोबाइल फोन पर गृह सचिव के निजी सहायक ने सूचना दी कि सचिव कुछ बात करना चाहते हैं। गृह सचिव ने टेलीफोन लाइन पर ही प्रतिनिधिमण्डल को बताया कि कॉ. गौरव से मिलने के लिए उन्हें जर्मन दूतावास से अनापत्ति प्रमाण-पत्र हासिल करना होगा। दूसरे दिन सबेरे प्रतिनिधिमण्डल जर्मन दूतावास गया और अनापत्ति प्रमाण-पत्र हासिल करने में सफल रहा। जर्मन दूतावास ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि उसे प्रतिनिधिमण्डल के कॉ. गौरव से मुलाकात करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिनिधिमण्डल पुनः गृह सचिव के कार्यालय पहुंचा। वहां प्रतिनिधिमण्डल को यह सूचना पाने के लिए कि गृह सचिव 'व्यस्त' हैं आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। प्रतिनिधिमण्डल को गृह विभाग के उप सचिव, जेल किरणबाकरण के कार्यालय जाने के लिए कहा गया। उप सचिव ने तुरन्त मुलाकात करवाने में अपनी असमर्थता बताते हुए कहा कि नियम-कानून एवं प्रक्रिया के स्पष्ट होने के बाद ही मुलाकात सम्भव है। इस दौड़-धूप से यह बात साफ हो गई कि भारतीय अधिकारी किसी भी तरह प्रतिनिधिमण्डल को कॉ. गौरव से मुलाकात करने से रोकना चाहते हैं। साथ ही भारतीय अधिकारी भारत को जनवादी देश साबित करने का प्रयास भी कर रहे थे। इसी का फायदा उठाकर प्रतिनिधिमण्डल ने अधिकारियों पर जोर डाला। यदि भारतीय अधिकारी मुलाकात की अनुमति नहीं देते तो राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय जन मानस को यह साफ संदेश जाता कि कॉ. गौरव की लम्बी हिरासत के पीछे कुछ राज छुपा हुआ है और इसे जनवाद कहना कठिन होगा।

26 मार्च की सुबह जेल जाने के पहले प्रतिनिधिमण्डल आलंदूर के न्यायिक मजिस्ट्रेट राजन से मुलाकात की जिनके पास कॉ. गौरव के पासपोर्ट केस लम्बित है। जज ने यह कहते हुए कि वह अपने कक्ष में वकीलों से बात करने के लिए बाध्य नहीं है और वह न्यायालय में ही बात करेगा, प्रतिनिधिमण्डल से मिलने से इनकार कर दिया। इस खेल को देख रहे सहायक सरकारी वकील ने कहा कि वह उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रतिनिधिमण्डल उससे मिलने की कोशिश न करे। दोपहर 12 बजे के करीब प्रतिनिधिमण्डल गृह सचिव के कार्यालय पुनः पहुंचा और कॉ. गौरव के साथ घंटे भर की मुलाकात की। इस पूरी मुलाकात के दौरान जेल उपाधीक्षक सारे नियमों को ताक में रखते हुए पास में ही बैठा रहा एवं पूरी बातचीत को सुन रहा था। बातचीत के बीच में उसने उच्चाधिकारियों को सदेश भेजा कि प्रतिनिधिमण्डल गौरव से साक्षात्कार ले रहा है जिसे प्रकाशित किया जा सकता है। राहुल ने इस कार्रवाई का यह कहते हुए जोरदार विरोध किया कि गौरव और प्रतिनिधिमण्डल के बीच की चर्चा पूरी तरह गोपनीय है और जेल अधिकारियों को उसमें रोक-टोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

मुलाकात के दौरान उपाधीक्षक ने कॉ. गौरव को जेल की बदतर परिस्थितियों पर बातचीत करने से रोकने की बहुत कोशिश की। जब प्रतिनिधिमण्डल ने उपाधीक्षक से इस बात की पूछताछ की तब उसने बातचीत को बीच में ही काटते हुए कहा कि कॉ. गौरव को विदेशी बन्दी का दर्जा दिया गया है और सब कुछ ठीक है। दरअसल जेल अधिकारियों ने कॉ. गौरव को राजनीतिक बन्दी का दर्जा देने से इनकार किया और उन्हें अखबार एवं पत्रिकाएं तक नहीं दी जा रही हैं। 40 डिग्री सेन्टीग्रेड की तपती गर्मी में उन्हें पंखा तक उपलब्ध नहीं कराया गया और बुनियादी जरूरतों से भी उन्हें वंचित किया गया है।

हालांकि कॉ. गौरव की स्थित बहुत खराब है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जेल की खराब हालत को अपनी क्रान्तिकारी जोश और उत्साह को कम करने की अनुमति नहीं देंगे। कॉ. गौरव ने प्रतिनिधिमण्डल को बताया कि भारतीय अधिकारी उन पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि वे या तो नेपाल सरकार के हवाले किए जाने के लिए तैयार रहें या फिर विदेशियों के लिए बनाए गए विशेष बन्दी गृह में लम्बे समय तक कैद रहने के लिए तैयार रहें जहां की परिस्थितियां और भी दूभर होंगी। उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल को यह जानकारी भी उपलब्ध कराई कि उसी जेल के विशेष शिविर में श्रीलंकाई तमिल लोग विगत 14 सालों से बिना किसी मुकदमे के सड़ रहे हैं। 27 मार्च को प्रतिनिधिमण्डल के द्वारा चेन्नई प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। चेन्नई के इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के 15 संवाददाता इस पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। इस पूरी घटना से सम्बन्धित खबरें अखबार व टीवी चैनलों में दिखाया गया।

अस्थाई सांगठनिक समिति

विश्व जन प्रतिरोध आन्दोलन (यूरोप)

खबरें नेपाल के जंगे मैदान से

गोबेल्स के तरीके का झूठा प्रचार नेपाल की क्रान्ति को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता !

(यह रपट इंटरनेट वेबसाइटों द्वारा प्राप्त सही जानकारी पर आधारित है। चूंकि माओवादी भी अब 4 एफएम रेडियो केन्द्र चला रहे हैं, अतः राजशाही एवं उसके साम्राज्यवादी समर्थक सच्चाई को ज्यादा समय तक छुपा नहीं सकते। माओवादियों के द्वारा संचालित रेडियो केन्द्र पहले 5 थे, जबकि एक केन्द्र हाल ही में पकड़ा गया।)

21 मार्च की रात। समय 10 बजे। जन मुक्ति सेना के लगभग 5,000 जांबाज लाल सैनिकों ने पश्चिमी नेपाल के म्याग्दी जिला मुख्यालय, बेनीबाजार पर धावा बोल दिया। बेनी बाजार दो नदियों के संगम पर बसा है। जबर्दस्त समन्वय के साथ किए गए इस हमले ने शाही सेना (आरएनए) को दहशत में डाल दिया। यहां पर 1,300 सैनिक तैनात थे, जिसमें से 300 सैनिक सड़क बनाने के लिए विशेष रूप से तैनात थे। यह जिला मुख्यालय रोल्पा आधार इलाके से मात्र 150 किलोमीटर दूर है। माओवादी सैनिकों ने जिला मुख्यालय के परिसर, रिहायशी आवास, मुख्य प्रशासनिक भवनों पर एक साथ हमले किए, जिनकी सुरक्षा में 160 सैनिक तैनात थे। जिला पुलिस कार्यालय, जिला प्रशासनिक तथा जिलाधिकारी कार्यालयों पर कब्जा किया गया और अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद भवनों को बमों से उड़ा दिया गया। हताहत सैनिकों की संख्या ज्ञात नहीं है जबकि खबर है कि कई सैनिक इस हमले के बाद भाग गए हैं। मुख्य हमले का निशाना मिलिटरी बैरक थे जहां बड़ी तादाद में सैनिक थे। दो घंटे में ही पांच में से चार बैरकों पर कब्जा हो गया। दो बैंकों को अपने हाथों में ले लिया गया और जिला मुख्यालय का बाकी हिस्सा भी माओवादियों के नियन्त्रण में आ गया। लेकिन पांचवें बैरक पर कब्जे के लिए और 12 घण्टे लड़ाई चलती रही। यही मुख्य बैरक था, जहां बड़े पैमाने पर हथियार, गोलाबारूद तथा बैंकों की नकदी रखे गए थे (बैंकों की नकदी अब नेपाल में बैंकों की बजाए सेना के बैरकों में रखा जाता है और दिन में आवश्यकतानुसार निकाला जाता है) जो माओवादियों के कब्जे में नहीं आ पाया। एक माओवादी वेबसाइट के अनुसार माओवादियों ने 150 राजशाही सैनिकों का सफाया कर दिया और 137 आधुनिक हथियार जब्त कर लिए। शनिवार और रविवार को हुई बेनिबाजार की इस लड़ाई में माओवादियों ने 1 दो इंच मोर्टार, 3 एलएमजी, 15 इंसास रायफलें, 1 एम-16, 8 एसएमजी, 35 एसएलआर, 70 थ्रीनॉटथ्री रायफलें, 15 पिस्तौल, 47 हजार कारतूस जब्त कर लिए।

पुलिस उपाधीक्षक, मुख्य जिलाधिकारी सागरमनी पूराजली सहित 38 अधिकारियों को भी माओवादी अपने साथ ले गए, जिसमें से दो को शाही सेना के हेलिकॉप्टर गन फायर में घायल होने के कारण मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सौंप दिया गया। शेष अभी भी माओवादियों की हिरासत में हैं। बड़े पैमाने पर हुए नुकसानों को छुपाने के लिए सरकार ने 500 माओवादियों को मार गिराने की अफवाह फैलाई। रविवार के देर शाम (21 मार्च) कॉमरेड प्रचण्ड ने एक बयान जारी करके कहा कि केवल 46 माओवादियों ने बेनीबाजार के संघर्ष में अपनी शहादत दी। शहीदों में ब्रिगेड के वाइस कमाण्डर शामिल थे। रात के 10 बजे से शुरू होकर दूसरे दिन दोपहर तक जारी इस लड़ाई में सेना की मदद के लिए अतिरिक्त बल नहीं भेजे गए जबकि आधे घण्टे की दूरी पर (वाहन द्वारा) दो जिला मुख्यालय – पर्वत और बगलांग स्थित हैं जहां एक-एक हजार सैनिक तैनात हैं। नदी पर बने दोनों पुलों को उड़ा दिया गया था तथा बेनी पहुंच मार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया था। इस पूरी कार्रवाई के बाद ही सरकारी हेलिकाप्टर पहुंचे और आसपास के गांवों पर अंधाधुंध बमबारी करके 26 ग्रामीणों को मार डाला गया। बमबारी अभी भी जारी है जिससे हताहतों की संख्या और भी बढ़ सकती है। यह भी खबर मिली है कि बौखलाई शाही सेना जेलों से माओवादी कैदियों को बेनी बाजार इलाके के आसपास लाकर मौत के घाट उतार रही है। यह सब माओवादियों को हुए नुकसानों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए किया जा रहा है।

यह बड़ा हमला उस समय हुआ जब राजशाही को खत्म करने की मांग को लेकर एक बढ़ा जन आन्दोलन चल रहा है जिसमें विपक्षी दल भी शामिल हैं। 12 मार्च को राजा के विरोध में निकाले गए जुलूस में हजारों लोगों ने भाग लिया। साथ ही जन मुक्ति सेना ने सैनिक हमलों में तेजी लाई। विगत 2 सप्ताह के अंतराल में बेनी बाजार की घटना माओवादियों के द्वारा जिला मुख्यालयों पर किया गया दूसरा बड़ा हमला था। इससे पहले माओवादियों ने पूर्वी नेपाल में स्थित भोजपुर जिला मुख्यालय पर हमला किया था जिसमें 32 सुरक्षा बलों का सफाया किया गया था।

बेनी बाजार की लड़ाई के दिन ही माओवादियों के एक दस्ते ने मेहौली हवाई अड्डे पर स्थित कंट्रोल टावर को शक्तिशाली बम से उड़ा दिया। हवाई अड्डे के मुख्य अधिकारी ने कहा कि इस विस्फोट से 25 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। पड़ोसी जिलों से भी माओवादियों के हमलों की खबरें आ रही हैं। बगलांग के बरलाकुती से भी लड़ाई की खबर है। इस बीच कॉ. प्रचण्ड ने घोषणा की कि जब तक प्रगतिशील राजनीतिक समाधान नहीं निकल पाता तब तक बड़े और छोटे हमले जारी रहेंगे। ✶

संघर्ष की राह पर आगे बढ़ती दण्डकारण्य जनता

(कुछ अनिवार्य कारणों से 'प्रभात' के पिछले दो अंकों में संघर्ष की रिपोर्टों को हम शामिल नहीं कर सके, इसके लिए हमें खेद है। हम इस अंक में पिछले 8-9 महीनों की रिपोर्टें इकट्ठे प्रकाशित कर रहे हैं जिससे पाठकों को दण्डकारण्य के आन्दोलन को गहराई से समझने का मौका मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। इस विलम्ब से पाठकों को हुई असुविधा के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। – सम्पादकमण्डल)

माड़ डिवीजन

जनता का दुश्मन कुम्मा डाडी का सफाया

कुम्मा डाडी इंद्रावती एरिया के ताकिलोड गांव का निवासी था। वह कुख्यात जालिम पोदिया पटेल का दहीना हाथ माना जाता था। पोदिया पटेल को जनता के फैसले पर छापामारों द्वारा कुछ साल पहले मार डाला गया था। डाडी का नाम से ही आसपास के लोग डरते थे। जब यहां पर छापामार दस्ते की गतिविधियां नियमित नहीं थीं तब इसकी तूती बोलती थी। लेकिन जबसे इस इलाके में क्रान्तिकारी जन संगठनों की गतिविधियां शुरू हुईं तबसे इसके जुल्मों पर अंकुश लगना शुरू हुआ। बीच में डाडी ने संगठन की गतिविधियों में बाधा डालने की कोशिश की और पंचायत के पैसों का गबन किया तो इसे दो बार चेतावनी दे दी गई। कुछेक लोगों की इसने मनमानी पिटाई भी की।

डाडी का पूरा परिवार ही जन विरोधी था। इसके एक भाई बोटी (गुरूजी) को जनता ने गांव से बहिष्कार कर दिया। उसकी सारी सम्पत्तियां भी जब्त कर लीं। इसके बाद से डाडी पुलिस मुखबिरी करने लगा। गांव में झूठी आजादी के खिलाफ पिछले साल 15 अगस्त को लोगों ने काला झण्डा उठाया तो इसकी सूचना डाडी ने पुलिस को दी। हाल में सम्पन्न लोकसभा चुनाव के मौके पर पुलिस ने इन्द्रावती इलाके में अमानवीय अत्याचार और जुल्म किए थे। एक शादीशुदा महिला बुधरी के साथ सामूहिक बलात्कार करके बाद में उसे गोली मार दी और मुठभेड़ की कहानी फैलाई। एक अन्य किसान चैतू को पुलिस व सीआरपीएफ ने पीट-पीटकर मार डाला। इन जघन्य हत्याओं के विरोध में इस इलाके की जनता ने भैरमगढ़ में एक रैली निकालने का फैसला लिया था। जब लोग रैली की शक्ल में भैरमगढ़ की ओर बढ़ रहे थे तब डाडी ने दौड़ते हुए थाना जाकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। और बाद में बड़ी संख्या में पुलिस आई और लोगों को बन्दूक की नोंक पर तितर-बितर किया। इस घटना के बाद स्थानीय जनता और पार्टी ने इसका सफाया करने का फैसला किया। पीजीए के सदस्यों ने 2004 अप्रैल के आखिरी सप्ताह में इस जन विरोधी का सफाया करके लोगों को राहत दिलाई।

डौला एरिया में मुखबिर जाल को लोगों ने तोड़ डाला

डौला (धौड़ाई) पुलिस थाने से 4-5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांव – मरगडा, सुलुंगा और कनारगांव में पुलिस ने मुखबिरों का जाल तैयार करके रखा था। फिलहाल इन गांवों में क्रान्तिकारी जन संगठनों का निर्माण और आन्दोलन का प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर है। इसका फायदा उठाते हुए पुलिस ने यहां के आवारगर्द किस्म के नौजवानों को इकठ्ठा करके उन्हें तरह-तरह के लालच देकर मुखबिर बना लिया। हैरान की बात यह है कि पुलिस ने मासूम छात्रों को भी अपने घिनौने षड्यंत्र का हिस्सा बनाया। गांव मरगडा से 5, गांव सुलुंगा से 5 और कनारगांव से एक को इस तरह मुखबिर बनाया गया। इनमें अधिकतर 20-22 साल के पढ़े-लिखे नौजवान थे। इन्हें बाकायदा पुलिस ने प्रशिक्षण भी दिया। एसपी ने इन लोगों से बैठक करके इन्हें जन संगठनों और छापामार दस्तों की खोजखबर लगाने, अन्य गांवों के छात्रों को शामिल करके इस नेटवर्क को बढ़ाने, लापता मवेशी ढूंढने के बहाने दूसरे गांवों में जाकर वहां के भरोसेमंद लोगों को मुखबिर बनाने तथा आन्दोलन के लिए मजबूत गांवों में किसी बहाने जाकर लोगों से संपर्क कायम करके सूचना इकठ्ठा करने की जिम्मेदारियां सौंपीं। इन्हें 2 से 4 हजार रुपए के वेतन भी दिए जाते थे।

लेकिन जनता को इसकी भनक लग गई। सुलुंगा गांव के जागुलु नामक व्यक्ति पर जनता को संदेह हुआ। उसे पीजीए के दस्ते ने गिरफ्तार किया और कड़ी पूछताछ की। उसने सारी बातें उगलीं। उन सभी लोगों के नाम बताए जिन्हें पुलिस ने मुखबिर बना रखा है। इसके बाद स्थानीय पार्टी के फैसले के मुताबिक 150 मिलिशिया सदस्यों ने रातोंरात इन तीनों गांवों पर हमला करके सभी मुखबिरों को गिरफ्तार किया। उसी दिन, यानी 16 दिसम्बर, 2003 को 15 गांवों की जनता को बुलाकर एक जन अदालत आयोजित की गई जिसमें कम से कम 3,000 लोगों ने भाग लिया। इनमें महिलाएं, नौजवान, स्कूली छात्र और गुरुजन सभी शामिल थे। अदालत में मुखबिरों ने अपना गुनाह कबूल करते हुए विस्तारपूर्वक बताया कि उन्हें कैसे पुलिस ने लालच में फंसाकर मुखबिर बनाया था और किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया था। बाद में जनता के फैसले पर एक कट्टर मुखबिर लालसाय का सफाया किया गया और बाकी 8 लोगों को चेतावनी के साथ छोड़ दिया गया। इन सभी लोगों से पुलिस के दिए तमाम पैसे लोगों ने जब्त कर लिए। अन्त में जनता ने अपने लोगों को मुखबिर बनाने की सरकार की साजिश के खिलाफ जोरदार नारे लगाए।

ज़ालिम मुखिया मनकू के घर पर आर्थिक हमला

माड़ डिवीजन के इन्द्रावती इलाके के ऊतला गांव का वासी है मनकू। गांव में इसकी कई चल व अचल सम्पत्तियां हैं। वह गांव के गरीबों को धान व धन सूद पर देता था। अगर कोई नहीं लौटा पाता तो उसकी जमीन छीन लिया करता था। इस तरीके से इसने कई लोगों की जमीनें जब्त कर लीं। जो इसकी बात नहीं सुनता उसकी पिटाई भी किया करता था मनकू। इसने दो बेहद गरीब परिवारों के 8 सदस्यों को बन्धुवा मजदूर के बराबर बनाया था। उन्हें सालों से सिर्फ दो जून का खाना देते हुए उनकी मेहनत लूटता रहा। गांव के अन्य

प्रेस वक्तव्य

माड़ इलाके में पुलिसिया दमन का विरोध करो !

पुलिस द्वारा भूमकाल शहीदों के स्मारक की तोड़फोड़ की निंदा करो !!

दिनांक : 29/02/2004

पिछले सप्ताह सीआरपी बलों और नारायणपुर पुलिस जिले के पुलिस बलों ने माड़ अंचल के आदिवासियों पर व्यापक दमन अभियान चलाया। कई बेकसूर लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें नक्सली घोषित किया। सैकड़ों की संख्या में आए हुए सीआरपी और पुलिस बलों ने माड़ के टेकानार, नेलनार, बेरेवाड़ा, इरपानार, कद्देर, टाहकाडोंड, सोनपुर, पैलीपाड, बेच्चा, कीहकाड, बासिंग, डोंढरीबेड़ा आदि गांवों पर छापेमारी करके सैकड़ों लोगों को बेरहमी के साथ मारपीट की। और दर्जनों बेकसूर लोगों को गिरफ्तार करके सिर्फ 25 लोगों को गिरफ्तार करने का बयान दिया। कद्देर और टाहकाडोंड गांवों में पुलिस ने लोगों को इतनी बेरहमी और पाशविकता के साथ पीटा कि कई लोगों के सिर फूट गए। कुछेक लोगों को छुरियों से मारा। नेलनार गांव में पुलिस ने शहीद स्मारक को बन्दूक की संगीनों से कुरेदकर उसे क्षतिग्रस्त किया जो महान भूमकाल संघर्ष में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बनाया गया था। हाल ही में वहां पर एक बहुत बड़ी सभा हुई थी जिसमें करीब 10 हजार लोगों ने भाग लिया और भूमकाल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इस सभा में भाग लेने वाली आदिवासी जनता ने भूमकाल की ऐतिहासिक विरासत को जारी रखते हुए वर्तमान जनयुद्ध को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था। इससे लुटेरे शासक वर्ग और उनके रक्षक पुलिस बल खफा हैं। भाजपा की रमणसिंह सरकार एक तरफ आदिवासियों की भलाई करने का ढिंढ़ोरा पीटते हुए ही, दूसरी तरफ आदिवासियों पर क्रूर दमन चला रही है। उसकी पुलिस ने गांव नेलनार में भूमकाल शहीदों के स्मारक में तोड़फोड़ करके खुद को अंग्रेजी सैनिकों का वारिस साबित किया।

हमारी पार्टी रमण सिंह सरकार के इन बर्बरतापूर्ण क्रियाकलापों की कड़े शब्दों में निंदा करती है। हम यह मांग करते हैं कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तमाम निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा कर दिया जाए। जनता द्वारा निर्मित स्मारकों को सरकार ध्वस्त करने का काम नहीं रोकती है तो सरकार द्वारा निर्मित ढोंगी नेताओं के स्मारकों पर जनता हमला करने को बाध्य होगी। इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार सीआरपी बलों को बड़ी संख्या में तैनात करके समूचे बस्तर में लोगों पर भयानक दमन चलाने की तैयारियां कर रही है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जनता का दमन बन्द करे और सीआरपी बलों को वापिस ले, वरना जनता और जन छापामार सेना (पीजीए) की प्रतिरोधी कार्यवाहियों का सामना करने के लिए तैयार रहे।

(पाण्डू)

सचिव,

माड़ डिवीजनल कमेटी

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार]

लोगों के श्रम का भी शोषण करता था। उसके इन जन विरोधी और जुल्मी क्रियाकलापों के लिए उसे स्थानीय जन संगठन ने दो बार चेतावनी भी दी। लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। लोगों को मार-पीट करना जारी ही था। हाल में उसने अपने पारिवारिक झगड़ों में अपनी सगी बहन को फांसी देकर मारा। इस घटना के बाद पार्टी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने इसकी सारी गलतियों पर जन अदालत चलाई। जन अदालत ने यह ध्यान में रखते हुए कि चेतावनियों का दौर भी पूरा हो चुका है, इसके घर पर आर्थिक हमला करके उसके घमण्ड पर चोट करने का फैसला लिया। इसके अनुसार 30 फरवरी 2004 को 18 गांवों के मिलिशिया सदस्यों और आम लोगों, कुल 500 से ज्यादा लोगों ने हमला किया। इसकी 8 एकड़ जमीन के अलावा घर से करीब 600 बोरा धान, 4 मवेशी आदि जब्त कर लिया गया। यह सारी सम्पत्ति लोगों में बांटी गई। इसके अलावा इसके पास जो लोग सालों से मजदूरी कर रहे थे उनके लिए अलग से जमीन, धान और बैल निकाले गए। इस घटना के बाद आसपास के गांवों के लोगों में बेहद उत्साह का संचार हुआ। लोगों में यह विश्वास बढ़ा है कि वे अपनी एकजुटता से बड़े से बड़े जालिम को भी पंगु बना सकते हैं।

पुलिस मुखबिर बुधराम का खात्मा

माड़ डिवीजन के ग्राम आसनार का सरपंच बुधराम पिछले एक साल से पुलिस मुखबिर बनकर काम कर रहा था। जनता से कार्यवाही के डर से उसने गांव छोड़ा और ओरछा में डेरा जमाया। ओरछा में पुलिस की सुरक्षा में ही रहने लगा था। ओरछा हाट बाजार में जाने-आने वाले लोगों को संगठन सदस्य बताकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाने लगा था। इससे आसनार और आसपास के गांवों के लोगों के लिए बाजार जाना ही खतरा सा बन गया था। ऐसी स्थिति में जनता ने बुधराम को हर कीमत पर खत्म करने की ठान ली। स्थानीय पार्टी ने जन मिलिशिया के सदस्यों को यह जिम्मा सौंपा तो उन्होंने 26 मई को ओरछा में ही उस पर हमला करके मार गिराया। इस कार्यवाही के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय दुश्मनों में कंपकंपी पैदा हुई क्योंकि वे पुलिस की सुरक्षा में भी सुरक्षित नहीं हैं।

मुखबिर महेश का सफाया

डौला एरिया के गांव नरिया (नारायणपुर तहसील) का एक आदिवासी युवक था महेश। 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाला महेश आवारागर्द हुआ करता था। पुलिस को ऐसे ही लोगों की हर दम तलाश रहती है, सो उसने इसे अपना मुखबिर बना ही लिया। यह हर दिन आसपास के गांवों, जो क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए मजबूत माने जाते हैं, का चक्कर लगाया करता था और दस्तों व जन संगठनों की गतिविधियों के बारे में जो भी खबर उसे मिलती थी वह पुलिस को पहुंचाया करता था। ऐसे ही जब महेश एक गांव में आया, तो वहां के जन संगठन कार्यकर्ताओं को उस पर संदेह पैदा हुआ। तुरन्त ही उन्होंने उसे गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। बाद में जनता की अदालत लगाई गई जिसमें 200 लोगों ने भाग लिया। तमाम लोगों ने उसके चरित्र और पुलिस के हाथों औजार की तरह काम करने में उसकी सक्रियता पर गहराई से विचार-विमर्श करके एक मत से फैसला किया कि इसे मार डाला जाए। जनता के फैसले को पीजीए के दस्ते ने तत्काल ही लागू कर दिया।

झूठे गणतंत्र दिवस के खिलाफ डौला के लोगों ने मनाया काला दिवस

26 जनवरी को माड़ डिवीजन के डौला एरिया के लोगों ने काला झण्डा फहराकर झूठे गणतंत्र के प्रति अपना विरोध दर्ज किया। गांव-गांव में इस सम्बन्ध में दीवार-लेखन भी किया गया। कुल 4 जगहों पर डीएकेएमएस और केएएमएस की अगुवाई में सभाएं आयोजित हुईं। इनमें कुल मिलाकर 4,000 लोगों ने भाग लिया। तोयनार, गोटाबेनुर, डंडवंड और मोहनार गांवों में ये सभाएं हुईं। इनमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। इन सभाओं में वक्ताओं ने लोगों को बताया कि भारत का तथाकथित गणतंत्र महज ढोंग है, जबकि यहां अत्यधिक लोगों को कोई आजादी नहीं है। उन्होंने लोगों को अवगत कराया कि देश के लुटेरे शासक वर्ग विदेशी साम्राज्यवादियों, खास तौर पर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के इशारों पर नाचते हैं और देश की सार्वभौमिकता को उनके पास गिरवी रखे हुए हैं। ऐसे में यह वास्तविक गणतंत्र नहीं है और यह संविधान जनता का नहीं है। हमें नव जनवादी क्रान्ति के रास्ते पर चलते हुए इस संविधान को तोड़कर मजदूर-किसानों का संविधान बनाना होगा और हमारे देश को सच्चे लोक गणराज्य में बदलना होगा।

लोगों को डरा-धमकाकर वोट डलवाने वालों को सजा

पिछले 1 दिसम्बर को हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में डौला एरिया के कुछ गांवों में जालिम मुखियाओं ने जनता को डरा-धमकाकर वोट डालने पर मजबूर किया था। बाद में जन संगठनों की अगुवाई में ऐसे जन विरोधियों के खिलाफ जन अदालत बुलाई गई। ग्राम जतापारा के 7 लोग, कज्जुम के 4 लोग, कोसलपारा का कोटवार और गोगला का सरपंच को जनता की अदालत में लाकर सख्ती से पूछताछ की गई। आखिर में जनता ने इन लोगों को यह चेतावनी देकर छोड़ दिया कि आइंदा लुटेरी सरकार का पक्ष लेकर जनता के खिलाफ कोई काम करेंगे तो खैर नहीं।

पुलिस मुखबिर गुडराल का सफाया

डौला एरिया के गांव बेनूर का पारा बाटपल का निवासी गुडराल लम्बे समय से पुलिस मुखबिरी करता आ रहा था। पास के फरसगांव के संगठन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने में न सिर्फ इसका हाथ रहा, बल्कि थाने में इसने पुलिस से ज्यादा क्रूरता से उनकी पिटाई भी की। इन्नर, डंडवन, कलबट्टि और वाकजार गांवों के संगठन कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवाने में इसी का हाथ था। इसे अपने इन काले कारनामों को बन्द करने की चेतावनी देते हुए स्थानीय एरिया पार्टी कमेटी ने पोस्टर भी लगाए, लेकिन गुडराल पर इसका कोई असर न रहा। बाद में बेनूर में थाने से थोड़ी ही दूर पर पीजीए की एक ऐक्शन टीम ने इसका सफाया कर दिया और उससे एक 12 बोर और एक भरमार कुल दो बन्दूकें छीन लीं।

स्कूली चपरासी के भेस में छिपे तीन मुखबिरों को सजा-ए-मौत

क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने की अपनी रणनीति के तहत पुलिस कई घिनौने हथकण्डे अपना रही है। खासतौर पर पुलिस मुखबिरों का मजबूत जाल बनाने के लिए पुलिस कई साजिशें कर रही है। हाल में जनता द्वारा पकड़े गए कुछ मुखबिर स्कूलों में चपरासी का काम कर रहे थे। पुलिस इन मुखबिरों को जानबूझकर चपरासी नौकरी दिलवाया ताकि उन गांवों से क्रान्तिकारी आन्दोलन की गतिविधियों की सूचना इकट्ठी की जा सके और लोगों को कोई शक भी न हो। लेकिन जनता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जनता की नजरों से कोई भी दुश्मन हमेशा छिपकर नहीं रह सकता। आखिर जनता ही क्रान्तिकारी आन्दोलन की ताकत है। डौला एरिया में जनता ने पुलिस की इस किस्म की एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

कोह्कामेट्टा एरिया का ग्राम मुरनार का निवासी मंगल और इंद्रावती एरिया के ओरछा के निवासी संतु और बंगारु – ये तीन पुलिस मुखबिर थे। लेकिन पुलिस ने इन्हें बड़ी साजिश के तहत डौला एरिया में डंडवन और कोंगेरा गांवों की पाठशालाओं में चपरासी नौकरी पर लगवा दिया। ये इन गांवों में चपरासी का काम करते हुए छात्रों को और अपने सगे-संबन्धियों को मुखबिर बनाने लगे थे। कुछ लोगों को इन्होंने थाना ले जाकर पुलिस अधिकारियों से परिचय भी करवाया। छापामार दस्ते के आने-जाने की सूचना इकट्ठा करके हर पांच दिन में एक बार थाना जाकर दे दिया करते थे। इनकी गतिविधियों से जनता को शक पैदा हुआ। जनता से इनके सम्बन्ध में सूचना पाकर छापामार दस्ते ने इन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ की तो इन्होंने सारी बातें उगल दीं। इनमें से संतु और बंगारू को पुलिस ने हथियार भी दिए थे, यह जानकारी भी इन्होंने दी। हालांकि छापामारों के एक टोले ने ओरछा स्थित इनके घरों पर धावा बोल दिया, लेकिन तब तक बात खुल जाने से पुलिस हथियार ले गई थी। इन पर जन अदालत में मुकदमा चलाया गया और जनता के फैसले के मुताबिक इन्हें मार डाला गया।

पश्चिम बस्तर डिवीजन

जन विरोधी तेलम घट्टैया के घर पर जनता का हमला

पश्चिम बस्तर डिवीजन के महेड एरिया में ग्राम कमरगुडा का निवासी तेलम घट्टैया शुरू से जन विरोधी और क्रान्ति विरोधी शख्स रहा। 1991-92 के समय क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ प्रतिक्रियावादियों द्वारा चलाए गए जन जागरण अभियान में भी इसकी भागीदारी रही जो उस समय गांव का सरपंच था।। बाद में जब जन जागरण अभियान को नाकाम बनाया गया तब जनता के फैसले पर इसकी पिटाई भी की गई थी। जनता के दबाव के चलते इसने सरपंच पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन बाद में हुए चुनाव में यह फिर सरपंच बन गया। दोबारा सरपंच बनने के बाद इसने कई घोटाले किए। जनता के नाम पर सरकार से पैसा निकलवाकर खुद ही खा जाना, 'काम के बदले अनाज' की योजना के तहत आने वाले चावल हड़पना और निजी व्यापारियों को बेचना और उसके इस भ्रष्ट आचरण के खिलाफ कोई उंगली उठाता है तो उसकी पिटाई कर देना, आदि काम करता रहा। गांव के तीन अन्य लोग – तेलम भीमा, कोरसा बाबुल और गोटे सम्मैया उसकी हां में हां मिलाते हुए हर दम साथ देते थे। गांव में छापामार दस्ता जाता है तो लोगों को उससे मिलने जाने से मना करते थे और यहां तक कि खाना ले जाने से भी मना करते थे। गांव के लोग इनका विरोध करके कोई कदम नहीं उठा पाते थे। घट्टैया और उसके गुर्गे अच्छी तरह जानते थे कि गांव के लोगों के पार्टी से मिल जाने से लोगों की जागरूकता बढ़ सकती है और उनकी पोल खुल सकती है। इसके बाद उन्हें लूटकर खाने का मौका नहीं रहेगा।

इस पृष्ठभूमि में स्थानीय पार्टी और जन संगठनों ने फैसला किया कि घट्टैया के घर पर हमला करके उसकी सारी सम्पत्तियां छीन कर लोगों में बांटा जाए और इस प्रकार उसे सबक सिखाया जाए। 150 लोगों ने 1 अगस्त 2003 की रात में उसके घर पर धावा बोलकर सारा सामान छीन लिया जिसमें 5 बोरा धान, 10 गायें, 2 भैंसे, 5 बकरियां और अन्य सामान शामिल हैं। बाद में इन चारों लोगों की पिटाई करके यह चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि आइंदा इस तरह के काम करेंगे तो गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

पुलिस मुखबिर कुडियम घट्टी के घर पर हमला

पश्चिम बस्तर डिवीजन के महेड एरिया के नूकनपल्ली गांव आवापल्ली-बीजापुर सड़क पर स्थित है। पहले भी इस गांव के कुछ लोगों को पुलिस ने अपना मुखबिर बनाया था और छापामारों ने एक-दो लोगों का सफाया भी किया था। हाल में कुडियम घट्टी पुलिस का मुखबिर बन गया और जब पुलिस ने इस इलाके में गश्त अभियान चलाया तब इसने उनके साथ रहकर रास्ता दिखाने का काम किया। इसके अलावा गांव के गन्नू जो इसका भाई और सरपंच है, गुरान जो उपसरपंच है, सुनील और एरमोन – ये पांचों लोग पुलिस के मुखबिर बन गए। आवापल्ली थानेदार के साथ इनके पक्के सम्बन्ध बन गए। स्थानीय पार्टी इन्हें पकड़कर जन अदालत में पेश करने का फैसला लेकर सभी को गिरफ्तार किया। चूंकि उस दिन सुनील गांव में नहीं था, इसलिए वह पकड़ में नहीं आ सका। बाद में घट्टी यह सोचकर कि जन अदालत में उसकी पोल खुल जाने से मौत की सजा भी हो सकती है, किसी तरह छापामारों को चक्मा देकर भाग गया। उसके बाद बाकी तीन लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अब वह पुसिस के साथ ही रह रहा है।

बाद में घट्टी पर आर्थिक हमला करके उसे सबक सिखाने का फैसला लिया गया। इसके तहत 2003 के अगस्त महीने में पीजीए के नेतृत्व में 100 लोगों ने इसके घर पर धावा बोलकर 11 बकरियों, 11 गायों और अन्य सामग्रियों को जब्त करके जनता में बांट दिया। बाद में उसके घर को ध्वस्त कर दिया।

15 अगस्त को पश्चिम बस्तर में मना 'काला दिवस'

15 अगस्त 1947 की झूठी आजादी का पर्दाफाश करते हुए पश्चिम बस्तर के नेशनल पार्क और भैरमगढ़ इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया। लोगों को यह अवगत कराते हुए कि 15 अगस्त से सिर्फ सत्ता गोरों के हाथों से काले लुटेरों के हाथों में आई है और गरीबों को कोई आजादी नहीं मिली है, गांव-गांव में पोस्टर-पर्चे बांटे गए। कई पाठशालाओं में छात्र-छात्राओं ने तिरंगे झण्डों को हटाकर काले झण्डे उठाए।

भैरमगढ़ के मिरतुल इलाके में 9 स्कूलों में काला दिवस मनाया गया। एक स्कूल में 150, एक में 130, एक में 220 – इस प्रकार सभी मीटिंगों में 1,080 लोगों ने भाग लिया। इन मीटिंगों में झूठी आजादी का लोगों के बीच पर्दाफाश किया गया। नेशनल पार्क इलाके के केरपे, सेंड्रा, सागुमेट्टा, तोयनार और अन्नापुर की स्कूलों में जन संगठनों की रेंज कमेटियों की अगुवाई में काले झण्डे उठाए गए।

केरपे गांव में 300 लोगों ने, जिनमें कुछ छात्र भी शामिल थे, जुलूस निकाल कर झूठी आजादी के खिलाफ नारे लगाए। सागुमेट्टा में 80, तोयनार में 100 और सेंड्रा में 150 छात्रों और कई अन्य लोगों ने काले झण्डे उठाकर जुलूस निकाले। सभी जगहों पर जन संगठन नेताओं ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित किया। उन्होंने अपने भाषणों में सरकार की यह कहकर निंदा की कि वह एक तरफ आजादी का जश्न मनाते हुए ही दूसरी तरफ, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे लोगों को 'नक्सली' बताकर जेलों में ठूंस रही है और उनकी हत्या कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि 56 साल बीतने के बाद भी जब लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान जैसी न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं मिल पाई हैं तो यह कैसी आजादी है। उन्होंने लोगों को समझाया कि असली आजादी लड़कर ही हासिल की जा सकती है।

लोगों के सामूहिक श्रमदान से तालाब दुरुस्त बना

केरपे गांव में लुटेरी सरकार द्वारा बनाए गए एक पुराने तालाब से ही वहां के आसपास के तीन गांवों के मवेशियों को गर्मियों में पानी मिलता है। पिछले साल (2003) ज्यादा बारिश होने से तालाब में ज्यादा पानी आया और उसका बांध फूट गया। इससे तालाब सूख गया। लोगों ने निश्चय किया कि इसे दुरुस्त बनाने का बीड़ा खुद ही उठाया जाए। चूंकि अब समूचे दण्डकारण्य में हर गांव में जन सरकार

कायम करने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए लोगों ने सोचा कि इसके मरम्मत कार्य के लिए लुटेरी सरकार का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। हालांकि गांव के कुछ परम्परागत मुखियाओं ने कोशिश की कि यह काम लुटेरी सरकार के जरिए ही करवाया जाए जिसमें उन्हें थोड़ी-बहुत दलाली भी मिलने की उम्मीद थी। लेकिन बहुमत उनके खिलाफ था। आसपास के 9 गांवों से कुल 300 लोगों ने लगातार दो दिन काम करके तालाब को सुधार लिया। गौरतलब है कि दो दिन के काम के दौरान खाने के लिए चावल भी वे अपने-अपने घरों से ही लाए थे। इस प्रकार की गतिविधियों से लोगों को यह एहसास होने लगा है कि वे अपनी सामूहिक शक्ति के जरिए कोई भी काम कर सकते हैं।

अकाल से निपटने के लिए लोगों ने ली पहलकदमी

पिछले साल नेशनल पार्क इलाके में फसलें चौपट हो जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी थीं। लोगों को दाने-दाने के लिए तरसना पड़ा। ऐसी स्थिति में स्थानीय जन संगठनों ने पहलकदमी लेते हुए इलाके के धनी और मध्यम किसानों से अपील की कि वे लोगों को खाने के लिए कुछ अनाज दें। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से अनाज दे दिया जो कुल जमा 190 बोरे हो गए। इस अनाज को नितांत गरीब लोगों को प्रत्येक घर को एक बोरे के हिसाब से बांट दिया गया। इसके अलावा चन्दे के रूप में पैसे भी इकट्ठे किए गए। इन पैसों से 96 क्विन्टल चावल खरीदकर उन परिवारों में बांटा गया जो भूख से पीड़ित थे।

लुटेरी सरकार की ओर से इस इलाके में 'काम के बदले अनाज' के नाम पर कुछ योजनाएं शुरू की गईं। लेकिन इन योजनाओं से गांव के इने-गिने लोगों को ही फायदा हो रहा था और इसका मोटा हिस्सा मुट्ठी भर लुटेरे अधिकारियों की जेब में जा रहा था। और बहुत सारा चावल पिछवाड़े से धन्ना सेठों की दुकानों में पहुंचाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने सरकार की इन झूठी विकास योजनाओं का विरोध करके 160 क्विन्टल चावल जब्त करके आपस में बांट लिया।

इसी प्रकार मिरतुल एरिया में भी लोगों ने जन संगठनों की अगुवाई में अकाल से निपटने के लिए अगस्त 2003 में कुछ कदम उठाए। स्थानीय धनी किसानों से करीब 100 बोरा धान तथा आसपास के कस्बों में स्थित व्यापारियों से करीब 100 क्विन्टल चावल चंदे के तौर पर इकट्ठा करके उन परिवारों को बांट दिया गया जो अकाल से बुरी तरह प्रभावित थे। बेहद तंगी के उन दिनों में एक-एक परिवार को 15-15 किलो चावल मिल गया।

उत्तर बस्तर डिवीजन

पृथक बस्तर राज्य के लिए लोगों का संघर्ष

1 नवम्बर 2003 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर बस्तर के लोगों ने पृथक बस्तर राज्य की अपनी मांग को दोहराते हुए जगह-जगह रैलियां, जुलूस आदि निकाले। उत्तर बस्तर के कडिमे एरिया में एक सभा हुई जिसमें 100 महिलाओं समेत कुल 600 लोगों ने भाग लिया।

केसकाल एरिया में बारदा एलजीएस की अगुवाई में उरंदाबेड़ा रेंज के ग्राम पोलफा में एक बड़ी सभा हुई जिसमें 29 गावों से आए हुए 1,020 पुरुषों और 644 महिलाओं ने भाग लिया। सभा के पहले एक जुलूस भी निकाला गया जिसमें पृथक बस्तर राज्य की मांग के समर्थन में जोरदार नारे लगाए गए। स्थानीय 'चेतना नाट्य मंच' के कलाकारों ने अपने नाच-गाने से इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। बाद में लोग सभा-स्थल पर पहुंचे और वक्ताओं के भाषणों को ध्यान से सुना। सभा को डीएकेएमएस रेंज कमेटी अध्यक्ष कॉमरेड सोनू, सदस्य कॉमरेड अनील, केएमएस अध्यक्ष कॉमरेड जानकी ने सम्बोधित किया। इसके बाद एलजीएस कमाण्डर कॉमरेड जयमती और एरिया कमेटी सचिव कॉमरेड सुभाष ने अपना भाषण दिया। उन्होंने बस्तर के इतिहास पर रोशनी डालते हुए लोगों को विस्तारपूर्वक बताया कि पृथक बस्तर राज्य की मांग कितनी जायज और प्रासंगिक है। सभा के अन्त में सीएनएम के सांस्कृतिक कर्मियों ने बढ़िया कार्यक्रम पेश किए। बस्तर के लोगों के अतीत के संघर्षों के बारे में और झूठे चुनावों के बारे में उन्होंने छोटे-छोटे दो नाटक भी प्रदर्शित किए।

पृथक बस्तर राज्य की मांग के समर्थन में किसकोडो गांव में एक रैली निकाली गई जिसमें 150 महिलाओं समेत कुल 700 लोगों ने भाग लिया। इसकी अगुवाई डीएकेएमएस की रेन्ज कमेटी ने की। रैली के बाद आयोजित सभा को रेन्ज कमेटी सदस्यों ने सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर का विलय अन्याय था। बस्तर का शुरू से ही अलग अस्तित्व रहा है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बस्तर की असीम सम्पदाओं को निर्बाध लूटने के लिए ही शासक वर्ग पृथक बस्तर राज्य की मांग को ठुकरा रहे हैं। सभा के अन्त में स्थानीय 'चेतना नाट्य मंच' के कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों का मन मोह लिया।

इसी प्रकार अन्तागढ़ रेन्ज के धौसा गांव में भी लोगों ने रैली निकालकर पृथक बस्तर राज्य की मांग दोहराई। रैली के बाद सभा भी हुई। इसमें कुल 9 गांवों के 250 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। डीएकेएमएस और केएएमएस के रेन्ज कमेटी नेताओं ने सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बस्तर के जबरिया विलय की जमकर निंदा की। लोगों ने संकल्प लिया कि पृथक बस्तर राज्य के लिए अपना आन्दोलन तेज करेंगे।

डीएकेएमएस का उरंदाबेड़ा रेंज सम्मेलन कामयाब

उत्तर बस्तर डिवीजन के केशकाल इलाके में आने वाले उरंदाबेड़ा रेंज में सितम्बर 2003 में डीएकेएमएस का रेन्ज सम्मेलन सफलता से सम्पन्न हुआ। पहले रेंज कमेटी अध्यक्ष कॉमरेड सोनू ने डीएकेएमएस का झण्डा फहराकर सम्मेलन का प्रारम्भ किया। इस सम्मेलन में डीएकेएमएस के घोषणा-पत्र पर चर्चा हुई। इसके अलावा स्थानीय समस्याओं को लेकर भी गहन विचार-विमर्श हुए और उसके बात उनको लेकर कुछ फैसले और प्रस्ताव भी किए गए। मुख्य रूप से बलपूर्वक विवाह को बन्द करने, विवाह के मौके पर खर्च कम करने, मुरगा बाजारों के आयोजन को हतोत्साहित करने आदि रिवाजों से जुड़े विषयों पर चर्चा के बाद समुचित फैसले लिए गए। इसके

अलावा स्थानीय समस्याओं को लेकर जन संघर्षों को तेज करने और अधिक से अधिक लोगों को संघर्षों में लामबन्द करने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रस्ताव किए गए। संघर्ष को मजबूत करते हुए संगठन को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ प्रतिनिधिगण अपनी-अपनी जगहों में चले गए।

दक्षिण बस्तर डिवीजन

6 दिसम्बर को साम्प्रदायिकता-विरोधी दिवस मना

6 दिसम्बर 2003 को किष्टारम इलाके में कई जगहों पर साम्प्रदायिकता-विरोधी दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई सभाएं और बैठकें हुईं। विरोध जताने के लिए काले झण्डे भी फहराए गए।

6 दिसम्बर 1992 को संघ गिरोह के भाजपा, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद आदि कट्टर हिन्दुत्ववादी संगठनों ने बाबरी मस्जिद को ढहाया था। देश में हिन्दू कट्टरवाद को बढ़ावा देकर अपना उल्लू सीधा करने के इरादे से ही इन्होंने यह जघन्य हरकत की थी। उसके बाद हुए दंगों और कई अन्य मौकों पर हुए दंगों में अनेक मासूम मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। मुसलमानों के साथ-साथ ईसाइयों पर भी हिन्दू फासीवादियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं जिससे उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ चुका है। आदिवासी इलाकों में कट्टर हिन्दू संगठन तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। आदिवासी संस्कृति को तबाह करते हुए उन्हें जबरन या बहला-फुसलाकर हिन्दू बनाया जा रहा है। 2002 में गुजरात में ढाई हजार से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम ने देश में बढ़ रहे साम्प्रदायिकतावाद की भयावह तस्वीर सामने लाई है। ऐसे में 6 दिसम्बर को साम्प्रदायिकतावाद के खिलाफ आवाज बुलन्द करने का महत्व और भी बढ़ गया है।

पार्टी के आह्वान पर चिन्ना केडवाल गांव में एक सभा हुई जिसमें 110 लोगों और 25 पीजीए सैनिकों ने भाग लिया। सभा के प्रारम्भ में काला झण्डा फहराया गया। धर्मोन्माद के खिलाफ नारे लगाए गए और जुलूस भी निकाला गया। बाद में सभा को स्थानीय कॉमरेडों ने सम्बोधित किया। ग्राम बूर्गुलंका और एल्मागोंडा में भी इस प्रकार सभाएं हुईं जिनमें क्रमशः 230 और 150 लोगों ने भाग लिया। इन गांवों में काला झण्डा उठाकर विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। सभाओं में भाग लेने वाले लोगों ने हिन्दू धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ नारे लगाए।

पुलिस दलाल करटम गंगाल को जनता ने मार डाला

दक्षिण बस्तर डिवीजन के कोंटा इलाके के एर्राबोर के निकट ग्राम वोड्डिनगूडेम का निवासी करटम गंगाल, जो पुलिस का दलाल बन चुका था, को जनता ने पीजीए की मदद से 31 दिसम्बर 2003 को मार डाला। इसका ब्यौरा इस प्रकार है – क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने की मंशा से छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ नए थाने खोलने का फैसला लिया जिनमें से एक एर्राबोर में तय हुआ। चूंकि सरकार को लोगों से प्रतिरोध उठ खड़े होने का डर था, इसलिए पुलिस की सुरक्षा में ही थाना भवन एक माह के भीतर बना दिया गया। निर्माण के दौरान 30 सिविल पुलिस वाले और 50 सीआरपीएफ वाले रहा करते थे। एक तरफ थाना भवन बनाते हुए ही पुलिस ने मुखबिरों का जाल बुनाने की कोशिशें भी तेज कीं। खास तौर पर कुछ पुलिस वाले, जो स्थानीय भाषा और रस्मोरिवाजों से परिचित थे, इसी काम में लगे हुए थे। पढ़े-लिखे बेरोजगारों, आवारागर्दों, शराब बेचने वाली महिलाओं, आदि पर खास नजर रखकर उन्हें पैसे का लालच दिखाकर मुखबिर बना लिया। पुलिस ने 3 महीनों के अन्दर ही इस प्रकार 20 से ज्यादा लोगों से सम्पर्क बना लिया। उन्हीं में से एक था करटम गंगाल जिसके साथ पुलिस ने तब सम्पर्क साधा था जब वह एर्राबोर में लगने वाले हाट बाजार गया हुआ था।

पहले तो उसे सब्जियां लाने आदि हल्के-फुल्के काम बताया जाता था, बाद में धीरे-धीरे मुखबिर बनने को कहा गया। उसे 500 रुपए और नए कपड़े भी पुलिस ने दिए। गंगाल प्रलोभन में आ गया। इसे खास तौर पर कुछ काम सौम्पे गए – मसलन, शबरी नदी पार करके बस्तर और उड़ीसा में प्रवेश करने वाले दस्तों की सूचना तुरन्त देना, एर्राबोर के निकटवर्ती गांवों में अगर दस्ता आता है तो उसकी सूचना देना, आसपास के गांवों के 8वीं पास बेरोजगार युवकों से गुप्त रूप से मिलकर उन्हें मुखबिर बनने प्रोत्साहित करना, पुलिस थाने के सामने नाका पर रहकर आने-जाने वाले लोगों में से संगठन सदस्यों व सक्रिय कार्यकर्ताओं को पहचानना। अगर संगठन सदस्य को पकड़ाएगा तो 1,500 रुपए और संगठन नेता को पकड़ाएगा तो 2,000 रुपए का इनाम भी देने का वादा किया गया। इस लालच में गंगाल ने मराइगूडेम गांव के पटेल को संगठन सदस्य बताकर पुलिस के हाथों पकड़वाया था। पुलिस ने उन्हें 3, 4 दिनों तक बुरी तरह पीटकर बाद में छोड़ दिया। गंगाल इसी कोशिश में था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पुलिस के हाथों पकड़वाया जाए। इस बीच इसकी हरकतों के बारे में जनता ने स्थानीय छापामार दस्ते को इत्तला दी।

इसे तुरन्त गिरफ्तार करने का फैसला लिया गया। कुल 200 लोगों ने, जिनमें जन संगठनों और मिलिशिया संगठनों के सदस्यों समेत आम लोग भी शामिल थे, 29 दिसम्बर की रात को गंगाल को उसके घर से उठा लाया। उसकी सूचना पर कुछ अन्य संदेहास्पद लोगों को भी पकड़ लिया गया। अगले दिन स्थानीय पार्टी ने एर्राबोर के आसपास के 20 गांवों के लोगों से जन अदालत बुलाई जिसमें 1,000 जनता ने भाग लिया। यह अदालत लगातार दो दिन चली जिसमें गंगाल से कड़ी पूछताछ की गई। उसने उपरोक्त सारी बातें उगल दीं। एर्राबोर में पुलिस द्वारा रची जा रही साजिशों और उसके साथ सांठगांठ करने वाले अन्य लोगों के बारे में उसने जनता को बताया। बाद में जनता ने एकमत से फैसला सुनाया कि ऐसे व्यक्ति को, जिसने क्रान्तिकारी आन्दोलन और जनता के साथ गद्दारी की, माफ नहीं किया जाए। बाद में जनता ने इसे पीट-पीटकर मार डाला।

इसी मौके पर जन अदालत के फैसले के अनुसार कुछ अन्य लोगों को पिटाई करके छोड़ दिया गया जो पुलिस से हाथ मिलाए हुए थे। जनता ने पुलिस की साजिशों के हराने का अपना संकल्प दोहराया।

मिलिशिया ने किया जनता का कट्टर दुश्मन और गोपनीय सैनिक सुक्काल का सफाया

सुक्काल मूलतः पश्चिम बस्तर डिवीजन के गंगलूर इलाके का निवासी था। वहां रहते समय वह पुलिस का दलाल बन गया और गोपनीय ढंग से होमगार्ड काम करने लगा था। स्थानीय पार्टी नेरुसे मार डालने का फैसला लिया था। किसी तरह उसको शक हुआ और गांव छोड़कर दोरनापाल इलाके में आया। पुलिस ने उसे मन्नीकुण्टा गांव में जा बसने को कहा। वहां गांव के सरपंच और पटेल से दोस्ती करके गांव में डेरा बना लिया। पास के गांव गगनपल्ली की एक लड़की से शादी भी कर ली और बच्चे भी पैदा किए। इस तरह चार-पांच साल गुजर गए। यहां से भी वह मुखबिरी का काम जारी रखा हुआ था । जनता के जरिए इसके बारे में स्थानीय पार्टी को सूचना मिली थी। लेकिन पार्टी ने उसके बीवी-बच्चों को देखकर चेतावनी देकर उसे सुधरने का एक मौका दिया। इसके बाद वह बीवी-बच्चों को छोड़कर दोरनापाल थाना भाग गया। वहीं रहकर स्थानीय संगठनों और पार्टी के सम्बन्ध में मुखबिरी करने लगा था। आसपास के गांवों के लोगों के लिए यह सिरदर्द का कारण बन गया था क्योंकि किसी काम पर दोरनापाल जाने वालों को यह पुलिस की मदद से प्रताड़ित किया करता था। पार्टी के फैसले के मुताबिक पीजीए के सैनिकों ने इसे मार डालने की दो-तीन कोशिशें कीं पर सफल नहीं रहीं। आखिरकार 15 सितम्बर 2003 को इसे पीजीए के आधार बल सैनिकों ने घर पर ही धर-दबोचा और वहीं मार डाला जबकि वह अपने बीमार बीवी-बच्चों से गुप्त रूप से मिलने आया हुआ था। इस कार्यवाही से पीजीए के सैनिकों ने यह संदेश दिया कि जनता के दुश्मनों को आखिरकार अपनी जन विरोधी गतिविधियों का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा।

गोपनीय होमगॉर्ड पूनेम नागेश का सफाया

छत्तीसगढ़ सरकार दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया करने के लिए व्यापक दमनचक्र चला रही है। इसके तहत मुखबिरों और कोवर्टों को बड़े पैमाने पर तैयार कर रही है। दक्षिण बस्तर डिवीजन के बासागूडेम रेंज गांव लिंगगिरी का निवासी पूनेम नागेश को पुलिस ने होमगॉर्ड के रूप में नियुक्त किया। पिछले छह माह से नागेश बासागूडेम के थानेदार की देखरेख में मुखबिरी कर रहा था। इसे बाकायदा 1800 रुपए प्रति माह वेतन भी दिया जाता था। यह गांव में रहते हुए डीएकेएमएस का सचिव भी बन गया। एक तरफ जन संगठन में रहते हुए ही दूसरी तरफ बड़े ही गोपनीय तरीके से पुलिस के साथ संपर्क जारी रखा हुआ था। सीबीआई में काम करने वाले एक अधिकारी के साथ भी इसके सम्बन्ध रहे। लेकिन जनता को इसके कारनामों पर शक हुआ और पार्टी को इसकी इत्तला मिली। तत्काल ही पीजीए के एक दस्ते ने पूनेम नागेश को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उसने चार बार पुलिस को सूचना देना कबूल किया। गांव में जन संगठनों में काम करने वाले सभी सदस्यों के नाम पुलिस को बताना भी इसने कबूला। इसके बाद 18 गांवों के लोगों को बुलाकर एक जन अदालत आयोजित की गई जिसमें एकमत से फैसला हुआ कि इसका सफाया किया जाए। 9 फरवरी 2004 को जन मिलिशिया के एक दस्ते ने इसे जेगुरगोण्डा कस्बे में ले जाकर थाने से 10 मिनट की दूरी पर इसका सफाया कर दिया।

गड़चिरोली डिवीजन

आन्ध्र के लोगों, हम तुम्हारे साथ हैं !

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] की केन्द्रीय कमेटी के आह्वान पर आन्ध्रप्रदेश में जारी पुलिसिया दमन के खिलाफ मार्च 2003 में दण्डकारण्य भर में विरोध सप्ताह मनाया गया। इसके तहत गड़चिरोली में भी जनता ने कई जगहों पर सभा-जुलूस आदि का आयोजन किया। भामरागड़ इलाके में दो जगहों पर सभाएं हुईं। 23 मार्च को आयोजित एक सभा में 6 गांवों से आए 300 लोगों ने भाग लिया तो दूसरी जगह पर 4 गांवों से 200 लोगों ने सभा में भाग लिया। स्थानीय एरिया पार्टी कमेटी सदस्यों ने सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने आन्ध्रप्रदेश के क्रान्तिकारी किसान संघर्ष को उत्कृष्ट संघर्ष बताया। गत 30 सालों से आन्ध्र की जनता वीरतापूर्ण कुरबानियां देते हुए अपनी समस्याओं पर लड़ रही है। वह क्रान्तिकारी संघर्ष देश के अन्य इलाकों में भी फैल गया और वहां की जनता के लिए प्रेरणास्रोत बन गया। हमारे दण्डकारण्य आन्दोलन के साथ आन्ध्र के संघर्ष का अटूट सम्बन्ध है। उस आन्दोलन पर शुरू से ही पुलिसिया दमन जारी था जो कि तेलुगुदेशम के शासन के दौरान तीखा बन गया। 1400 क्रान्तिकारियों को पुलिस ने मार डाला। क्रान्ति के समर्थकों के सैकड़ों परिवारों को पुलिस कई प्रकार की प्रताड़नाएं दे रही है। क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखने पर पुलिस लोगों को अवर्णीय यातनाओं का शिकार बना रही है। फिर भी वहां के किसान नित्य दमन के बीचोंबीच भी अपनी समस्याओं पर लड़ रहे हैं। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों बिक चुके चन्द्रबाबू की नीतियों के खिलाफ जनता बिना रुके लड़ रही है। यही बात पुलिस के गले नहीं उतर रही है। और इसलिए आन्दोलन को दबाने की भरसक कोशिश कर रही है। हम उनके संघर्षों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे ताकि लुटेरे शासक वर्गों की साजिशों को नाकाम किया जा सके। आन्ध्र के क्रान्तिकारी संघर्ष के प्रति भाईचारा प्रकट करते हुए क्रान्तिकारी जनता के साझे प्रतिरोध को हम विकसित करेंगे – इस प्रकार वक्ताओं ने लोगों को संदेश दिया। आखिर में सभी लोगों ने लाल झण्डे उठाकर ''आन्ध्र के लोगों, आप अकेले नहीं हैं'', ''नव जनवादी क्रान्ति जिन्दाबाद'', ''आन्ध्र, बिहार, झारखण्ड और दण्डकारण्य किसान संघर्ष जिन्दाबाद'' आदि नारे गोण्डी भाषा में लगाए। उस दिन शहीद भगत सिंह की शहादत की सालगिरह भी थी और इस मौके पर लोगों ने उस महान शहीद को भी याद किया और श्राद्धांजली पेश की।

इसी मौके पर लोगों ने इस इलाके में बढ़ते जन विरोधियों के बारे में विचार-विमर्श किया। उन्होंने फैसला लिया कि गड़चिरोली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे दमनात्मक कार्यवाहियों में भाग लेते हुए जनता को प्रताड़ित कर रहे गद्दारों को दण्डित किया जाए। बाद में इस इलाके के मोडुस्के पटेल, गट्टा गांव का पटेल गोटा सत्तू, दुब्बागूडेम

पुलिसिया राज में पुलिस जो कहे वही अपराध !?

गड़चिरोली डिवीजन में पुलिसिया दमन के बारे में 'प्रभात' में सिलसिलेवार रिपोर्टें प्रकाशित की जा रही हैं, अतः पाठकों को यह मालूम होगा कि वहां पर पुलिसिया राज जारी है। खाकी बलों का कानून चल रहा है। कोठी गांव में यह घटना भी इसी की कड़ी है।

भामरागड़ इलाके में पेनकोठी अपेक्षाकृत बड़ा गांव कहलाता है। यहां पर हाई स्कूल है जहां 10वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता है। उसके ठीक बगल में पुलिस थाना मौजूद है। दरअसल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दण्डकारण्य में जानबूझकर इसी प्रकार पुलिस थाने बनाए जा रहे हैं।

18 फरवरी 2002 को पीजीए के छापामारों ने पुलिस थाने पर गोलीबारी की थी। वहां हो रहे फर्जी पंचायत चुनावों का बहिष्कार करने के सिलसिले में यह गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुए और कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन सुबह गांव के स्कूल से सडिमेक गुरूजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

क्यों? उनका अपराध क्या था?

पुलिस का आरोप है कि नक्सलवादियों ने उनके घर के बगल से ही गोलीबारी की थी और गुरूजी ने ही उनके साथ सांठगांठ करके यह काम करवाया। अब दो साल के बाद भी गुरूजी की रिहाई नहीं हुई। गांव का बच्चा-बच्चा बताएगा कि पुलिस जो कुछ कह रही है वह सरासर झूठ है। सडिमेक गूरूजी गांव में 20 सालों से कार्यरत थे। ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने का एक मात्र कारण यह था कि उनका भतीजा पीजीए में एक प्लटून कमाण्डर है। यह सीधा-सीधा बदले की कार्यवाही के अलावा कुछ भी नहीं है। पुलिस के करतूतों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ।

उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक हालत बिगड़ जाने से कालेज में पढ़ रही उनकी बेटी को पढ़ाई बीच में ही रोक देनी पड़ी। उनके जवान बेटे को गांव तुम्मिरिकोडी में गुरूजी की नौकरी मिल तो गई पर वह भी चार दिन की चांदनी साबित हुई। एक दिन जब उनके लड़के ने कोठी थाना जाकर अपने पिताजी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पुलिस से सवाल-तलब किया तो दरोगा ने यह धमकी दी कि तुझे देख लूंगा।

चूंकि इस इलाके में पुलिस द्वारा झूठी मुठभेड़ में लोगों का मारा जाना कोई नई बात नहीं है। इन्हीं पुलिस वालों ने कुछ साल पहले चिन्ना मेट्टामी को ऐसी ही एक झूठी मुठभेड़ में मार डाला था, जिसकी याद लोगों में अभी भी ताजी ही है। ऐसी स्थिति में पुलिस की धमकी के बाद उन्होंने अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर स्थित तुम्मिरिकोडि में नौकरी ही छोड़ दी क्योंकि उन्हें कोठी थाने के सामने से ही जाना पड़ता है। उन्हें डर है कि पुलिस पकड़कर कहीं झूठी मुठभेड़ में न मार दे। यह है गुरूजी के बेटे की हालत।

हालांकि गड़चिरोली के शिक्षकों ने इस सम्बन्ध में शुरू में कुछ विरोध खड़ा किया लेकिन पुलिस अफसरों की धमकियों से वे अब पीछे हट गए। पुलिस के आपराधिक हमले अभी भी जारी है। इसके पहले 2002 में भामरागड़ इलाके के ही लहिरी में भी पुलिस ने एक गुरूजी को गिरफ्तार किया था। उन पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मालू कोपा बोगामी की हत्या का मामला दर्ज किया। (मालू का सफाया पीजीए ने फरवरी 2002 में किया था) वो आज भी जेल में सड़ रहे हैं। उन पर पोटा लगाने की संभावना के मद्देनजर इस इलाके के कर्मचारी भयभीत हैं।

गड़चिरोली डिवीजन में गुरूजी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मलेरिया उन्मूलन कार्यकर्ता, सचिव आदि कर्मचारियों को भी आज सुरक्षा नहीं है। उन पर कब और कहां पुलिस की मार पड़ेगी यह कोई नहीं जानता सिवाए पुलिस के। दिनोंदिन असुरक्षित बन रहे कर्मचारियों के सामने जुझारू संघर्षों का रास्ता अख्तियार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ★

का पटेल, गोटपाड का पटेल, खियेर का विकासखण्ड अध्यक्ष (सभापति) रामा बोगामी, रामजी आदि जालिम और जन विरोधियों की जनता के फैसले के मुताबिक पिटाई की गई। उन्हें यह चेतावनी दी कि आइंदा अगर वे किसी प्रकार की जन विरोधी कार्यवाहियों में शामिल हो जाते हैं तो गंभीर खामियाजा भुगतने को तैयार रहें।

जनता ने वन विभाग वालों के वाहन फूंके

सिरोंचा इलाके के आसारेल्ली रेंज के वन विभाग वालों के एक जीप और एक ट्रैक्टर को 24 अगस्त 2003 को जनता ने सोमनपल्ली गांव के निकट जला दिया। इस इलाके में वन विभाग वालों के जुल्म बढ़ गए थे। इसके पहले ही यहां पर उनकी सारी गतिविधियों को बन्द करने को कहा गया था। कुछेक जन विरोधी अधिकारियों को जनता ने सजा भी दी थी। लेकिन वे दूसरे हथकण्डे अपनाते हुए अपनी विभागीय गतिविधियां चलाने की कोशिश में थे। उन्होंने गांव में मन्दिर निर्माण करने की बात कहकर 20 हजार रुपए रिश्वत देकर गांव में फिर से डेरा डालने की कोशिश की। जनता से घूस वसूलना, लकड़ी लाने पर मामला दर्ज करना, जुल्म करना आदि का सिलसिला फिर से शुरू हो गया जो अरसा पहले क्रान्तिकारी आन्दोलन के दबाव में बन्द हो चुका था। इससे जनता में इनके खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। छापामार दस्ते की मदद से लोगों ने उनके वाहनों को जला दिया। और अधिकारियों से यह मांग भी की कि किसानों पर दर्ज किए गए मामलों (पीओआर) को तत्काल वापिस लिया जाए।

जन विरोधी सरपंच पोयम बापू की पिटाई

सिरोंचा इलाके के आसारेल्ली रेंज के गांव सेतालापल्ली का सरपंच पोयम बापू की 2 अप्रैल 2003 को जन अदालत के फैसले के अनुसार पिटाई की गई। इसने लोगों से सरकार से कर्ज और मकान दिलवाने के बहाने प्रत्येक व्यक्ति से 5,000 रुपए वसूला था। ग्राम पंचायत के नाम से सरकार से मिलने वाले पैसों में इसने बड़ी हेराफेरियां कीं। जो व्यक्ति इसका विरोध करता या इस बारे में पूछता तो बापू उसकी मारपीट करता। इस इलाके में एक लम्बे अन्तराल के बाद हमारी पार्टी के नेतृत्व में संगठन दोबारा मजबूत होने

गड़चिरोली में पुलिस कर्मी की गिरफ्तारी और रिहाई

अक्टूबर 2003 में गड़चिरोली डिवीजन में पीजीए के एक दस्ते ने मालेवाड़ा थाने के पुलिस मुंशी सुरेश किरगे को गिरफ्तार किया और पांच दिन अपनी हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया। सुरेश अपनी पत्नी के साथ एक सवारी बस में जा रहा था जिसकी खबर जनता से पीजीए को मिली। तुरन्त ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि सुरेश क्रान्तिकारियों के खिलाफ किसी दमनात्मक कार्यवाही में सीधे तौर पर शामिल नहीं था और निहत्था भी था, इसलिए पीजीए ने अपने उसूल के अनुसार उसे कोई नुकसान न करने का फैसला किया। लेकिन इस मौके का पीजीए ने बढ़िया इस्तेमाल किया ताकि निचले दर्जे के पुलिस वालों में यह संदेश पहुंचाया जा सके कि वे जिस सरकार के लिए काम कर रहे हैं वह दरअसल उनकी नहीं है। पीजीए ने सुरेश को हिरासत में लेते हुए सरकार के सामने यह मांग रखी कि अगर वह सुरेश की रिहाई चाहती है तो उस इलाके के गिरफ्तार किसानों को तुरन्त रिहा करे जिन्हें झूठे केस लगाकर महीनों से जेलों में बन्द किया गया था। लेकिन सरकार को एक साधारण पुलिस कर्मी की जान की परवाह ही क्या थी? पहले तो पुलिस अधिकारियों ने यह बयान दिए कि वे अपने बलों को भेजकर सुरेश को छुड़ाएंगे। लेकिन उनकी कोशिश विफल होने के बाद बयान बदलकर उलटी-सीधी बातें करने लगे कि नक्सलवादियों के साथ सुरेश के सम्बन्ध रहे हैं और वह इसी सिलसिले में उनसे मिलने गया हुआ है। पुलिस अधिकारी सुरेश को छुड़ाने में कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए यह साबित करने की विफल कोशिश करते रहे कि अपहरण का यह मामला एक नाटक था। छापामारों की हिरासत में रहकर सुरेश ने इस सम्बन्ध में सारी खबरें रेडियो से सुनीं और अखबारों में पढ़ीं। धीरे-धीरे वह समझने लगा था कि वह जिस सरकार के लिए अब तक काम करता रहा वह उसे बचाने में कितनी लापरवाही बरत रही है। हिरासत के दौरान पीजीए सैनिकों ने सुरेश को क्रान्तिकारी राजनीति से अवगत कराया और पांच दिन बाद छोड़ दिया।

अपनी रिहाई के बाद सुरेश ने अखबारों में जो बयान दिया वह गौरतलब है। उसने कहा कि उसे सरकार पर विश्वास ही उठ चुका है और कि नक्सलवादी जिस लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं वह सही है। उसने आगे कहा कि नक्सलवादियों के आचरण के बारे में अधिकारियों ने अब तक उसे और उस जैसे पुलिस वालों को जो कुछ बताया है वह पूरी तरह गलत है। सुरेश ने बताया कि नक्सलवादी न तो चोर हैं न ही कोई गुण्डे हैं, बल्कि अनुशासित जिन्दगी जीने वाले जनता के सच्चे सेवक हैं।

इर कार्यवाही से पीजीए ने आम पुलिस कर्मियों में वर्गीय चेतना जगाने की दिशा में बहुत सीमित ही सही कामयाबी हासिल की। पुलिस कर्मी के पीजीए की हिरासत में रहने के दौरान और रिहाई के बाद सुरेश के बयानों से कुछेक पुलिस कर्मी तो सोच में जरूर पड़ गए होंगे कि सचाई क्या है। और इस घटनाक्रम से सरकार ने भी अपने अड़ियल बयानों से खुद को यह साबित किया कि वह दरअसल आम पुलिस कर्मियों के हितों की विरोधी है क्योंकि, जाहिर सी बात है, सुरेश की जगह कोई बड़ा अधिकारी, नेता या कोई मालदार आदमी होता तो सरकार का रवैया ऐसा न होता। ★

लगा तो इसे लगा कि इसके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है। इसलिए इसने जनता को यह धमकियां देना शुरू किया कि जो लोग छापामार दस्ते से मिलने जाएंगे उनके नाम वह पुलिस को दे देगा। स्थानीय पार्टी ने इसे इस सम्बन्ध में दो बार चेतावनी देकर सुधरने का मौका दिया। इसके बावजूद न तो इसने अपने भ्रष्ट आचरण को और न ही धमकियों को बन्द किया। इससे तंग आकर लोगों ने इसकी पिटाई करने का फैसला लिया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को पार्टी नेताओं ने समझाया कि सरकार के झूठे सुधार कार्यक्रमों से आखिर किन लोगों की जेबें भर रही हैं। सरपंच बापू ने अपनी गलतियों को लोगों के समक्ष स्वीकार करते हुए सुधरने का एक और मौका देने की गुजारिश की।

ट्रैक्टर जोताई की रेट कम करने के लिए संघर्ष

भामरागड तहसील के ताडिगांव रेंज में ट्रैक्टर मालिक जमीन जोतने के लिए प्रति घण्टा 300 रुपए लेते थे। लेकिन स्थानीय जनता ने माना कि यह रेट बहुत ज्यादा है, अतः इसे कम करने की जरूरत है। बाद में पार्टी की पहल पर वहां लोगों की एक कमेटी गठित की गई। भामरागड और ताडिगांव इलाकों की जनता ने एकजुट होकर ट्रैक्टर मालिकों से इस सम्बन्ध में चर्चा की। इस चर्चा में करीब 50 लोगों ने भाग लिया। जनता की एकजुटता को देखकर ट्रैक्टर मालिकों ने बात मान ली और रेट को 300 रुपए से 250 रुपए तक घटा दिया। इस संघर्ष से लोगों में यह विश्वास बढ़ गया कि संगठित शक्ति से वे अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं।

पुलिस मुखबिर बाबूराव तलांडे का खात्मा

गड़चिरोली डिवीजन के पेरिमिलि एरिया का एक गांव है जिंजिगांव। यहां का बाबूराव तलांडे एक धनी किसान था और गांव के लोगों से हमेशा यह दुश्मनी रखता था। जो भी उसके गलत व्यवहार के खिलाफ बोलेगा तो उसकी बाबूराव पिटाई कर देता था। इस तरह 5-6 लोगों को बाबूराव ने बेवजह पिटाई की। वर्ष 2001 में एक बार स्थानीय छापामार दस्ते ने उसे समझा-बुझा दिया था कि वह इस प्रकार के जन विरोधी काम करने से बाज आए। लेकिन वह नहीं सुधरा। उसके बाद वह पुलिस की दलाली करने लगा। जन संगठनों के बारे में और स्थानीय दस्ते के बारे में पुलिस को इत्तला दिया करता था। इसका विरोध करने वाले लोगों को वह डराया-धमकाया करता था।

मई 2003 में स्थानीय पार्टी ने पुलिस की मुखबिरी करने के जुर्म में इसकी पिटाई की थी और उसे सुधरने का एक और मौका दिया था। इसके बावजूद भी बाबूराव में कोई बदलाव नहीं आया। वह बराबर पुलिस मुखबिरी करता रहा। इस गांव में छापामार दस्ता जब भी जाता तो बाबूराव इसकी सूचना पुलिस को जरूर देता रहा। बाद में पुलिस वाले आकर लोगों को यह कहते हुए प्रताड़ित करते थे कि दस्ता तुम्हारे गांव आया था और तुम लोग उनसे मिले थे। इस सिलसिले में स्थानीय एरिया पार्टी कमेटी ने बाबूराव का सफाया करने का फैसला लिया। पीजीए के सैनिकों ने 1 दिसम्बर 2003 की रात को इसका खात्मा कर दिया। ★

इंद्रावती इलाके में मानवता की सारी हदें पार करता पुलिसिया आतंक

बुधरी और चैतू की हत्याओं से क्रान्तिकारी आन्दोलन रुकेगा नहीं !

चुनाव को 'शांतिपूर्ण' और 'निष्पक्ष' ढंग से सम्पन्न कराने की कीमत दो लोगों की जान हो सकती है, शायद इसकी कल्पना भैरमगढ़ तहसील के धर्मा और पल्ली गांव के लोगों ने कभी नहीं की होगी। उन्हें यह एहसास भी नहीं था कि भूख और भय से मुक्ति दिलाने का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार अपने पुलिस को भेजकर उनकी बहु-बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करवा सकती है। यह कोई दर्दनाक कहानी के अंश नहीं हैं, बल्कि दन्तेवाड़ा जिले के गांव धर्मा और छोटे पल्ली में लोकसभा चुनावों के समय हुई एक वास्तविक घटना से सम्बन्धित है। दन्तेवाड़ा जिले के भैरमगढ़ विकासखण्ड के अन्तर्गत बैल पंचायत में आते हैं ये दो गांव। इन गांवों के पास से बहती है इंद्रावती नदी जो अब सीआरपी वालों के वहशीपन व दरिन्दगी की साक्षी बन गई है। क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिहाज से यह इलाका माड़ डिवीजन के तहत इंद्रावती इलाका कहलाता है।

लोकसभा चुनावों के पहले ही दण्डकारण्य के संघर्ष इलाकों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के पुलिस बलों ने गश्त और खोजबीन अभियान तेज किए। बस्तर में सीआरपीएफ, पंजाब कमांडो, बीएसएफ, आदि बलों को हजारों की तादाद में तैनात किया गया। इन बलों ने स्थानीय पुलिस बलों से मिलकर लोगों में आतंक व दहशत फैलाना शुरू किया ताकि चुनाव बहिष्कार के आह्वान को विफल बनाया जा सके। इसी तरह भैरमगढ़ थाना पुलिस और सीआरपीएफ के 50 जवान 2 अप्रैल की आधी रात को इंद्रावति नदी पार करके पहले धर्मा गांव पर छापेमारी की। वहां पर एक जन संगठन नेता के घर पर हमला किया, लेकिन वह उस समय घर पर नहीं थे। रात के 3.30 बजे वे गांव की ओर आने वाले रास्ते पर घात लगाकर बैठ गए। उस समय मरकापाल मेले से लौट रही दो युवतियों और छह युवकों को उन्होंने गिरफ्तार किया। युवकों के हाथ बांधकर एक तरफ बिठा दिया और दो युवतियों को अलग ले गए। वहां जब उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की तो एक युवती किसी तरह भाग गई। लेकिन दूसरी युवती बुधरी पुलिस की दरिंदगी का शिकार बन गई। उसके साथ उन्होंने बारी-बारी से तब तक सामूहिक बलात्कार किया जब तक कि वह मर नहीं जाती। बाद में उसकी लाश पर उन्होंने एक गोली चलाई और हवा में सैकड़ों गोलियां दागीं। इसके साथ एक मुठभेड़ की कहानी तैयार हो गई। अगल दिन पुलिस ने भैरमगढ़ में पत्रकारों और डॉक्टरों को बुलाकर मुठभेड़ की सूचना दी और 'एक महिला नक्सली मारी गई' बताया। गौरतलब है कि पुलिस बुधरी की लाश भैरमगढ़ नहीं ले गई, बल्कि पल्ली के ग्रामीणों को सौम्प दी। पल्ली गांव बुधरी का माइका था और धर्मा ससुराल गांव। इस बलात्कार और हत्या की खबर सुनकर बुधरी के पिता विज्जाल धर्मा जाकर वहां रुके हुए पुलिस वालों को खूब गालियां दीं, क्योंकि इसके अलावा कुछ करने को अशक्त था वह बूढ़ा बाप।

4 अप्रैल को बुधरी की लाश को दफनाने के बाद पल्ली गांव का चैतू नामक एक किसान इन्द्रावती नदी में नहाने गया था। वह नहा-धोकर ज्यों ही तट पर आते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और यह कहते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी कि वह नदी में बारूदी सुरंग बिछाने गया था। उसे इतना भयानक ढंग से मारा जिसका वर्णन करना मुश्किल है। उसे पानी में डुबो-डुबोकर तब तक मारा जब तक कि चैतू बेहोश न होता। उसे जानवर की तरह एक डंडे में लटकाकर शाला भवन लाया और वहां फिर पिटाई शुरू की। पुलिस ने पत्थर पटका-पटकाकर इतनी बेरहमी से मारा कि उसने दम ही तोड़ दिया। दो व्यक्तियों की हत्या से भी इन खूंखार भेड़ियों की खून की प्यास नहीं बुझी। इन्होंने पास के झिल्ली गांव से जेमली और पाली नामक दो युवतियों को उठा लाया और शाला भवन में उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। और गांव के पटेल समेत कुछ लोग इस वहशीपन के प्रत्यक्ष साक्षी थे, उनके नजरों के सामने ही पुलिस ने इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया। बाद में इन दो युवतियों के साथ-साथ पल्ली गांव के मंगली और बुधराम तथा टाडुम गांव के एक व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके भैरमगढ़ ले गई। पुलिस द्वारा पीटे जाने से मंगलू का हाथ टूट गया।

पुलिस के इन घोर अत्याचारों के खिलाफ आसपास के गांवों की 1,000 जनता ने 6 अप्रैल को रैली के शक्ल में भैरमगढ़ जाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने उन्हें भैरमगढ़ पहुंचने से पहले ही रोक दिया और चैतू की लाश समेत गिरफ्तार लोगों को वहीं जनता के सुपुर्द किया। जनता को बन्दूकों से डराकर वहां से भगा दिया। इसके बावजूद लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। बाद में पुलिस ने यह घोषणा की कि चैतू की मौत दस्त लगने से हुई। इस बीच स्थानीय लोगों के कहने पर कुछ पत्रकारों ने इन घटनाओं के बारे में अखबारों में खबरें प्रकाशित कीं। कलेक्टर ने इस पर जांच का आदेश दिया। मुख्यमंत्री रमण सिंह को भी मजबूर होकर जांच का आदेश देना पड़ा। 17 मई से 25 मई के बीच दन्तेवाडा अदालत में चैतू के मामले पर सुनवाई हुई। इसके पहले ही पुलिस ने चैतू की पत्नी और भाई को पकड़ लिया और तीन दिन थाने में रखकर खुब डराया-धमकाया। घूस देने की कोशिश भी की। इससे उन्होंने सुनवाई में यह कबूल किया कि चैतू की मौत दस्त से हुई थी। जब जनता को यह मालूम हुआ तो इन दोनों मामलों की दोबारा सीबीआई से जांच करवाने की मांग उठाई। लोग अभी भी लड़ रहे हैं लेकिन पुलिस किसी भी तरह लोगों को दबाने की कोशिश में है। वर्तमान न्याय व्यवस्था के चरित्र को देखकर यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि इस कानून लड़ाई में जीत पुलिस की ही होगी, जनता

(शेष पृष्ठ 24 पर....)

गोण्डी रिपोर्टकु

जन जागरण मेळावा मुखियालोरकु सजा

गड़चिरोली जिला भामरागड़ तहसील ते नीरे अप्रैल-मई महीना लोप्पो उचवुर नेतालोर मेळावा लोप्पो शामिल आसि जनता तुकु विरुद्ध नित्तोर। आकिना रेट साटी मीटिंग इंजि जनता तुन नाडे कीसि सरकारी योजनांग पाइजे इंजि, तड़ाई-बोड्डी गावालिंजि, सुवा-घरकूल गावालिंजि, मेडपल्ली पुलिया गावालिंजि वडकतोर। इद्रमतोर मुखियालोरिकिन जनता, पीजीए तोर मिलेमासि सजा हीत्तोर।

सितम्बर 2003 ते इरपानार ते चैतू वड्डे, कलमसाय, बाबूराव; कुच्चेर ते गंगाराम कोठारेनु; कुकामेट्टा सरपंचनु; पिट्टेकस्सा सोमानु ओसो उचुवुर किना पोरो कार्यवाही कीत्तोर। वीरु सब्बेटोर संगठन तुक विरोध मंजि पुलिस तुक मदद हींदुर। अदिनके वीरा लोप्पो उचुवुर कुन पिटाई कीत्तोर, ओसो उचुवुरकिन चेतावनी हीत्तोर। अद्रमे दलम ते भर्ती आसि मंजि पेरिक लोन वितिसि पुलिस तुक मदद हीवल परेनार तोर दौलत ओसो महकापाड तोर कोमटी नु वेने जनता अलस्तोर।

ईदूर नाटेनोर बदमाश मालू डोलतोर

गड़चिरोली डिवीजन ता भामरागड इलाका ता ईदूर नाटेनोर मालू पुलिस मुखबिर आसि नीरे (2003) ते पीजीए कैदे डोलतोर। दीनकु मुन्ने इदे नाटेनोर आलम पाण्डू कमाण्डो तगा भर्ती आसि दरोगा पद ते मत्तोर। वोर नालवुर लोकुरकु नकली मुठभेड़ ते हौक्तोर। बचोनो मानवन गुमसतोर आणि दलमतोरिन वेने मुठभेड़ कीसि हौक्तोर। पय्या 1997ते वोनु छापामारलोर ऐम्बुश ते हौक्तोर। दाना पेरिकि इदु नाटे संगठन ता कामकाज ताक्सोरे मंदु। मति इदु नडुम मालु तिम्मा इंदनोर पुलिस तोरा पैसा ना लालच ते मुखबिर बनेमातोर। नीरे उंदि दिव्या ऐवुर छापामार दलम सदस्यीर इदु नाटे हत्तास्के वीरु पुलिस तुकु कबुरु हीतोर। 50-60 पुलिसतोर वासि दलम पोर्रो पक्का फायरिंग कीत्तोर। पुलिसतोर संगे लड़ेमासोरे छापामारलोर रिट्रीट आतोर। बोनके नुकसान आयो मति छापामारलोरा मूंड्डु किटकु, उंदि 12 बोर तुपाय हत्तांग। दाना पय्या दलमतोर ओसो जनता जांच कीत्तास्के पुलिस तुकु कबुरु हीत्तोर मालु आंदुर इंजि समझेमात्ता। 23 अगस्त 2003 ता दिव्या पीजीए सैनिकलोर वोनकु अरेस्ट कीसि हौक्सीत्तोर।

मेळावा ता पेरिके चुगिलितोरा पोरो आणि जन विरोधी नेतालोरा पोर्रो जनता ना प्रतिरोध-अभियान

गड़चिरोली एसपी राजवर्धन नक्सलवादीरकु गांवबंदी कीयाना इंजि पक्का प्रचार कीसोरे जन जागरण मेळावा ता नाटक लगातार कीसोरे मंतोर। वीरु नार-नार मीटिंग कीसि पैसा ना लालच तोह्चि लेविकि रेयपि कीसि पार्टी तुकु खिलाफ उचुवुर किन तैयार कीसोरे मंतोर। इदु अभियान ता पेरिके पार्टी ता नेतृत्व ते जनता वीरा विरोध ते उंदि प्रतिरोध अभियान ताकि कीत्ता। जनता कु विरोध आसि नितोरिकिन रंग-रंगना सजा कीता।

कुचेर तोर गंगाराम कोठारे – वीना दादाल देवराव मुन्ने मावा पार्टी ते दल कमाण्डर मंदूर। तन कमजोरी तल वोर दलम तल हंजि सरेंडर आतोर। अस्के गंगाराम वोनु पुलिस तगा सरेंडर कीत्तोर। पेरिकि संदेहास्पद परिस्थिति ते वोर फांसी आसि डोलतोर। अस्केटाल गंगाराम पुलिसतोरा संगे गोति आसि मंदूर। पुलिस तगा पैसा एतसोरे चुगली कींदुर। जन जागरण मेळावा लोप्पो शामिल आसि पुलिस अधिकारीलोरा संगे क्रान्ति तुकु खिलाफ भाषण हींदुर। अदिनकु वीनु सितम्बर 2003 ते पीजीए ता नेतृत्व ते जनता पिटाई कीत्तोर।

इरपानार तोरु मुवुर वेने पुलिस तोरा संगे मिलेमासि मेळावा ते भाषण हीत्तोर। पार्टी तुकु, क्रान्ति तुकु विरुद्ध वडकतोर। वीरिकिन चेतावनी हीसि विड्सतोर। राननिपोडूर तोर वेने वरोर अद्रमे नाटे पुलिस वातस्के मदद कीयना, हर्री तोहना कीसोर मत्तोर। वोनकु वेने पिटाई कीसि विड्सतोर। इद्रम पुलिसतोरा मेळावा तुकु विरुद्ध पार्टी वेने विरोधी अभियान ताकि कीत्तांकु जनता लोप्पो उत्साह बेरस्ता।✶

(.... पृष्ठ 23 का शेष)

हार जाएगी।

आखिर जनता पर यह जुल्म और अत्याचार क्यों? क्योंकि आज दण्डकारण्य की जनता हमारी पार्टी की अगुवाई में वर्तमान लुटेरी व्यवस्था को ध्वस्त करके एक शोषणविहीन व सच्ची जनवादी व्यवस्था कायम करने के लिए लड़ रही है। वर्तमान व्यवस्था के तहत चलने वाले चुनावों को जनता एक ढकोसला मानते हुए उनका बहिष्कार कर रही है। साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और दलाल नौकरशाही पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंककर मजदूर-किसान एकता की बुनियाद पर तमाम शोषित वर्गों की साझी हुकूमत कायम करने के लिए नव जनवादी क्रान्ति लाने को दण्डकारण्य जनता कमर कस चुकी है। लुटेरे शासक इस आन्दोलन का जड़ से मिटाने के मकसद से पूरे दण्डकारण्य को पुलिस व अर्ध सैनिक बलों की छावनी में बदल रहे हैं। ये भाड़े के सैनिक पीजीए के योद्धाओं से सीधी टक्कर से आम तौर पर बचते हुए आम जनता पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। आम लोगों मारकर मुठभेड़ की कहानियां गढ़ रहे हैं। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और मारपीट कर रहे हैं। इस तरह जनता को आतंकित करके उसे क्रान्तिकारी आन्दोलन से अलग करने की सोची-समझी साजिश के तहत ही वे ऐसे घिनौने कारनामे कर रहे हैं। जनता के जायज आन्दोलनों के दमन में महिलाओं के साथ बलात्कार को एक औजार के बतौर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि दमन हर बार प्रतिरोध को ही जन्म देता है। हत्यारे और बलात्कारी जन अदालत में सजा से नहीं बच पाएंगे। हम इन दो मृत कॉमरेडों के परिवार जनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और जनता का आह्वान करते हैं कि जनयुद्ध को तेज करके इन कॉमरेडों की हत्याओं का बदला ले। ✶

"देहातों की जांच-पड़ताल" की प्रस्तावना

17 मार्च 1941

पार्टी की मौजूदा ग्रामीण नीति इस समय भूमि-क्रान्ति की नीति नहीं है जैसी कि वह दस वर्ष के गृहयुध्द के दौरान थी, बल्कि आज वह जापान-विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का निर्माण करने की ग्रमीण नीति है। समूची पार्टी को चाहिए कि वह 7 जुलाई और 25 दिसम्बर 1940 के केन्द्रीय कमेटी के निर्देशों और आगामी सातवीं राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशों पर अमल करे। कामरेडों को समस्याओं का अध्ययन करने का तरीका निकालने में मदद देने के उद्देश्य से निम्नलिखित सामग्री प्रकाशित की जा रही है। हमारे बहुत से कामरेडों का काम करने का ढंग अब भी अपरिपक्व और लापरवाहीपूर्ण है, वे चीजों को अच्छी तरह समझने की कोशिश नहीं करते और यहां तक कि वे नीचे के स्तर की परिस्थितियों से बिलकुल अनभिज्ञ हैं, परन्तु फिर भी वे कार्य-संचालन की जिम्मेदारी सम्भाले हुए हैं। यह एक अत्यन्त ही खतरनाक स्थिति है। चीनी समाज में विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थितियों के बारे में सही मायनों में ठोस ज्ञान हासिल किए बिना कोई भी नेतृत्व सचमुच अच्छा नहीं हो सकता।

परिस्थिति की जानकारी प्राप्त करने का एममात्र तरीका यह है कि सामाजिक जांच-पड़ताल की जाए, हर सामाजिक वर्ग के वास्तविक जीवन की परिस्थिति की जांच-पड़ताल की जाए। जिन लोगों के कन्धों पर कार्य-संचालन की जिम्मेदारी है, उनके लिए परिस्थिति की जानकारी प्राप्त करने का बुनियादी तरीका यह है कि वे एक योजना के मुताबिक चन्द शहरों और देहातों में अपना ध्यान केन्द्रित करके मार्क्सवाद के बुनियादी दृष्टिकोण को, यानी वर्ग-विश्लेषण के तरीके को इस्तेमाल करते हुए कई बार पूरी जांच-पड़ताल करें। सिर्फ इसी तरह हम चीन की सामाजिक समस्याओं के बारे में सर्वाधिक प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए पहले नीचे देखना चाहिए, अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ ही नहीं देखना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति नीचे देखने में दिलचस्पी नहीं रखता और ऐसा करने के लिए संकल्पबद्ध नहीं रहता, तब तक बह जिन्दगीभर चीन की हालत सही मायनों में नहीं समझ सकता।

दूसरे, जांच-पड़ताल मीटिंगें करनी चाहिए। निश्चय ही, सिर्फ इधर-उधर नजर घुमाने और सुनी-सुनाई बातों से किसी चीज के बारे में सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। हुनान प्रान्त और चिङकाङशान से सम्बन्धित जो सामग्री मैंने जांच-पड़ताल मीटिंगों के जरिए प्राप्त की थी, वह खो गई है। यहां जो सामग्री प्रकाशित की गई है। वह मुख्यतया "शिङक्वो की जांच-पड़ताल" "छाङकाङ श्याङ की जांच-पड़ताल" की सामग्री है। जांच-पड़ताल मीटिंगें करना सबसे आसान, सबसे अधिक व्यावहारिक और सबसे अधिक विश्वसनीय तरीका है जिससे मैंने बहुत लाभ उठाया है; यह किसी भी विश्वविद्यालय से बेहतर विद्यालय है। इन मीटिंगों में भाग लेने वाले लोग मध्यम या निम्न रैंकों के सही मायनों में अनुभवी कार्यकर्ता, अथवा साधारण लोग होने चाहिए। हुनान प्रान्त की पांच काउन्टियों और चिङकाङशान की दो काउन्टियों की जांच-पड़ताल के दौरान मैं प्रत्येक काउन्टी के मध्यम रैंक के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मिला : शयुनऊ की जांच-पड़ताल के समय मैं मध्यम और निम्न रैंकों के कुछ कार्यकर्ताओं, एक गरीब श्यूछाए, एक व्यापारी संघ के दिवालिया भूतपूर्व प्रेसिडेन्ट, और काउन्टी की मालगुजारी वसूल करने के काम के इनचार्ज एक सेवाच्युत छोटे क्लर्क से मिला। इन सभी लोगों ने मुझे बहुत सी एसी बातें बताईं जो मैंने इसके पहले कभी नहीं सुनी थीं। जिस आदमी ने पहली बार मेरे सामने चीनी जेलों की गिरी हुई हालत की पूरी तस्वीर रखी वह एक साधारण जेलर था जिससे मेरी मुलाकात

माओ की संकलित रचनाओं के दूसरे और तीसरे भागों से हम ये दो लेख प्रस्तुत कर रहे हैं। आज दण्डकारण्य आन्दोलन जनता की राजसत्ता कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, यह हम सभी जानते हैं। इस पृष्ठभूमि में कई पार्टी कार्यकर्ता गांवों में वर्ग विश्लेषण करने में लगे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि प्रस्तुत लेख "देहातों की जांच-पड़ताल" की प्रस्तावना इन कॉमरेडों के लिए उपयोगी हो सकता है। मई 2004 में हमारी दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने निर्णय लिया कि आने वाले महीनों में सभी क्षेत्रों में संगठन का सुदृढ़ीकरण अभियान चलाया जाए। इस पृष्ठभूमि में हम माओ का "कार्यकर्ता सम्बन्धी नीति" लेख प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इस अभियान में उपयोगी हो सके।

– सम्पादकमणमडल

हुनान प्रान्त की डङशान काउन्टी की जांच-पड़ताल के दौरान हुई थी। शिङक्वो काउन्टी और छाङकाङ व छाएशी श्याङों की अपनी जांच-पड़ताल के दौरान मैं श्याङ के स्तर पर काम करने वाले कामरेडों और साधारण किसानों से मिला। ये कार्यकर्ता, किसान, श्यूछाए, जेलर, व्यापारी और मालगुजारी-क्लर्क सभी मेरे आदरणीय शिक्षक थे और उनके शिष्य के रूप में मुझे उनके प्रति बड़ा सम्मानजनक, मेहनती तथा कामरेडों जैसा रवैया अपनाना पड़ता था; अन्यथा वे मेरी तरफ ध्यान न देते, और जानकारी रखते हुए भी वे मुझे न बताते, या अगर बताते भी तो पूरी तरह से नहीं बताते। जांच-पड़ताल के लिए ज्यादा बड़ी मीटिंगें करने की जरूरत नहीं है; तीन से पांच या सात अथवा आठ लोगों की मीटिंगें काफी हैं। इसमें काफी समय लगाना चाहिए और जांच-पड़ताल के लिए एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए : यही नहीं, हमें खुद भी सवाल पूछने चाहिए, जो कुछ बताया जाए उसे नोट करना चाहिए, और मीटिंग में मौजूद लोगों के साथ विचार-विनिमय करना चाहिए। इसलिए यह बात निश्चित है कि हम तब तक जांच-पड़ताल नहीं कर सकते या अच्छी तरह से नहीं कर सकते, जब तक हमारे अन्दर उत्साह पैदा नहीं हो जाता, अपनी नजर नीचे की तरफ रखने का संकल्प पैदा नहीं हो जाता और ज्ञान-पिपासा पैदा नहीं हो जाती, तथा जब तक हम मिथ्याभिमान का लबादा उतारकर एक जिज्ञासु शिष्य नहीं बन जाते। यह समझ लेना जरूरी है कि जन-समुदाय ही सच्चे वीर होते हैं, जबकि हम खुद अक्सर बड़े बचकाने और अनजान साबित होते हैं: इस बात को समझे बिना अत्यन्त प्रारम्भिक किस्म का ज्ञान प्राप्त करना भी असम्भव है।

मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि इस सन्दर्भ-सामग्री को प्रकाशित करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है निम्न स्तर पर मौजूद हालतों का पता लगाने के लिए एक तरीका बतलाना; इसका उद्देश्य यह नहीं है कि साथी लोग विशिष्ट सामग्री और उससे निकाले गए नतीजों को कंठस्थ कर लें। सामान्य तौर पर, चीन का शिशु पूंजीपति वर्ग सामाजिक परिस्थितियों के बारे में न तो अभी तक कोई अपेक्षाकृत सांगोपांग या यहां तक कि कोई प्रारम्भिक सामग्री पेश कर सका है और न ही कभी कर पाएगा, जैसा कि योरप अमरीका और जापान के पूंजीपति वर्ग ने किया है; इसलिए हमारे पास सामाजिक परिस्थितियों के बारे में खुद ही सामग्री जुटाने के अलावा और कोई चारा नहीं हैं। खास तौर पर, व्यावहारिक काम करने वाले लोगों को चाहिए कि वे बदलती हुई परिस्थिति की जानकारी हमेशा हासिल करते रहें, और यह एक ऐसा काम है जिसके लिए किसी भी देश की कम्युनिस्ट पार्टी दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकती। इसलिए, व्यावहारिक काम करने वाले हर व्यक्ति को नीचे के स्तर में जाकर स्थितियों की जांच-पड़ताल करनी चाहिए। इस प्रकार की जांच-पड़ताल करना खास तौर पर उन लोगों के लिए जरूरी जो सिद्धान्त को तो जानते हैं लेकिन वास्तविक स्थितियों को नहीं जानते, क्योंकि इसके बिना वे सिद्धान्त को व्यवहार के साथ नहीं मिला पाएंगे। हालांकि मेरे इस कथन को कि "बिना जांच-पड़ताल किए किसी को बोलने का हक नहीं है", "संकीर्ण अनुभववाद" का नाम देकर उसकी खिल्ली उड़ाई गई है, फिर भी आज तक मुझे अपने इस कथन पर जरा भी अफसोस नहीं; अफसोस करना तो दूर रहा, उल्टे मैं आज भी यह बात डंके की चोट पर कहता हूं कि जिसने जांच-पड़ताल न की हो, उसे बोलने का हक कतई हासिल नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो करने लगते हैं तो किसी चीज की निन्दा; लेकिन दरअसल ऐसे सभी लोगों को असफलता का मुंह देखना पड़ता है। क्योंकि जो विचार और जो आलोचनाएं पूरी जांच-पड़ताल पर आधारित नहीं हैं, वे महज फिजूल की बकवास हैं। इन "शाही दूतों" की मेहरबानी से, जो जहां-तहां दौड़ते फिरते हैं, हमारी पार्टी को अनगिनत मौकों पर नुकसान उठाना पड़ा है। स्तालिन ने ठीक ही कहा है, "सिद्धान्त को यदि क्रान्तिकारी व्यवहार से न मिलाया जाए तो वह निरुद्देश्य साबित होता है।" उन्होंने आगे कहा है और ठीक ही कहा है, "अगर हमारे व्यवहार का रास्ता क्रान्तिकारी सिद्धान्त के जरिए रोशन नहीं किया जाएगा, तो हमारा व्यवहार अंधेरे में भटकता रहेगा।" किसी भी व्यक्ति पर "संकीर्ण अनुभववादी" का लेबिल नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ उस "व्यावहारिक व्यक्ति" को छोड़कर, जो अंधेरे में भटकता रहता है तथा दिशाज्ञान और दूरदर्शिता नहीं रखता।

आज भी मैं इस बात की सख्त जरूरत महसूस करता हूं कि मैं चीन तथा विश्व के मामलों के बारे में पूरी तरह छान-बीन करूं; इसका सम्बन्ध चीनी मामलों तथा विश्व मामलों के बारे में मेरे खुद के ज्ञान की कमी से है और इसका मतलब यह नहीं हैं कि मैं हर चीज जानता हूं और दूसरे लोग अनभिज्ञ हैं। यह मेरी आकांक्षा है कि मैं शिष्य बना रहूं, और दूसरे पार्टी-कामरेडों के साथ मिलकर जन-समुदाय से सीखता रहूं। ★

कार्यकर्ता सम्बन्धी नीति

(.... पृष्ठ 27 का शेष)

चौथे, जिन कार्यकर्ताओं ने गलतियां की हैं उनके प्रति सामान्यतया समझाने-बुझाने का तरीका अपनाना चाहिए, तथा उन्हें अपनी गलतियां सुधारने में मदद देनी चाहिए। संघर्ष का तरीका केवल उन्हीं के प्रति अपनाया जाना चाहिए जो गम्भीर गलतियां करने के बाद भी निर्देशन का पालन करने से इनकार करते हैं। इस सम्बन्ध में धीरज से काम लेना निहायत जरूरी है। लोगों पर बिना सोचे-समझे "अवसरवादी" का बिल्ला लगा देना तथा उनके खिलाफ बिना सोचे-समझे "संघर्ष चलाना" गलत है।

पांचवे, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में मदद करनी चाहिए। जब कभी कार्यकर्ता लोग बीमारी, तंगी अथवा घरेलू या अन्य मुश्किलों की वजह से परेशान हों, तो हमें उनकी यथासम्भव अधिक देखभाल करनी चाहिए।

कार्यकर्ताओं की अच्छी तरह देखभाल करने का यही तरीका है। ★

कॉमरेड माओ की रचनाओं से

कार्यकर्ता सम्बन्धी नीति

अक्टूबर 1938

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दसियों करोड़ लोगों वाले एक महान राष्ट्र में महान क्रान्तिकारी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी है। योग्यता और नैतिकता से लैस नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या के बिना वह अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा नहीं कर सकती। पिछले सत्रह वर्षों में हमारी पार्टी ने अनेक सुयोग्य नेताओं को प्रशिक्षित किया है जो फौजी, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में तथा पार्टी-कार्य और जन-आन्दोलनों में हमारा मेरुदण्ड हैं; इस सफलता का समस्त गौरव पार्टी और पूरे राष्ट्र को है। लेकिन हमारा मौजूदा मेरुदण्ड इतना मजबूत नहीं है जो संघर्ष के विशाल भवन को सहारा दे सके, और अब भी बड़े पैमाने पर सुयोग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। चीनी जनता के महान संघर्ष में अनेक सक्रिय व्यक्ति सामने आए हैं और लगातार आते जा रहे हैं। उन्हें संगठित करने, उनको प्रशिक्षित करने, उनकी अच्छी तरह देखभाल करने तथा उनका उचित उपयोग करने का उत्तरदायित्व हम पर ही है। जहां एक बार राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारित कर दी गई, तो कार्यकर्ता एक निर्णयात्मक तत्व बन जाते हैं। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से नए कार्यकर्ताओं की विशाल संख्या को प्रशिक्षित करना हमारा जुझारू कार्य है।

हमें केवल पार्टी-कार्यकर्ताओं का ही नहीं बल्कि गैरपार्टी कार्यरक्ताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। पार्टी के बाहर अनेक सुयोग्य व्यक्ति हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को उन्हें नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए। हर कम्युनिस्ट का यह कर्तव्य है कि वह अलगाव और हेकड़ी से दूर रहे तथा गैरपार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अच्छी तरह मिलजुलकर काम करे, उनकी सच्चे दिल से सहायता करे, उनके प्रति स्नेहपूर्ण साथियों जैसा बरताव करे तथा जापान का प्रतिरोध करने और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण करने के महान कार्य में उनकी पहलकदमी का उपयोग करे।

हमें मालूम होना चाहिए कि कार्यकर्ताओं को कैसे पहचाना जाए। हमें किसी कार्यकर्ता की जिन्दगी के थोड़े से अरसे अथवा उसकी जिन्दगी की किसी एक घटना के आधार पर ही उसके बारे में अपनी राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए, बल्कि उसकी जिन्दगी और उसके काम को समूचे रूप में आंकना चाहिए। यह कार्यकर्ताओं को पहचानने का मुख्य तरीका है।

हमें यह मालूम होना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का अच्छी तरह कैसे उपयोग किया जाए। अन्ततोगत्वा नेतृत्व पर ये दो मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं : उपायों को खोज निकालना और कार्यकर्ताओं का अच्छी तरह उपयोग करना। योजना बनाना, निर्णय करना तथा आदेश और हिदायतें देना, आदि सभी बातें "उपायों को खोज निकालने" की श्रेणी में आती हैं। इन उपायों को अमल में लाने के लिए हमें कार्यकर्ताओं को एकताबद्ध करना चाहिए और उन्हें अमल में मैदान में उतरने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए; यह "कार्यकर्ताओं के उपयोग करने" की श्रेणी में आता है। कार्यकर्ताओं के उपयोग के सम्बन्ध में हमारे राष्ट्रीय इतिहास में दो विरोधी कार्यदिशाएं रही हैं, पहली है "नैतिकता और योग्यता के आधार पर नियुक्ति करना" और दूसरी है "पक्षपात द्वारा नियुक्ति करना"। पहली कार्यदिशा ईमानदारी की है और दूसरी बेईमानी की। कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकर्ता सम्बन्धी नीति में कार्यकर्ताओं को परखने की कसौटी यह होनी चाहिए कि क्या कार्यकर्ता पार्टी की कार्यदिशा को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित करते हैं अथवा नहीं, पार्टी-अनुशासन का पालन करते हैं अथवा नहीं, जन-समुदाय से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं अथवा नहीं, स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता रखते हैं अथवा नहीं, तथा सक्रिय, परिश्रमी और निस्वार्थ व्यक्ति है अथवा नहीं। इसी का मतलब है "नैतिकता और योग्यता के आधार पर नियुक्ति करना"। चाङ क्वो-थाओ की कार्यकर्ता सम्बन्धी नीति इससे ठीक उल्टी थी। "पक्षपात द्वारा नियुक्ति करने" की नीति पर चलकर उसने अपने आसपास अपने निजी कृपापात्रों को जमा करके एक छोटा-सा गुट बना लिया, और अन्त में उसने पार्टी के साथ गद्दारी कर दी और भाग खड़ा हुआ। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। इससे और इसी तरह के ऐतिहासिक सबकों से चेतावनी लेकर कार्यकर्ता सम्बन्धी नीति में केन्द्रीय कमेटी को और हर स्तर के नेताओं को ईमानदारी और न्यायोचित व्यवहार पर दृढ़ता के साथ चलने तथा बेईमानी और अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध करने को अपनी प्रमुख जिम्मेदारी बना लेना चाहिए, ताकि पार्टी का एकीकरण व उसकी एकता मजबूत हो सकें।

हमें यह मालूम होना चाहिए कि कार्यकर्ताओं की अच्छी तरह देखभाल कैसे की जाए। इसके कई तरीके हैं।

पहले, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपना काम स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए ताकि उनमें जिम्मेदारी उठाने का साहस पैदा हो जाए, तथा साथ ही उन्हें उचित समय पर हिदायतें भी देनी चाहिए ताकि पार्टी की राजनीतिक कार्यदिशा के मार्गदर्शन में वे अपनी पहलकदमी का पूरा-पूरा इस्तेमाल कर सकें।

दूसरे, उनका स्तर उन्नत करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें अध्ययन करने का मौका देकर शिक्षित करना चाहिए, ताकि वे अपनी सैद्धान्तिक जानकारी और कार्य-क्षमता को बढ़ा सकें।

तीसरे, उनके काम की जांच-पड़ताल करनी चाहिए, तथा अपने अनुभवों का निचोड़ निकालने, अपनी उपलब्धियों का विकास करने और गलतियों को सुधारने में उनकी सहायता करनी चाहिए। केवल काम सौंपते जाना और उसकी जांच-पड़ताल न करना, तथा जब गम्भीर गलतियां की जाएं सिर्फ तभी उनकी ओर ध्यान देना – यह कार्यकर्ताओं की देखभाल करने का तरीका नहीं है।

(शेष पृष्ठ 26 पर....)

झारखण्ड में पीएलजीए के लाल योद्धाओं का बहादुराना कारनामा

सारन्डा ऐम्बुश और भाजपा की बौखलाहट

झारखण्ड के मुख्यमंत्री ने फासीवादी आडवाणी की रथयात्रा के झारखण्ड में प्रवेश के भारी-भरकम स्वागत की तैयारी कर रखी थी। लेकिन रथ के प्रवेश के ठीक एक दिन पहले माओवादियों ने पश्चिम सिंगभूम के सारन्डा के घने जंगलों में एक जबर्दस्त बारूदीसुरंग का विस्फोट करके 27 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया और 30 अन्य को बुरी तरह घायल किया। भारत के माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र के पीएलजीए बलों के द्वारा अंजाम दिए गए इस ताकतवर हमले से झारखण्ड पुलिस थरथराई। रथयात्रा को छोड़कर मुख्यमंत्री ने आनन-फानन में घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस का मनोबल बढ़ाने की असफल कोशिश की। इस ऐम्बुश में कुख्यात पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार, जो नक्सल विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहा था, गंभीर रूप से घायल हुआ। मरने वालों में सीआरपीएफ के 152वें बटालियन का उपनिरीक्षक और नुआमुण्डी पुलिस थाने के टीआई भी शामिल थे।

माओवादियों के आवागमन की खबर पाकर एसपी प्रवीण कुमार 120 पुलिस जवान एवं 90 सीआरपीएफ जवानों का अमला लेकर गश्त अभियान पर निकला था। 6 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक गांवों पर हमला करके गांव वालों की पिटाई करके माओवादियों को पकड़ने में असफल होकर 12 वाहनों के काफिला लौट रहा था। ठीक शाम 5-30 बजे गुवा-बलीबा सड़क से ढाई किलोमीटर दूर पर एक भयानक विस्फोट हुआ जिसे छापामारों ने अंजाम दिया। पुलिस काफिला अपना मार्ग बदलने ही वाला था कि जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद लगातार दौ और धमाके हुए। पहले धमाके में एसपी के सुरक्षा वाहन ध्वस्त हुआ। दूसरे धमाके में एक और वाहन के परखचे उड़ गए जिसमें नूवामुण्डी का टीआई बैठा था। तीसरे धमाके में एक और वाहन का बोनेट उड़ गया। इन धमाकों में एसपी की गाड़ी में आग लग गई। आंतक का पर्याय बना एसपी प्रवीण कुमार इस हमले में अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। धमाकों के बाद छापामारों ने पुलिस काफिले पर गोलीबारी की। एसपी प्रवीण कुमार अपने सिपाहियों को उनके हाल पर छोड़कर खुद की जान बचाने में लगा रहा। गोलीबारी में घायल एसपी छीपते-भागते तीन घण्टे पैदल चलकर बाद में साइकिल के सहारे कारमपाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां से माल गाड़ी में कूदकर किरीबुरू पहुंचा। पूरे 6 घण्टे पागल की तरह भाग-दौड़ करके आखिर एसपी ने अपनी जान बचाई। यह वही एसपी था जिसने सैकड़ों ग्रामीणों को यातनाएं दी थीं तथा कई माओवादियों एवं उनके समर्थकों की हत्या की। शासक वर्गों का पालतू कुत्ता प्रवीण कुमार के 6 घण्टे की फरारी के दौरान उसके सिर पर मंडराती मौत से वह इस कदर घबराया था कि किसी गांव में रुका तक नहीं। हर पल वह इस आशंका से पीड़ित था कि गांव के लोग उसे पकड़कर छापामारों के हवाले कर देंगे।

इस साहसिक हमले में माओवादियों ने पुलिस से 40 हथियार एवं बड़ी मात्रा में गोलाबारूद जब्त किया। सारन्डा के जंगलों में यह एमसीसीआई द्वारा किया गया पहला हमला नहीं था। इसके पूर्व 19 दिसम्बर 2002 को छापामारों ने उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के सरहदी जंगल में स्थित बिटकिल सोया गांव के नजदीक 19 पुलिस वालों को उड़ा दिया था।

880 वर्ग किलोमीटर का सारन्डा का घना जंगल एमसीसीआई का प्रभुत्व वाला क्षेत्र है जहां उसने जमींदारों, वन विभाग के अधिकारियों एवं व्यापारियों की लूट के खिलाफ लोगों को लामबन्द किया था और मजबूत जन समर्थन हासिल किया। प्रवीण कुमार जब पश्चिम सिंगभूम का एसपी बना, उसने यह दंभ भरा कि सारन्डा के जंगल को वह नक्सलियों से मुक्त कराएगा। साथ ही, उसने इस इलाके में आतंक मचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज वह अस्पताल में पड़ा है और उसकी हिम्मत की सारी हवा निकल गई। वह शासक वर्गों का भरोसेमन्द कुत्ता था जो इस बात से साबित होती है कि उसे टाटा के निजी हवाई जहाज से ले जाकर कोलकाता के बड़े अस्पताल में दाखिल किया गया।

इस बीच आड़वाणी की रथयात्रा को लेकर भाजपा सहम सी गई थी। वह जल्द से जल्द रथ यात्रा को झारखण्ड से विदा करना चाहती थी। रथयात्रा कोडरमा के पास झारखण्ड में प्रवेश किया और एक ही दिन में वह झारखण्ड पार करके छत्तीसगढ़ में घुस गया। मेघातराई से कोडरमा और वहां से झुमरीतलैया तक 30 किलोमीटर के इलाके को रथयात्रा के दौरान सैनिक छावनी में तब्दील किया गया था। हर पुल एवं पुलिया की सुरक्षा करते हुए हजारों की संख्या में राज्य के सशस्त्र बलों एवं अर्ध सैनिक बलों के द्वारा दी गई फहरेदारी में रथयात्रा झारखण्ड से गुजरी। एक पार्टी विशेष के एक व्यक्ति के चुनाव प्रचार में एक दिन करोड़ों का जन धन पानी की तरह बहाया गया।

जब तक जनता खामोश है, तब तक फासीवादी भाजपा सरकार एवं उसकी पुलिस आक्रामक बनी रहेगी एवं दहशत फैलाएगी। एक बार जनता अपनी खोमोशी तोड़ेगी एवं विद्रोह पर उतारू हो जाएगी, ये सभी अपनी जान बचाने चूहों की तरह भागेंगे। भाजपा के फासीवाद एवं राज्य हिंसा के आतंकी गठजोड़ का मुकाबला सिर्फ आन्दोलनरत जनता अपने सशस्त्र बलों के द्वारा ही कर सकती है एवं उसे परास्त कर सकती है। यदि गुजरात में इस तरह की ताकत होती, तो वहां भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंगदल 2000 से ज्यादा मुसलमानों के कत्लेआम, बलात्कार, लूट एवं आगजनी जैसी घिनौनी एवं जघन्य कारनामों को अंजाम देने की कभी हिम्मत नहीं कर सकते थे।★

हैती पर अमेरिकी कब्जे का विरोध करो

वह प्रचार माध्यमों द्वारा फैलाया गया एक और झूठ था। अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार माध्यमों ने उसे सरकार के खिलाफ विद्रोहियों के सशस्त्र संघर्ष के रूप में पेश किया। दरअसल, वहां अमेरिकी दूतावास के द्वारा सैनिक तख्तापलट की कार्यवाही को अंजाम दिया गया था।

हैती के दो सौ साल के इतिहास में पहली बार 1994 में जॉन बेरट्रैन्ड आस्ट्राइड अध्यक्ष चुने गए थे। वह लिबरेशन थियोलोजी से प्रभावित एक कैथोलिक पादरी थे। सन् 2000 में 90 प्रतिशत से अधिक वोटों से वे दोबारा निर्वाचित हुए। हैती एक छोटा सा देश है। हिस्पानियोना नामक द्वीप का आधा हिस्सा और डोमेनिकन गणराज्य का आधा हिस्सा मिलकर यह देश बना था। पश्चिमी गोलार्ध में सबसे गरीब देश यही है। पूरे विश्व में चौथा गरीब देश है। इसकी साक्षरता दर सिर्फ 50 प्रतिशत है।

जबसे जार्ज बुश सत्ता में आया तबसे वह हैती के पुराने एवं बर्बर शासक डुवेलियर के सशस्त्र दस्तों का लालन-पालन कर रहा है। भूतपूर्व सैनिक तथा पुलिस अधिकारियों, पेशेवर हत्यारों और आपराधिक गुटों को सीआईए ने अमेरिका एवं डोमेनिकन रिपब्लिक में प्रशिक्षण दिया था। ये सभी 1994 में जब आस्ट्राइड सत्ता में आया था हैती से भाग खड़े हुए थे। इन सभी को एलसाल्वेडार के कान्ट्राओं की तर्ज पर प्रशिक्षित किया गया।

अमेरिकी आधुनिक हथियारों से लाइस ये सशस्त्र 'दस्ते' फरवरी के शुरूआत में हैती में घुस गए। पश्चिमी मीडिया में इन्हें 'विद्रोही' कहा गया। अमेरिकी मीडिया ने आस्ट्राइड को पागल के रूप में पेश किया और यह जूठा प्रचार किया कि हैती की जनता आस्ट्राइड के खिलाफ विद्रोह कर रही है। हैती में घुस आए आतंकी एवं लम्पट दस्तों ने शहरों पर कहर बरपाते गए। उसी समय अमेरिका ने तीन जल जहाजों में 2,000 अमेरिकी नौ सैनिकों को तैनात किया। अमेरिकी सैनिकों ने भी 'सुरक्षा' प्रदान करने के नाम पर हैती में जबरिया प्रवेश किया। अन्य साम्राज्यावदियों ने भी तत्परता दिखाई और अमेरिका के साथ सांठगांठ कर लिया। फ्रांस एवं केनेडा ने अपने हिस्से के सैनिकों को वहां भेज दिया। यहां यह बताना लाजिमी होगा कि फ्रांस का हैती उपनिवेश रह चुका था। एक बार फिर अमेरिका का कठपुतला संयुक्त राष्ट्र संघ ने आक्रमणकारियों को एक अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल गठित करने अधीकृत किया। इराक मामले के ठीक विपरीत यहां सब कुछ सिर्फ तीन हफ्तों में हुआ।

सन् 1994 तक हत्यारा व कातिल शासक डोवेलियर एवं उसका बेटा पापाडाक की तानाशाही को झेलता रहा हैती। उस समय के कुख्यात अधिकारी आज के सशस्त्र गुटों का नेतृत्व कर रहे हैं। ''विद्रोह'' को अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया ने ऐसा पेश किया, मानो वह बहुत बड़े जनसंहार का कारण बनने वाला था। ''विद्रोहियों'' ने राजधानी में घुसकर अध्यक्ष भवन को घेर लिया। विदेशी सैनिकों ने यह इंतजाम कर रखा था कि कहीं कोई विरोध उठ खड़ा न हो जाए। 28 फरवरी को अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया। आस्ट्राइड को बोरिया-बिस्तर सहित हवाई जहाज में बिठाकर जबरन अफ्रीका भेज दिया गया। और अमेरिकी दूतावास ने प्रधानमंत्री को नजरअन्दाज करके प्रधान न्यायमूर्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया।

बाद में आस्ट्राइड ने उस दुखद दिन की याद करते हुए दुनिया को बता दिया कि उसके साथ क्या सलूक किया गया। बड़े पैमाने पर सशस्त्र बलों ने जिनमें गोरों के साथ-साथ हैती के लोग भी थे, 28 फरवरी के रात के अंधेरे में अध्यक्ष भवन पर धावा बोल दिया। और आस्ट्राइड का अपहरण किया। वह अपहरण एक भौगोलिक एवं राजनीतिक अपहरण था। वह आतंकवाद के सिवाए और कुछ नहीं था। अमेरिकी सैनिक अधिकारियों ने आस्ट्राइड पर यह कहते हुए इस्तीफे लिखकर देने बन्दूक की नोंक पर दबाव डाला क्योंकि अध्यक्ष भवन सहित पूरे राजधानी में कदम-कदम पर विद्रोही फैल गए हैं, किसी भी क्षण हमला चालू हो सकता है। एक बार हमला चालू होने के बाद वहां खून की होली खेली जाएगी। हजारों लोगों की मौत होगी। और मिशन पूरा होते तक कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। दरअसल बुश के पालतू आतंकवादियों की मंशा थी – अध्यक्ष आस्ट्राइड को जिंदा या मुर्दा पकड़ना और तख्ता पलटना। आखिर मजबूर होकर आस्ट्राइड ने इस्तीफा उनके हाथों में सौंपा। आस्ट्राइड को रातोंरात हैती से बाहर कर दिया गया। हैती की अर्थव्यवस्था की जड़ें बागानों, मिठाई दुकानों एवं आयात उद्देशित प्लान्टों में हैं। ये हैती की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के समान हैं। लेकिन ये सभी अमेरिकी, फांसीसी, केनेडियन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा मुट्ठी भर स्थानीय दलाल पूंजीपतियों के कब्जे में हैं। अमेरिका पापाडाक एवं हत्यारों के शासन को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिकी सैनिक दुराक्रमण एवं उदारवादी शासकों तक को न सहने के उसकी असहिष्णुता की एक मिसाल बन गया है हैती। उसे आज सिर्फ कठपुतली कहना चाहिए, सौ फीसदी कठपुतली।

क्या दुनिया के लोग अमेरिका के इस तरह के दुराक्रमण एवं सरकारों को अस्थिर करने की जघन्य, क्रूर एवं घिनौने हरकतों के प्रति चुप्पी साधेंगे? दुनिया की एक भी सरकार ने हैती पर अमेरिकी हमले और कब्जे की निंदा तक नहीं की। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जब साम्राज्यवादी एकजुट होते हैं तो बाकी चुप हो जाते हैं। ये खामोशी दुनिया के गरीब देशों पर हमले एवं कब्जे का खुला न्यौता साबित होगा। लेकिन यह जगजाहिर है कि दलाल एवं सरकारों का चुप रहना स्वाभाविक है। इसलिए विश्व जनता को चाहिए कि वे साम्राज्यवादियों के बर्बर एवं पाशविक हमलों एवं कब्जे की निंदा करें, विरोध करें और बहादुर इराकी जनता की तरह डटकर मुकाबला करें। ✶

पश्चिम बंगाल की माकपा सरकार ने दोबारा शुरू किया फर्जी मुठभेड़ों का सिलसिला

लोक नायक कॉमरेड असीम दास को लाल-लाल सलाम !

29 फरवरी को पश्चिम बंगाल की संशोधनवादी माकपा नीत सामाजिक फासीवादी सरकार ने भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] की राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड असीम दास उर्फ कंचन की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की। यह पुलिस के द्वारा जान बूझकर की गई जघन्य हत्या थी।

सातवें दशक में जब सिद्धार्थ शंकर राय तथा उसके पूर्व माकपा राज्य में सत्तारूढ़ थे, तब उनके हाथों हजारों क्रान्तिकारियों के खून से रंगे थे। कांग्रेस एवं तथाकथित कम्युनिस्टों ने नक्सलबाड़ी की आग के लपटों को बुझाने की बहुत कोशिश की। क्रान्तिकारियों के प्रति इनके आपराधिक रवैये के बावजूद क्रान्ति की लपटें थमीं नहीं, बल्कि देश भर में हजारों-हजार युवाओं को प्रेरणा दी। हालांकि क्रान्तिकारी आन्दोलन को पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा धक्का लगा था, लेकिन वह देश के अन्य भागों में फैलता गया। लम्बे समय के बाद क्रान्तिकारी आन्दोलन एक बार फिर पश्चिम बंगाल की तपती धरती पर फैल रहा है। इससे राज्य के नकली कम्युनिस्टों में यह सोचकर कि उनकी फालतू व्यवस्था का सही लाल राजनीतिक विकल्प बन रहा है, कम्पकम्पी पैदा हो गई। कॉमरेड असीम दास की जघन्य हत्या संशोधनवादियों की बढ़ती बेचैनी का संकेत है। राज्य की जनता में क्रान्तिकारी विकल्प की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए संशोधनवादियों ने फासीवादी दमन की शुरूआत मुठभेड़ हत्याओं के रूप में की।

कॉमरेड असीम दास को उनकी हत्या के पहले पश्चिम मिडनापुर के लालगढ़ थाना इलाके के झीटका जंगल से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उनके बूढ़े एवं बीमार माता-पिता को लाश देने से इनकार कर दिया और उसे पश्चिम मिडनापुर के झारग्राम अस्पताल के शवगृह में रख दिया। नागरिक अधिकार संगठन (एपीडीआर), शहीद साथी के परिवारजन तथा पनिहाटी इलाके के लोगों ने लाश देने पुलिस पर दबाव डाला। लाश के लिए वे आन्दोलन करने लगे। 4 मार्च को क्रान्तिकारी युवा संगठन एवं अन्य जन संगठनों ने 12 घण्टों के लिए बन्द का आह्वान किया। पनीहाटी जो कि एक बड़ी बस्ती है, में बन्द पूरी तरह सफल रहा, कामकाज ठप्प रहा।

भूमिगत होने से पहले कॉमरेड असीम दास एक लोकप्रिय जन नायक था। अपने छात्र जीवन से ही वह छात्र आन्दोलन में शामिल था। आठवें दशक में वह माकपा में शामिल हुआ था और उसके लिए काम किया। लेकिन बहुत जल्द ही उसने माकपा के संशोधनवाद को पहचाना और यह समझ लिया कि माकपा का क्रान्ति से कोई लेना-देना नहीं है और मजदूर वर्ग एवं मजदूर आन्दोलन के प्रति वह बेईमान है। इसलिए कॉमरेड दास ने माकपा छोड़ी और पनीहाटी नागरिक समिति नामक सामाजिक संस्था में शामिल हो गया जो इलाके की जनता के हित में मुद्दों को उठा रही थी। इस संस्था के बैनर तले कॉमरेड असीम ने जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। जनता के हित में काम करने के दौरान वह क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आया और क्रान्तिकारियों की कतार में शामिल हो गया। वह पीपुल्सवार पार्टी का सदस्य बना और जल्द ही राज्य कमेटी के सदस्य स्तर तक विकसित हुआ। उत्पीड़ित जनता की मुक्ति की राह में लगन के साथ काम करते हुए क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आने से ही यह सब सम्भव हुआ।

पुलिस एवं माकपा सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा एवं आक्रोश इस कदर बढ़ गया कि आखिर शहीद साथी की लाश को अन्तिम संस्कार के लिए परिवारजनों को मजबूरन सौम्पना पड़ा। बन्द के दो दिन बाद लोगों को पता चला कि लाश एक अस्पताल में पड़ी है, बड़ी संख्या में युवा, छात्र एवं अन्य जन संगठनों के लोगों सहित इलाके की साधारण जनता ने लाश को अपने कब्जे में लिया और लगातार बढ़ते जुलूस के साथ उनका अन्तिम संस्कार किया गया।

कॉमरेड असीम दास की हत्या ने माकपा सरकार के अलोकतांत्रिक एवं फासीवादी व जन विरोधी चेहरे को बेनकाब किया। पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में जनयुद्ध के रूप में क्रान्तिकारी आन्दोलन के निर्माण की कोशिश में लगी ताकतों को दबाने सरकार ने अपने पुलिस बलों को खुली छूट दे रखी है। भारत के शासक वर्गों तथा उनके साम्राज्यवादी मालिकों की सेवा में लगी माकपा के प्रतिक्रियावादी एवं जन विरोधी चरित्र का भी इस हत्या ने पर्दाफाश किया। फर्जी मुठभेड़ों में क्रान्तिकारियों की हत्याएं साम्राज्यवाद के एजेन्डा का ही हिस्सा है जिसे विश्व बैंक निर्देशित चन्द्रबाबू सरकार ने आन्ध्रप्रदेश में पहले ही शुरू किया था।

यह घिनौना तरीका देश के अन्य इलाकों में भी अपनाया जा रहा है, जहां जन छापामार युद्ध जारी है। चूंकि जन जीवन दिन ब दिन दूभर होता जा रहा है, इसलिए इन जघन्य हत्याओं के बावजूद छापामार युद्ध नए-नए इलाकों में फैल रहा है। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शासक एवं उनके प्रान्तीय मुखिया जनता से अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं। माकपा इसका अपवाद नहीं है। वह भारतीय शासक वर्गों के अगवे दस्ते के रूप में काम कर रही है। और यह काम लाल झण्डे के साये में कर रही है जो कि जनता के खून से रंगा है। कॉमरेड असीम दास की हत्या उनके भूतपूर्व 'कॉमरेडों' द्वारा की गई जो पश्चिम बंगाल में साम्राज्यवाद एवं विश्व बैंक निर्देशित नीतियों को बड़ी खुशी से अमल कर रहे हैं। हिम्मत और साहस का प्रतीक कॉमरेड असीम दास को 'प्रभात' की ओर से लाल-लाल सलाम। ✶

पाठकों से अपील

- *'प्रभात' पर अपने सुझाव-आलोचनाएं भेजते रहिएगा।*
- *रिपोर्टों के साथ फोटो भेजते समय उसके पीछे उसका पूरा विवरण लिखना मत भूलिएगा।*
- *'प्रभात' को जन-जन तक ले जाएं। 'प्रभात' के पैसे नियमित रूप से भेजते रहें। 'प्रभात' अपने पैरों पर खड़े हो सके, इसमें आपके सहयोग की बेहद जरूरत है।*

- सम्पादकमण्डल

श्रद्धांजली

आन्ध्रप्रदेश में फासीवादी चन्द्रबाबू सरकार के हाथों मारे गए

कॉमरेड्स कौमुदी, सुगुणा और विश्वम को लाल सलाम !

2003 अक्टूबर में फासीवादी चन्द्रबाबू सरकार ने आन्ध्रप्रदेश के तीन अहम कॉमरेडों की हत्या कर दी। 1 अक्टूबर को पीजीए की ऐक्शन टीम के एक जबर्दस्त हमले में बाल-बाल बचने के बाद बौखलाए चन्द्रबाबू ने क्रान्तिकारियों की निर्मम हत्याओं का सिलसिला तेज कर दिया। उस पर किए गए हमले से लोगों की सहानुभूति मिलने की उम्मीद से उसने विधानसभा को भंग करके क्रान्तिकारी आन्दोलन पर दमनात्मक अभियान को तेज किया। हालांकि उसने अपने शासन के आखिरी चरण में दर्जनों कॉमरेडों की हत्या की, लेकिन हमें कुछ ही कॉमरेडों की जीवनियां प्राप्त हुई हैं। पेश हैं कुछेक शहीदों की संक्षिप्त जीवनियां –

कॉमरेड कौमुदी – क्रान्तिकारी कवि और स्वप्नद्रष्टा

कॉमरेड कौमुदी (सदानन्दम) का जन्म वरंगल जिले के तरालपल्ली गांव में हुआ था जोकि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों का परम्परागत गढ़ है। 1980 के शुरूआती सालों में जब वह पढ़ रहे थे, तभी क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल हुए। वह लम्बे समय तक क्रान्तिकारी लेखक संघ का सदस्य रहे थे और वह आन्ध्रप्रदेश में एक मशहूर कवि माने जाते थे जिसे क्रान्ति ने पैदा किया।

शुरू में उन्होंने मेदक जिले के छापामार दस्तों में काम किया और बाद में उसी जिले में ट्रेड यूनियन संगठनकर्ता के रूप में काम किया। वर्ष 2000 में उन्होंने विशाखापट्टनम शहर में मजदूरों को लामबन्द करने की जिम्मेदारी ली और आन्ध्र-उड़ीसा सीमान्त स्पेशल जोनल कमेटी (एओबी एसजेडसी) के तहत काम किया। सितम्बर 2003 में, यानी उनकी शहादत से एक माह पहले आयोजित प्लीनम में उन्हें एसजेडसी सदस्य के तौर पर चुन लिया गया था। उन्होंने 2001 में कॉमरेड सुगुणा से शादी की थी। इन दोनों कॉमरेडों को पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर 24 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में एक मकान से गिरफ्तार किया और अगले दिन गुन्टूर जिले में एक झूठी मुठभेड़ में दोनों की जघन्य हत्या कर दी।

कॉमरेड कौमुदी को उनकी बेहद भावनात्मक क्रान्तिकारी शायरी के लिए याद रखा जाएगा। अपनी एक कविता में वह लिखते हैं कि किस तरह वह एक दिन किसी झूठी मुठभेड़ में मारा जाएगा और वह कौन सा लक्ष्य है जिसने उसे जान की कुरबानी देने के लिए प्रेरणा दी है। वह अपनी मां से कहते हैं कि वह उसके लिए आंसू न बहाए, बल्कि उसकी शहादत पर गर्व महसूस करे। वह अपनी बहनों से कहते हैं कि वे एक जबर्दस्त संघर्ष के लिए तैयार रहें और उस दिन का इन्तजार करें जबकि वह दोबारा अपनी मां के हाथों में तलवार और ढाल बनकर वापिस आ जाए। उनकी सभी कविताएं, चाहे वे लाखों भूखे-नंगे लोगों की गरीबी और भूख का वर्णन करती हों, व्यक्तियों के प्रति आत्मीयता जताती हों, पुलिस राज्य के दमन अभियान के बारे में कहती हों, या फिर सर्वहारा वर्ग के ऐतिहासिक कर्तव्य के बारे में लिखी हुई हों, सभी में मानवीय स्पर्श की अनुभूति होती है और पाठकों को भावनात्मक प्रेरणा मिल जाती है। उनकी कविताएं अपने पाठकों को क्रान्तिकारी भावातिरेक की बेअन्त चोटियों की ओर ले जाती हैं।

कॉमरेड कौमुदी की मृत्यु से क्रान्तिकारी आन्दोलन ने एक शानदार मजदूर वर्ग संगठनकर्ता खोया और क्रान्तिकारी साहित्यिक जगत् ने एक महान स्वप्नद्रष्टा और सृजनात्मक लेखक खोया।

कॉमरेड कौमुदी इतने लोकप्रिय थे कि उनकी शहादत की खबर सुनते ही हजारों लोग उनके गांव गए थे ताकि उनका अन्तिम दर्शन किया जा सके। उनकी अन्त्येष्टी के दृश्य ने सभी के दिलों को छू लिया। समूचा तरालपल्ली गांव लाल बैनरों और झण्डों से सजाया गया था। कई क्रान्तिकारी लेखकों ने 27 तारीख को आयोजित उनकी अंत्येष्टी में भाग लिया। पुलिस ने उन्हें आने से रोकने के लिए तारालपल्ली आने वाले सभी रास्तों और सड़कों को सील कर दिया और सभी वाहनों की तलाशी ली। फिर भी लोगों ने सभी बाधाओं को पार करके बड़ी संख्या में अंत्येष्टी में भाग लिया। लेखकों ने उनकी लाश के सामने खड़े होकर उनकी कुछ कविताएं सुनाईं। उनकी मां ने कहा कि वह ऐसे बेटे को जन्म देकर खुश है जिसने गरीबों की मुक्ति लिए जिया और मरा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके बेटे की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। उनकी लाश को लेकर जब जलूस निकला तो माहौल क्रान्तिकारी गीतों और नारों से गूंज उठा। "झूठी मुठभेड़ों की निंदा करो", "कॉमरेड कौमुदी अमर रहें", "शहीदों की मौत का बदला लो", "एक योद्धा की मौत से हजारों पैदा होंगे" आदि नारे जोर शोर से लगाए गए। ✶

कॉमरेड सुगुणा – लोकप्रिय व जुझारू जन नेत्री

पार्टी में राधक्का और लता के नामों से लोकप्रिय कॉमरेड सुगुणा पिछले दो दशकों से ज्यादा अरसे से क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल थीं। वह 1974-76 में गद्वाल शहर के एक कॉलेज में इंटरमीडियट की छात्रा थीं। उनके पिताजी रामि रेड्डी कर्नूल जिले के मित्तूर गांव से आकर गद्वाल में आ बसे थे। वह एलआइसी में विकास अधिकारी थे। वह मार्क्सवादी-लेनिनवादी राजनीति के समर्थक और सीपी रेड्डी के अनुयायी थे। उन्होंने अपने बच्चों को प्रगतिशील साहित्य पढ़ने और प्रगतिशील गतिविधियों में भाग लेने को प्रोत्साहित किया।

आपातकाल के काले दिनों में उनके पिताजी को गिरफ्तार किया गया और 18 महीनों तक जेल में रखा गया। चूंकि घर में कमाने वाले एक मात्र व्यक्ति वही थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी से घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई थी। कॉमरेड सुगुणा की इंटरमीडियट कोर्स लगभग दो साल तक रुक गई।

जब उस शहर में संगठन का काम शुरू हुआ था, सुगुणा और उनकी बहनें ही संगठन में भर्ती होने वाली पहली महिला कॉमरेड्स थीं। कॉमरेड सुगुणा का बरताव काफी अच्छा रहता था, उन्होंने अपने कई सह-छात्रों और दोस्तों को आरएसयू (रैडिकल छात्र संगठन) में भर्ती करवाया। एक अच्छी जन नायिका के रूप में वह छात्रों की समस्याओं के लिए हिम्मत से लड़ती थीं। उन दिनों महिलाओं और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ आवारागर्द गुण्डे खूब छेड़छाड़ किया करते थे। सुगुणा और उनके साथियों ने ऐसे गुण्डा तत्वों के दिलों में दहशत भर दी जिसका श्रेय काफी हद तक कॉमरेड सुगुणा के जुझारूपन को जाता है।

कुछ ही समय में वह छात्रों की नेता बन गईं और कई छात्रों को संगठन में लामबन्द किया। वह छात्रों की समस्याओं तक ही सीमित न थीं, बल्कि उन्होंने मेहनतकश महिलाओं को गोलबन्द करना भी शुरू किया। उनके लिए उन्होंने रात्रि-पाठशालाएं शुरू कीं। कुछ अन्य छात्रों को भी उन्होंने शिक्षक बनाया। चूंकि वह सुरीली गायिका भी थीं, इस नाते उन्होंने कई छात्रों और नौजवानों को सांस्कृतिक कर्मी बनने की प्रेरणा भी दी।

जब वहां कालाबाजारी के खिलाफ एक बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था, तब कॉमरेड सुगुणा ने अवैध भण्डारों पर हमले करने और सामान लोगों को बांटने में नेतृत्वकारी भूमिका अदा की। महंगाई के खिलाफ आन्दोलन हो या फिर किसी भी जन समस्या को लेकर कोई आन्दोलन हो, सुगुणा अग्रिम मोर्चे पर रहा करती थीं। एक बार आरडीओ ने जन नाट्य मंडली के कार्यक्रम की अनुमति रद्द की थी, तो सुगुणा ने कुछ महिलाओं को साथ लेकर आरडीओ का दो घण्टों से ज्यादा समय तक घेराव किया और आखिरकार सभा की अनुमति हासिल की। जब पार्टी ने 'चलो गांवों की ओर' का आह्वान किया, तो कॉमरेड सुगुणा ने एक टोले की अगुवाई करते हुए तत्कालीन गद्वाल तहसील के अनेक गांवों का दौरा किया। वह अपनी शहरी मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि के बावजूद किसानों से आसानी से घुलमिल जाती थीं।

1983 में वह शहर में पार्टी सेल सदस्या बन गईं और शहर में आन्दोलन को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहर में हर कोई सुगुणा को जानते थे। उनकी लोकप्रियता के चलते पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने से डरती थी। 1985 में स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद वह पेशेवर क्रान्तिकारी बन गईं। हालांकि बाद में उन्होंने रायचूर के विधि महाविद्यालय में दाखिला लिया था, पर पार्टी के फैसले पर वह भूमिगत हो गईं जिससे वह अधूरी ही रह गई।

शुरूआती दौर में चूंकि महिला कॉमरेडों को समुचित काम देने में पार्टी असमर्थ थी, इसलिए उन्हें पहले पहल शेल्टर में ही रहना पड़ा था। तब उन्होंने पार्टी के सामने मांग रखी कि उन्हें जंगल इलाका भेजा जाए। बाद में महबूबनगर जिले के नल्लामला जंगलों में उन्हें भेज दिया गया। कम समय में वह चेंचु आदिवासियों में 'अरुणक्का' के नाम से काफी लोकप्रिय हो गईं।

कॉमरेड सुगुणा पार्टी में सबसे पहली महिला कमाण्डर थीं। उनके जीवन साथी कॉमरेड सुदर्शन, जो एक तालाब में डूब रहे अपने एक साथी को बचाने की कोशिश में खुद ही डूबकर शहीद हुए थे, की मृत्यु के बाद उन्होंने जनता के लिए आखिरी दम तक लड़ने का अपना इरादा पक्का बनाया। 1989 में वह नल्लामला दस्ते की कमाण्डर बन गईं। उन्होंने जंगल इलाके के दूभर हालात में खुद को ढाल लिया। बार-बार मलेरिया व टाइफाइड और समुचित भोजन का अभाव – इन दिक्कतों से वह जरा भी विचलित नहीं हुईं। हालांकि वह शहरी जिन्दगी से आई हुई थीं, फिर भी उन्होंने सभी शारीरिक व मानसिक मुसीबतों को झेला और बड़े लगन के साथ खुद को विकसित किया। वह खुद को सर्वहारा बनाने के लिए लगातार व चेतनापूर्वक कोशिशें करती रहीं ताकि जनता के साथ घुलमिल जाया जा सके। इस दौरान उन्हें गंभीर स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं झेलनी पड़ीं। हालांकि उन्हें नियमित रूप से मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगे थे, फिर भी वह जंगल इलाके से बाहर नहीं गई थीं। उन्होंने चेंचु महिलाओं की जिन्दगी पर कई लेख भी लिखे थे। वह एक कवयित्री भी थीं। जनता की जिन्दगी पर और शहीदों पर उन्होंने कई कविताएं और गीत लिखे थे।

बाद में वह इंदुप्रियाल दस्ते की कमाण्डर बनकर मेदक जिले गई थीं। कुछ समय बाद वह जिला कमेटी सदस्या बन गईं। 1999 में उस जिले को छोड़ने तक उन्होंने दोनों जिम्मेदारियां निभाईं। उस समय तेलंगाना में क्रूर दमन चल रहा था। घरों में आश्रय लेने वाले दस्तों के दस्ते ही बुरी तरह मारे जा रहे थे, लेकिन कॉमरेड सुगुणा ने जनता को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कतारों और जनता में विश्वास जगाया। वहां हमेशा युद्ध जैसा माहौल बना रहता था। कब दुश्मन हमला कर देगा और कब मुठभेड़ होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता था। इसी दौरान उनका जीवनसाथी, जिनके साथ उन्होंने अपने पहले जीवनसाथी की शहादत के बाद शादी की थी, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। एक लम्बे अरसे तक पुलिस ने उन्हें जेल में ही रखा था। उस समय उनके अन्दर अन्दरूनी संघर्ष चला था कि वह दोबारा शादी कर ले या नहीं। वह पार्टी में पहली महिला थीं जिसने ऐसी स्थिति में जब कि जीवनसाथी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका हो और यह कोई नहीं जानता हो कि उसकी रिहाई कब होगी, दोबारा शादी करने के अधिकार के लिए लड़ा था।

बाद में वह मेदक से गुन्टूर जिला गईं और वहां पर दुश्मन के खिलाफ कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह उस दस्ते की कमाण्डर थीं जिसने जिले में पहली बार रामिडिचेर्ला गांव के निकट पुलिस पर घात लगाकर हमला करते हुए 7 को मार गिराया। जिले में जब कुछ लोग पार्टी से चले जा रहे थे और अन्दरूनी समस्याओं से पार्टी जूझ रही थी, तब उन्होंने एक नेता के रूप में अपनी भूमिका विश्वास के साथ निभाई और कतारों का विश्वास जीत लिया। कॉमरेड सुगुणा की शहादत आन्ध्र में और देश में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए एक बड़ा नुकसान है। ★

कॉमरेड विश्वम – जिसने शोषक व्यवस्था पर कलम व बन्दूक दोनों ही उठाईं

कॉमरेड विश्वम का जन्म वरंगल जिले के गांव तिम्मापुर में हुआ था। शहर के नजदीक रहे इस गांव पर शुरू से क्रान्तिकारी राजनीति की छाप थी। शहर के छात्रों ने जब 'चलो गांवों की ओर' अभियान शुरू किया तभी यह गांव क्रान्तिकारी राजनीति के सम्पर्क में आया था। घर पर उनका नाम जनार्धन था। जब उनके यार-दोस्त उच्च पढ़ाई करके कैरियर बनाने के चक्कर में थे तो जनार्धन ने सब कुछ छोड़कर सृजनशील राजनीति को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया।

क्रान्तिकारी राजनीति ही उनके लिए सृजनशील राजनीति थी। वह शहीद कॉमरेड्स रामकृष्ण और नागेश्वर राव के समकालिक थे जिनकी सरकार ने 1986 में एक झूठी मुठभेड़ में हत्या की थी। जब उनकी हत्या हुई थी तब कॉमरेड जनार्धन ने 'लाल सलाम' शीर्षक से एक कविता लिखी थी। 1984-90 का समय वह दौर था जबकि आन्ध्रप्रदेश में एनटीआर सरकार ने लोगों की बोलचाल और नाच-गाने पर भी पाबन्दी लगा रखी थी। खुले कार्यक्रम का कोई अवसर नहीं था। लेकिन इस दौर में कॉमरेड जनार्धन ने साहित्य की रचना जारी रखी। वह क्रान्तिकारी लेखक संघ (विरसम्) का जिला कन्वीनर बनकर दमन के कठिन दौर में भी साथी लेखकों का हौसला बढ़ाते रहे। वह विरसम् में रहते हुए ही 1990 में वरंगल शहर में आयोजित किसान-मजदूर संघ के राज्य सम्मेलन को सफल बनाने की भरसक कोशिश की। वरंगल शहर में आयोजित इस ऐतिहासिक सम्मेलन में लाखों किसानों ने भाग लिया जो कि क्रान्तिकारी आन्दोलन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसे सफल बनाने के लिए महीनों तक अविश्रान्त काम किया। इस काम में सक्रिय रहे कॉमरेड जनार्धन सरकार की नजर में पड़ गए।

ईमानदारी और कर्मठता ने कॉमरेड जनार्धन को एक महान कार्यकर्ता बनाया। एक लेखक और कवि के नाते उनमें मौजूद संवेदनशीलता और भावनात्मकता ने उन्हें एक परिणत साहित्यक व राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उभारा। दिन ब दिन उन पर सरकार का दमन बढ़ने लगा था तो उन्हें खुले तौर पर काम करने का कोई मौका नहीं रह गया था। उस स्थिति में वह भूमिगत होकर पूर्णकालीन कार्यकर्ता के तौर पर आन्दोलन में कूद पड़े।

विशाखापट्टनम शहर में और उसके आसपास के इलाकों में उन्होंने विश्वम और अन्य नामों से जनता के बीच काम किया। एक दशक से ज्यादा समय तक कार्यकर्ता, नेता और जनता का मार्गदर्शन करने वाले बुद्धिजीवी के रूप में उन्होंने शोषित जनता के बीच ही जिया और काम किया। उनकी संवेदनशीलता साहित्य-रचना और क्रान्तिकारी व्यवहार में मानवीय रिश्तों की समझ के रूप में अभिव्यक्त हुआ करती थी। उन्होंने अपनी बेबाक आलोचना और सूक्ष्म परख के लिए हमेशा क्रान्ति के हितों को कसौटी माना था। खुले तौर पर भी और भूमिगत होकर भी उन्होंने हर पल क्रान्ति के लिए ही खर्च किया और अपनी सारी शक्ति क्रान्ति के हित में लगाई।

एक हाथ में कलम और एक हाथ में बन्दूक उठाकर लड़ने वाले सुब्बाराव पाणिग्राही और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले समुद्दु, एमएसआर, भूमिपुत्र, आदि की राह पर अब कौमुदी और विश्वम भी शामिल हो गए। एक साथ हुई एक ही जिले के इन दोनों क्रान्तिकारी लेखकों की शहादत ने वरंगल जिले की शोषित जनता को गहरा सदमा पहुंचाया है। इन तीनों कॉमरेडों की मौत क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान है। ✶

दण्डकारण्य के शहीदों को लाल सलाम !

कॉमरेड बिच्चू आत्रम अमर रहें !

कॉमरेड बिच्चू आत्रम गड़चिरोली जिले के पेरिमिलि इलाके के गांव गट्टापल्ली के निवासी थे। उनकी शहादत फरवरी 2004 में बीमारी के कारण हुई। कॉमरेड बिच्चू 1997 से जन संगठन में काम करते रहे। जब दमन के कारण लोग संगठन में रहने के लिए डर रहे थे तब कॉमरेड बिच्चू हिम्मत से आगे आए और अपने गांव में संगठन बनाया। वर्ष 2000 में उन्हें डीएकेएमएस रेंज कमेटी का नेता चुन लिया गया। 2001 में उन्हें पार्टी सदस्यता दी गई। वह संगठन में रहकर कुशलतापूर्वक काम करते थे और जब भी अपनी ओर से कोई गलती हुई तो अपनी कमेटी के अन्दर नम्रता के साथ आत्मालोचना करते थे। पार्टी जो भी काम सौम्पती तो वह अपना घर का सारा काम-धाम छोड़कर जाया करते थे। इस इलाके में दुश्मन को हैरान-परेशान करने के लिए किए गए कुछ हमलों में भी कॉमरेड बिच्चू ने सक्रिय भाग लिया। कुछ जन समस्याओं को लेकर पार्टी ने चक्काजाम का कार्यक्रम दिया तो उसे सफल बनाने में उन्होंने जनता कुशल नेतृत्व किया। पुलिस दमन जब उन पर बढ़ने लगा तो वह पूर्णकालीन सदस्य के रूप में पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हुए थे। पेरिमिलि दस्ते के इलाके में कम से कम 10-15 गांवों में संगठन की गतिविधियों को संचालित करने में कॉमरेड बिच्चू का जबर्दस्त योगदान रहा। लोगों के साथ उनका व्यवहार भी अच्छा हुआ करता था। एक नेता होने का घमण्ड उनमें कभी नहीं देखा गया। आज उनकी मृत्यु के बाद इस इलाके में एक खालीपन सा आ गया। बीमारी ने उन्हें हमसे अलग किया। आदिवासी इलाके असमायिक मृत्यु के लिए जाने जाते हैं। सरकारों की उपेक्षा के चलते छोटी-छोटी बीमारियों का भी सही समय पर इलाज न होने के कारण कई लोग बेमौत मारे जाते हैं। कॉमरेड बिच्चू की याद में इस इलाके के लोगों ने एक सभा आयोजित की जिसमें अनेक गांवों के लोगों ने भाग लिया। इस सभा को स्थानीय पार्टी नेताओं और जन संगठन नेताओं ने संबोधित किया। ✶

कॉमरेड सोमाल को लाल सलाम !

किष्टारम रेंज एलमागोंडा गांव का निवासी कॉमरेड पोडियम सोमाल की कुछ माह पहले बीमारी से मृत्यु हुई। वह बाल संगठन के दिनों से क्रान्तिकारी गतिविधियों में भाग लेते रहे। इस गांव का सरपंच पाण्डू के खिलाफ जनता के संघर्ष में कॉमरेड सोमाल आगे रहे थे। पाण्डू जनता का घोर दुश्मन था। कॉमरेड सोमाल के साथ जन संगठन में काम करने वालों में कुछ लोग दमन के कारण पीछे हटे थे और कुछ लोग पतित हो चुके थे। लेकिन वह तो आखिरी तक क्रान्तिकारी राजनीति से जुड़े रहे। पार्टी द्वारा कई बार आयोजित राजनीतिक व मिलिटरी प्रशिक्षण शिविरों में भी उन्होंने भाग लिया था। घर में परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए और खेती के काम करते हुए ही वह पार्टी के कामों को महत्व दिया करते थे। वह गांव में पार्टी सदस्य भी बने थे और ग्राम रक्षा दल के कमाण्डर भी चुन लिए गए थे। इस कॉमरेड की मृत्यु ने गांव वालों को झकझोर किया है। गांव के सभी लोगों ने कॉमरेड सोमाल की अन्त्येष्टी में भाग लिया। उनकी लाश पर लाल झण्डा ढांककर 'कॉमरेड सोमाल अमर रहें' के नारे लगाते हुए लोगों ने जुलूस निकाला। उनकी याद में लोगों ने एक गीत भी रचकर गाया। स्थानीय किष्टारम एरिया कमेटी ने कॉमरेड सोमाल को श्रद्धांजली दी और उनके अधूरे मकसद को पूरा करने की शपथ ली। ✶

श्रद्धांजली

फासीवादी चन्द्रबाबू नाइडू के भाडे के कुत्ते ग्रे-हाउण्ड्स के साथ बहादुरी से लड़कर शहादत का परचम ऊंचा करने वाली

वीर योद्धा कॉमरेड पेंटी पोरतेटी (स्वरूपा) को अमर रहें !

कोरापुट हमलों के लिए गठित विशेष कम्पनी की सदस्या कॉमरेड स्वरूपा 17 नवम्बर को विशाखापट्टनम जिले के बतनूर गांव में पुलिस के हमले में शहीद हुईं। इस विशेष कम्पनी की एक टुकड़ी की हलचल की खबर पाकर वहां के मुखबिर ने पुलिस को लाया था। पुलिस ने अचानक हमला करके दस्ते पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस गोलीबारी में कॉमरेड स्वरूपा के पैर में गोली लगने से वहीं गिर पड़ीं। वहीं से उसने लगभग दो घण्टों तक ग्रे-हाउण्ड्स बलों के खिलाफ लड़कर वीरगति को प्राप्त किया। पीजीए की इस जांबाज योद्धा को 'दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी' श्रद्धांजली अर्पित करती है।

कॉमरेड स्वरूपा का जन्म गड़चिरोली जिले के अहेरी इलाके के ग्राम करंचा में एक गरीब किसान परिवार में करीब 22 साल पहले हुआ था। मां-बाप ने उन्हें एक बेटे की तरह पाला-पोसा था। स्वरूपा की एक छोटी बहन और एक छोटा भाई थे। करंचा गांव शुरू से ही पार्टी के मजबूत गढ़ों में से एक रहा। स्वरूपा संघर्षों के बीच ही पली-बढ़ीं। बचपन से ही वह पार्टी के सम्पर्क में रही। बचपन से ही उन्हें संघर्ष के गीतों और कहानियों से काफी लगाव था। हमेशा सक्रिय व खुश रहने वाली यह लड़की जल्द ही गांव के बाल संगठन की सदस्या बन गई। जब बड़ी हुई तब केएएमएस की सदस्या बनकर काम करने लग गईं। जब पार्टी ने कॉमरेड स्वरूपा को पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर पार्टी में भर्ती होने को कहा तो वह बेहिचक आ गईं। वर्ष 2000 के बीच पार्टी में भर्ती होने वाली कॉमरेड स्वरूपा पीजीए की सदस्या बन गईं। इनके साथ इसी गांव से कॉमरेड लक्ष्मी भी पार्टी में आई थीं। दोनों अच्छी सहेलियां थीं। लेकिन दस्ते में आने के एक महीने के अन्दर ही चामोर्षी इलाके में पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में कॉमरेड लक्ष्मी शहीद हो गईं। इस घटना ने कॉमरेड स्वरूपा का हौसला और भी बढ़ाया। उन्होंने फैसला लिया कि वह भी अपनी सहेली लक्ष्मी की तरह आखिरी दम तक आन्दोलन में खडी रहेगी और जनता के लिए जान दे देगी। पार्टी के फैसले पर वर्ष 2001 से वह प्लटून-3 की सदस्या बन गईं। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के बावजूद वह आखिरी दम तक अपने कार्यभारों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करती रहीं।

कॉमरेड स्वरूपा ने दण्डकारण्य में पीजीए की अगुवाई में हुए कई हमलों में भाग लिया। 2001 में यहां चलाए गए पहले कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान के तहत बांदे पुलिस थाने पर हमले में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी साहस के साथ पूरी की। गड़चिरोली डिवीजन में कोठी के निकट एसपी राजवर्धन के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में भी वह शामिल थीं। पार्टी ने सिरोंचा एरिया में संगठन काम दोबारा शुरू करने का फैसला करके एलजीएस भेजा था। गड़चिरोली पुलिस ने इन कोशिशों को रोकने की पूरी कोशिश की। ऐसी स्थिति में पार्टी ने पीएल-3 को उस इलाके में भेजा था ताकि दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। उस दौरान कोप्पेला के निकट दुश्मन पर किए गए हमले में कॉमरेड स्वरूपा ने वीरता का प्रदर्शन किया। आन्दोलन का सफाया करने के लिए दुश्मन लगातार हमले बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पीजीए के बलों को भी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है। इसके तहत पार्टी ने पीजीए में स्ट्राइकिंग फोर्स का गठन करने का फैसला लिया। उसके प्रशिक्षण के लिए आयोजित कैम्प में छात्रा के तौर पर कॉमरेड स्वरूपा का चुनाव हुआ। पार्टी में, मुख्य रूप से दण्डकारण्य में लगातार विकसित हो रही पीजीए के लिए हथियारों की कमी पड़ रही थी। इसकी पूर्ति करने के लिए पार्टी ने कुछ अहम हमले करने का फैसला लिया। इसके तहत गीदम पुलिस थाने पर किए गए सफल हमले में कॉमरेड स्वरूपा ने स्टाप पार्टी सदस्या के रूप में भाग लेते हुए अतिरिक्त बलों को थाने की तरफ बढ़ने से रोका था।

चूंकि कॉमरेड स्वरूपा बेहद गरीब परिवार से आई हुई थीं, इसलिए उन्हें पढ़ाई नसीब नहीं हुई। घर के अन्दर व खेतों के कामों में वह मां-बाप का हाथ बंटाया करती थीं। उन्होंने अपने मेहनती स्वभाव को पार्टी और पीजीए में भी बरकरार रखा।

आज जबकि केन्द्र व राज्य के सशस्त्र बलों द्वारा तालमेल के साथ किए जा रहे हमलों का मुकाबला करने के लिए पीजीए को उन्नत फॉर्मेशनों में विकसित करना वक्त की मांग बन चुका है, कॉमरेड स्वरूपा जैसी युवा और साहसिक छापामार योद्धाओं की शहादत से पार्टी को, खास तौर पर पीजीए को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने अनगिनत वीर शहीदों द्वारा स्थापित कुरबानी की परम्परा को ऊंचा उठाते हुए अपने लहू से हमारे लाल झण्डे की लालिमा बढ़ा दी। वह आसमान में भोर का तारा बनकर हमें राह दिखाती रहेंगी। वर्तमान शोषक समाज को मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के हथियार से तहस-नहस करने के इरादे से कॉमरेड स्वरूपा पार्टी में आई थीं। इस मकसद को पूरा करने का उन्होंने सपना देखा। इस शहीद साथिन के सपनों को साकार बनाने का कर्तव्य अब हमारे कंधों पर है। जनयुद्ध को आगे ले जाकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजली पेश करेंगे। आइए, हम फिर एक बार कसम खा लें कि कॉमरेड स्वरूपा के ऊंचे अरमानों को हम मंजिल तक ले जाएंगे। ★

(.... अन्तिम पृष्ठ का शेष)

पीजीए का आधार बल है, ने दुश्मन को यहां आने से रोकने के लिए सुरक्षा का इतना व्यापक और सघन बन्दोबस्त किया कि कोई चींटी भी घुसने न पाए। यहां के जन संगठनों के आमंत्रण पर 'सहारा समय' और 'बीबीसी' टीवी चैनलों के लोग भी आए थे ताकि इस कार्यक्रम का कव्हरेज किया जा सके।

10 फरवरी को नेलनार पहुंचने के लिए दूरी के हिसाब से लोग दो से तीन दिन पहले ही अपने-अपने गांवों से निकल पड़े थे। काफी दूर के गांवों के लोग करीब एक हफ्ता पहले ही निकले थे। अलग-अलग टोलियों में निकले लोग अपने साथ खाने-पीने का सामान और बर्तन भी साथ ले आए। 9 तारीख की शाम तक सभी लोग नेलनार के आसपास के गांवों में इकट्ठे हो गए। नदियों और झरनों के इर्द-गिर्द डेरा लगाने वाले ये लोग 10 तारीख की सुबह का खाना वहीं खाकर नेलनार की तरफ बढ़े जो कि उनका आखिरी पड़ाव था। तब तक नेलनार गांव में जन संगठन कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर लीं। सुबह के 10 बजे से ही लोगों का वहां पहुंचना शुरू हुआ। हाथों में लाल झण्डे, बैनर और तख्तियां लेकर लोग अलग-अलग टोलियों में आने लगे थे। हर गांव से लोगों ने ढोल, नगाड़ा, तुड्डुम, *हक्कम* जैसे परम्परागत वाद्ययंत्र भी साथ लाए थे। विशाल मैदान में अलग-अलग जगहों पर इकट्ठे हुए लोगों के गीतों और नारों से पूरा माहौल बड़े शोर से भर गया था। दोपहर के दो बजे वहां से रैली निकली। दो-दो लोग कतारबद्ध होकर निकल पड़े। रैली एक सिरे से दूसरे सिरे तक कुछ किलोमीटर लम्बी बन गई थी। कुल लोगों की संख्या करीब 10 हजार थी। इनमें कम से कम 4 हजार तक महिलाएं होंगी।

एक और भूमकाल का बिगुल बजाता माड़वासी

बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी इस आयोजन की एक और खासियत थी। दूर के गांवों से महिलाएं कम संख्या में आई थीं, जबकि आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में आई थीं। सैकड़ों महिलाओं ने अपनी गोद में नन्हे बच्चों को लेकर और हाथ में लाल झण्डा लेकर जिस उत्साह के साथ इस रैली में भाग लिया, उसका वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ेंगे। उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानों वे एक महान संघर्ष की विरासत को खुद जारी रखते हुए ही अपने बच्चों को भी घुट्टी में पिला रही थीं।

रैली में 'भूमकाल संघर्ष जिन्दाबाद', 'वीर गुण्डाधुर को जुहार', 'भूमकाल संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे', 'नव जनवादी क्रान्ति जिन्दाबाद', 'नव जनवादी क्रान्ति को सफल बनाएंगे', 'विश्व जनता का नम्बर एक दुश्मन अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद', 'इराक से अमेरिकी बलों को वापिस लो', 'जनता की राज्यसत्ता की स्थापना करेंगे', 'लुटेरी वर्गों की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे' आदि नारे गोण्डी, हल्बी, हिन्दी आदि भाषाओं में लगाए गए। जोर शोर से लगाए गए ये नारे गांव के इर्द-गिर्द मौजूद जंगल-पहाडों में गूंज उठे। इस आयोजन में सैकड़ों बच्चों ने भी भाग लिया जो अपने-अपने गांवों के बाल संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। रैली गांव की उत्तरी दिशा में मौजूद एक बरगद तक जाकर फिर वहां से स्मारक तक लौटी जोकि मंच के बिल्कुल सामने था।

नेलनार गांव के इस बरगद को भी इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। दरअसल नेलनार गांव उन दसियों गांवों में से एक था जो 'भूमकाल' संघर्ष के मजबूत गढ़ हुआ करते थे। अंग्रेजों के जुल्मों और अत्याचारों का यह गांव भी शिकार हुआ था। अंग्रेजों ने इस गांव में जो अमानवीय कत्लेआम मचाया था, उसकी यादें इस गांव के बूढ़े लोगों के मन में आज भी ताजी हैं। वे बताते हैं कि अंग्रेजों ने इस गांव को जलाया था। उन्होंने महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और कई लोगों को मार डाला था। यहां पर लोगों के खून की धाराएं बही थीं। बताया जाता है कि जिस जगह पर खून की धाराएं बहाई गई थीं वहां उस समय एक बरगद का पौधा था जो खून में डूबा था। अंग्रेजी अधिकारियों ने टिप्पणी की थी कि इस खून से यह पौधा मर जाएगा और उसी तरह इस कत्लेआम से 'भूमकाल' विद्रोह भी दब जाएगा। भूमकाल विद्रोह खत्म हुआ। लेकिन वह पौधा एक बहुत बड़ा पेड़ के रूप में आज भी जिन्दा है, ठीक वैसा ही जैसा कि इस इलाके के लोगों में आजादी की चाह और शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का पक्का इरादा आज भी बरकरार हैं।

जब रैली स्मारक तक पहुंची, गांव के डीएकेएमएस अध्यक्ष ने डीएकेएमएस का झण्डा उठाकर भूमकाल संघर्ष के शहीदों को श्रद्धांजली पेश की। बाद में 'चेतना नाट्य मंच' के कलाकारों ने भूमकाल संघर्ष में शहीद होने वाले लोगों और भूमकाल के नेताओं को याद करते हुए एक गीत पेश किया। बाद में अध्यक्षमण्डल को मंच पर बुलाने के साथ ही सभा का कार्यक्रम शुरू हुआ। स्थानीय डीएकेएमएस और केएएमएस नेताओं ने सभा की अध्यक्षता की और जन संगठनों और पार्टी कमेटियों के नेताओं ने सभा को सम्बोधित किया।

सबसे पहले एरिया पार्टी कमेटी सदस्य कॉमरेड विजय ने सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने भूमकाल संघर्ष में इस इलाके के लोगों की वीरतापूर्ण भूमिका को याद करते हुए लोगों का आह्वान किया कि उनकी विरासत को जारी रखा जाए। नेलनार, झारा, दुरवेड़ा आदि गांवों के लोगों ने उन दिनों इस महान संघर्ष में भाग लेकर अपने अनमोल प्राणों को न्यौछावर किया था। कॉमरेड विजय ने आगे कहा कि भूमकाल के शहीदों ने शोषणविहीन समाज की स्थापना का जो सपना देखा था वह अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने आह्वान किया कि उनके सपनों को साकार बनाने के लिए हमें आज देश के कई हिस्सों में जारी नव जनवादी क्रान्ति को सफल बनाना होगा।

बाद में एरिया पार्टी कमेटी सचिव कॉमरेड राधक्का ने सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में लोगों को याद दिलाया कि उस समय के भूमकाल संघर्ष में माड़ इलाके की महिलाओं ने बड़ी

संख्या में भाग लिया था। कॉमरेड राधक्का ने खासतौर पर वहां उपस्थित महिलाओं का आह्वान किया – ''परालकोट विद्रोह में भी महिलाओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। इतिहासकारों के मुताबिक उस विद्रोह में एक महिला ने संघर्ष में जनता का नेतृत्व भी किया था। उसके बाद भूमकाल विद्रोह में भी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अंग्रेजी शासकों ने संघर्ष को दबाने के लिए बलात्कार को महिलाओं के दमन का एक साधन बनाया था। वर्तमान दलाल पूंजीवादी और सामंती शासक भी महिलाओं के लड़ाकूपन पर पानी फेरने के लिए अंग्रेजी शासकों की ही नीतियों पर ज्यादा क्रूरता से अमल कर रहे हैं। इसलिए भूमकाल शहीदों की विरासत को जारी रखते हुए, समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान बड़े पैमाने पर आगे आना चाहिए ताकि उन शहीदों के सपनों को साकार बनाया जा सके।''

बाद में माड़ डिवीजन पार्टी सचिव कॉमरेड पाण्डू ने अपने भाषण में विस्तारपूर्वक बताया कि भूमकाल संघर्ष किस ढंग से चला था और उस समय जनता के हालात क्या थे। उन्होंने कहा – ''आज शासक वर्ग भी भूमकाल संघर्ष का नेता गुण्डाधुर का नाम ले रहे हैं। उनके नाम पर स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि पुलिस ने जनता पर चलाए दमन-अभियान का नाम भी 'जय गुण्डाधुर अभियान' रखा है। शासक वर्गों के गुण्डाधुर का नाम लेने में उतनी ही धोखेबाजी है जितनी उनके 8 मार्च को महिला दिवस मनाने में और 1 मई को मजदूरों को बधाई संदेश देने में है। पिछले साल पुलिस द्वारा चलाए गए 'जय गुण्डाधुर अभियान' में पास में ही मौजूद ग्राम झारा का किसान जोगा वंजामी मारा गया था। दरअसल पुलिस ने उसे पकड़कर मार डाला था। झारा एक जमाने में अंग्रेजी सेनाओं के अत्याचारों का भी साक्षी था। आज ऐसे अनेक गांव हैं जो वर्तमान दलाल शासक वर्गों के पाशविक दमनचक्र को झेल रहे हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जहां ब्रितानी साम्राज्यवाद ने उस समय प्रत्यक्ष शासन करते हुए लोगों को लूटा था, वहीं आज भारत के दलाल पूंजीवादी और सामन्ती वर्गों की सरकारें साम्राज्यवाद के साथ सांठगांठ करके देशवासियों को अकथनीय शोषण और उत्पीड़न का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में भूमकाल संघर्ष और भूमकाल के शहीदों को याद करने का मतलब वर्तमान लुटेरी व्यवस्था को जड़ से सफाया करने की शपथ लेने के अलावा कुछ भी नहीं है। यहां की जनता को लूट, दमन, भूख, गरीबी, बीमारी, निरक्षरता आदि का शिकार बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे लुटेरे शासकों को न तो भूमकाल का नाम लेने और न ही गुण्डाधुर के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार है। शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति हासिल करनी है तो देश के कई हिस्सों में, खासतौर पर आंध्र, दण्डकारण्य, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा आदि राज्यों में जनता की राज्यसत्ता की स्थापना के लिए जारी संघर्ष में भाग लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए, आइए, हम सब महान भूमकाल संघर्ष को और उसके द्वारा स्थापित वीरतापूर्ण कुरबानियों की परम्परा को याद करते हुए वर्तमान जनयुद्ध के रास्ते में दृढ़ता से कदम बढ़ाने का संकल्प लें।''

आखिर में पार्टी की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव कॉमरेड कोसा ने भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में उन कारणों पर रोशनी डाली जिनके चलते उस समय भूमकाल जैसा एक महान विद्रोह आखिरकार पराजित हुआ था। उन्होंने कहा – ''उस समय यहां वैज्ञानिक विचारधारा से लैस एक पार्टी और सक्षम नेतृत्व के अभाव के चलते ही बस्तरवासियों द्वारा किए गए तमाम विद्रोह आखिरकार पराजित हुए थे। लेकिन आज हम मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद, जोकि वैज्ञानिक कम्युनिस्ट विचारधारा है, से लैस होकर लड़ रहे हैं। हमारे पास आज अपनी सेना – जन छापामार सेना – है। आज हमारा आन्दोलन कई गांवों में जनता की राज्यसत्ता के अंगों की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रहा है। दण्डकारण्य को आधार इलाके में तब्दील करने के लक्ष्य से हमारा यह जनयुद्ध जारी है। उस समय जनता ने अपनी सीमित चेतना से 'माडिया राज्य' की स्थापना की थी जो ताकतवर दुश्मन के आगे ज्यादा दिन नहीं टिक सका था। लेकिन आज हम ग्राम स्तर पर 'जनताना सरकार' (क्रान्तिकारी जन कमेटी) का निर्माण कर रहे हैं जो उन्नत चेतना से विकसित हो रही है। इसे हम ग्राम स्तर से बढ़ाकर उससे व्यापक स्तर में ले जाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। आज हम भूमकाल दिवस मनाते हुए अपना यह संकल्प दोहराएंगे कि मजदूर-किसानों की एकता के आधार पर शोषित जनता की राज्यसत्ता हासिल करने के लक्ष्य से जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। माओ के बताए तीन जादुई हथियार – पार्टी, जन सेना और संयुक्त मोर्चा को हम मजबूत बनाते हुए, इलाकावार राज्यसत्ता दखल करते हुए, आधार इलाकों का निर्माण करते हुए देशव्यापी जीत की ओर आगे बढ़ेंगे।''

जन सेना की उपलब्धियों का बखान करते हुए कॉमरेड कोसा ने इस कार्यक्रम के ठीक चार दिन पहले कोरापुट में पीजीए सैनिकों द्वारा किए गए साहसिक हमलों को जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि जन छापामार सेना द्वारा जनता के सक्रिय समर्थन से वहां हमला करके सैकड़ों हथियार छीने जाने की यह कार्यवाही इतिहास में यादगार रहेगी। कॉमरेड कोसा ने यह कहते हुए पीजीए के लाल योद्धाओं का लाल अभिनन्दन किया कि उन्होंने इन हमलों से साबित किया कि जनता पर निर्भर करने वाली सेना दुश्मन को उसके मजबूत गढ़ माने जाने वाले अड्डों में भी पराजित कर सकती है।

सरकारी सुधारों के ढोंग को समझाते हुए कॉमरेड कोसा ने लोगों से कहा, ''लुटेरी सरकारें जनता को क्रान्तिकारी आन्दोलन से गुमराह करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर कई सुधार सामने ला रही हैं। एक तरफ पुलिस बलों को उतारकर हत्याओं और जुल्मों का सिलसिला जारी रखते हुए ही, दूसरी तरफ पैसा फेंककर सुधारों को लागू करना सरकार की ढोंगबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है।'' उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि बुनियादी समस्याओं को हल न कर सकने वाले इन झूठे सुधारों को ठुकरा दें। इसी मौके पर कॉमरेड कोसा ने आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान भी किया।

इस सभा में प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष आकर्षण था। कई दिन पहले से ही चेतना नाट्य मंच के सांस्कृतिक कर्मियों ने अपनी तैयारियां शुरू कीं। उन्होंने खास तौर पर भूमकाल संघर्ष पर एक नाट्य रूपक प्रस्तुत किया। इसके अलावा शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए दीपों के साथ किए गए नृत्य ने भी लोगों का मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम देर रात तक चलते रहे। स्थानीय जनता ने भी मंच पर आकर अपने नाच-गाने का प्रदर्शन किया। भूमकाल संघर्ष की विरासत जारी रखने और जनता की राज्यसत्ता को कायम करके उसे मजबूत बनाने के संकल्प के साथ लोग वहां से लौटे। ★

भूमिपति बोड्डा मंगू की जमीन पर जनता का कब्जा

दक्षिण बस्तर डिवीजन के बासागूडेम इलाके में जनता अपने संगठनों की अगुवाई में गांव के ज़ालिम मुखियाओं, शोषक सरकार और जुल्मी पुलिस के खिलाफ लड़ते हुए कई उपलब्धियां हासिल कर रही है। हाल में एक जमींदार बोड्डा मंगू की जमीन पर किया गया कब्जा इनमें से एक है।

दरबा गांव का बोड्डा मंगू सरपंच और जालिम मुखिया था। शुरू से लोगों पर इसका जुल्म जारी था। इसके परिवार के अन्य सदस्य सरकारी पदों पर हैं। इसके पास 40 एकड़ जमीन थी। 100 से ज्यादा मवेशी थे। इसका भाई बोड्डा दुडवाल के पास भी 30 एकड़ जमीन थी। इन दोनों को जनता ने जन संगठनों और पार्टी के नेतृत्व में कई बार चेतावनी दी कि वे लोगों पर अपना जुल्म बन्द करें। इसके बावजूद इनमें कोई सुधार नहीं आया तो इन्हें जन अदालत में पेश किया गया जिसमें 10 गांवों के 900 लोगों के साथ-साथ 20 पीजीए छापामारों ने भी भाग लिया। जन अदालत के फैसले के अनुसार मंगू की पिटाई की गई और इन दोनों भाइयों की चल व अचल सम्पत्तियों को छीनना तय हुआ।

इसके बाद लोग अपने हाथों में लाल झण्डे लेकर नारे लगाते हुए और क्रान्तिकारी गीत गाते हुए निकल पड़े। इसमें स्थानीय चेतना नाट्य मंच के कलाकारों की भागीदारी भी रही। वे गीत गाते हुए लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे। लोगों ने मंगू की 20 एकड़ जमीन, 20 गायें और कुछ धान छीन लिया और उसके भाई से 10 एकड़ जमीन छीन ली। इस संघर्ष से जहां लोगों में क्रान्तिकारी उत्साह बढ़ गया, वहीं आसपास के इलाकों में जनता पर जुल्म करने वालों के दिलों में खतरे की घंटियां बज गईं।

पुलिस की मदद करने वाले मुखिया को चेतावनी

माड़ डिवीजन के बासिंग गांव का पटेल शुरू से ही जन विरोधी था। जबसे इस गांव में क्रान्तिकारी जन संगठनों का निर्माण हुआ, तभी से वह उनके विरोध में खड़ा हो गया। इसे स्थानीय पार्टी ने कई बार चेतावनी दी, फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। हाल ही में सम्पन्न छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के दौरान उसने लोगों को यह कहकर धमकी दी कि जो लोग वोट नहीं डालेंगे वह उनका नाम पुलिस को बताएगा। दरअसल इसे पहले से ही पुलिस की मदद हासिल थी। कई लोगों ने पुलिस से प्रताड़ना के डर से वोट डाला। इसके बाद पुलिस और सीआरपी बलों ने इस इलाके में गश्त अभियान चलाया तो इसी ने उनके साथ रहकर रास्ते दिखाया। इसके बाद स्थानीय पार्टी ने 27 जनवरी को 10 गांवों की जनता को बुलाकर जन अदालत आयोजित की जिसमें इसका पर्दाफाश किया गया। जन अदालत में इसके सारे काले कारनामों पर चर्चा हुई। जनता ने पटेल को गंभीर चेतावनी दी कि वह आइंदा पुलिस की मदद करेगा तो जान से मार डाला जाएगा। जनता की संगठित शक्ति के सामने पटेल ने सिर झुकाया और अपनी गलती स्वीकार ली। और उसने जनता से क्षमायाचना की।

शहीद कॉमरेड बिच्चू आत्रम
(रिपोर्ट पृष्ठ 33 में है।)

मुरगा बाजार के खिलाफ प्रचार

आदिवासी इलाकों में मुरगा बाजार पहले से प्रचलित रिवाज है। लेकिन जबसे लोग क्रान्तिकारी जन संगठनों में संगठित होने लगे तभी से उनमें इसके खिलाफ चेतना जगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जहां पर जन संगठन सक्रिय हैं, उन इलाकों में अब मुरगा बाजार काफी हद तक बन्द हो चुके हैं, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी मुरगा बाजार चल रहे हैं। माड़ डिवीजन के डौला इलाके में हाल ही में लोगों में इसके खिलाफ जागरूकता लाने के लिए केएएमएस और डीएकेएमएस की अगुवाई में अच्छी पहलकदमी ली गई है। इस इलाके के गांव-गांव में मुरगा बाजारों के दुष्प्रभावों के बारे में प्रचार करने के बाद एक जगह पर बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया जिसमें खासतौर पर मुरगा बाजार की बुराइयों के बारे में लोगों को विस्तारपूर्वक समझाया गया। कैसे इन बाजारों में गरीब लोग लुटते हैं और कैसे इसमें लोगों के बीच लड़ाई-झगड़े पैदा होते हैं, इसके बारे में वक्ताओं ने लोगों को विस्तार से बताया। इस सभा में इस इलाके के लोगों ने संकल्प लिया कि आर्थिक रूप से बर्बादी और एकता के लिए खतरे का कारण बन रहे मुरगा बाजारों को बन्द किया जाए। इसके बाद इस इलाके के टोटीमडानार, वयानार, एमा, मंगवाल, ईनार, डौला, मइमागवाडी, कोसलपारा, भोता, कनारगांव, कडियानार, वेडमाकोट, डंडवंड, करमेरी, गोंगला, आधि – इन गांवों में मुरगा लड़ाई पूरी तरह बन्द हो गई। खास बात यह थी कि इस अभियान में इस इलाके की महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही।

नशाबन्दी के लिए महिलाओं का आन्दोलन

माड़ डिवीजन के डौला एरिया में लगने वाले हाट बाजारों में दारू, लंदा, सल्फी आदि की बिक्री को बन्द करने के लिए महिलाओं ने एक आन्दोलन छेड़ दिया। केएएमएस की अगुवाई में इस इलाके में इस पर व्यापक प्रचार किया गया। केएएमएस कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि बाजारों में इनकी बिक्री से लोगों का पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ-साथ पुरुषों द्वारा बाजार में दारू पीकर घर आकर पत्नियों को पीटना भी आम हो चुका है। उन्होंने लोगों को समझाया कि बाजारों में दारू बेचने का धंधा ही बन्द करना चाहिए। इस प्रचार का अच्छा असर रहा, खासतौर पर महिलाओं ने इसका स्वागत किया। ★

माड़ अंचल में 'भूमकाल' दिवस इन्कलाबी जोश के साथ सम्पन्न

बस्तर जिले के माड़ अंचल को इतिहास में काफी अहम स्थान है। ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और अनमोल प्राकृतिक संपदाओं के लिए सुविख्यात इस इलाके में अंग्रेजी उपनिवेशी शासन के खिलाफ लोगों ने कई विद्रोह किए थे। बस्तर के कुछ विद्रोहों का मुख्य केन्द्र यही इलाका रहा था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के काफी पहले, सन् 1825 में भड़के परालकोट विद्रोह का नेता गेन्दसिंह इसी इलाके से था। गेंदसिंह को आंग्ल-मराठा शासकों ने फांसी पर चढ़ाया था। विद्रोह को कुचल दिया था। फिर भी लोगों में आजादी की तमन्ना दबी नहीं थी। 1910 में बस्तर के लोगों ने एक और जबर्दस्त विद्रोह – 'भूमकाल' का शंखनाद किया था, जिसके प्रमुख केन्द्रों में माड़ इलाका भी एक था। 'भूमकाल' शब्द का अर्थ है 'व्यापक हलचल।' बस्तर के अवाम के अनेक विद्रोहों में से 'भूमकाल' विद्रोह को तीव्रता और पैमाने के नजरिए से सबसे ताकतवर विद्रोह कहा जा सकता है। 'भूमकाल' संघर्ष में इस इलाके के गांव के गांव ही शामिल हो गए थे। माड़वासियों ने विद्रोह का परचम ऊंचा उठाकर कुरबानी की बढ़िया परम्पराओं की नींव रखी थी। आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सेनाओं का यहां के लोगों ने तीर-धनुष, भरमार बन्दूक जैसे अपने परम्परागत हथियारों से मुकाबला किया था। लेकिन आखिरकार अंग्रेजी हुकमरानों ने अपने पाशविक बलों के जरिए इस विद्रोह को भी कुचल दिया था। इस विद्रोह का नेता गुण्डाधुर ने बस्तरिया जनता के विद्रोह के संकेत के रूप में जनता के दिलों में अमिट छाप छोड़ी थी।

'भूमकाल' संघर्ष की एक और खासियत यह थी कि लोगों ने आंग्ल-मराठा शासकों द्वारा जारी लूट और उत्पीड़न के खिलाफ लड़कर यह ऐलान किया था कि उनका राज वे खुद ही चलाएंगे। 10 फरवरी को लोगों ने 'माड़िया राज्य' की स्थापना की थी। लेकिन वह बहुत दिनों तक नहीं टिक सका, अतः 12 तारीख तक अंग्रेजी सेनाओं के द्वारा कुचल दिया गया। इस प्रकार 'भूमकाल' विद्रोह को लोगों द्वारा उनकी राज्यसत्ता की स्थापना के लक्ष्य से किया गया विद्रोह भी कहा जा सकता है। आज यहां जनता की जनवादी राज्यसत्ता की स्थापना के मकसद से जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन ने पहली बार इस वर्ष 10 फरवरी को भूमकाल दिवस मनाने का फैसला किया। स्थानीय जन संगठनों ने इस आयोजन के लिए नेलनार गांव का समुचित चुनाव किया क्योंकि इस गांव के कई लोगों ने इस विद्रोह में अपने प्राणों को न्यौछावर किया था।

उस जमाने के उपनिवेशी शासक और आज के दलाल शासक दोनों ने ही इस इलाके के लोगों के विद्रोहों को इतिहास में समुचित जगह न देकर गद्दारी ही की। इतने महान संघर्षों के इतिहास के बावजूद, बाहरी लोगों की नजर में इस इलाके का अभी तक 'अबूझ'माड़ के रूप में रह जाना लुटेरे शासक वर्गों की साजिश का ही नतीजा था। 1980 में दण्डकारण्य में प्रवेश करने वाले क्रान्तिकारी आन्दोलन को यहां तक फैल जाने में पांच साल और लगे थे। 1985 से इस इलाके के लोग कदम-ब-कदम संगठित होते आ रहे हैं। क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रयासों की बदौलत 1999 से यहां की जनता 'अबूझ' शब्द को, जोकि पिछड़ेपन और अपमान का संकेत था, हटाकर बाहरी दुनिया से अपने इलाके को सिर्फ 'माड़' ही कहने की अपील कर रही है। अब बुर्जुवाई मीडिया ने भी इसे 'अबूझ'माड़ न कहते हुए सिर्फ 'माड़' ही कहना शुरू किया है।

स्थानीय जन संगठनों ने लगभग एक माह पहले से ही गांव-गांव और घर-घर जाकर भूमकाल दिवस का प्रचार शुरू किया। डीएकेएमएस और केएएमएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस प्रचार अभियान में भाग लिया। लगभग 50 वलन्टियरों ने सभास्थल में मंच का निर्माण, स्मारक की सजावट आदि कामों में भाग लिया। लगभग 10 एकड़ जमीन को उन्होंने साफ करके इस आयोजन के लिए मैदान बनाया। समूचे सभास्थल को लाल बन्दनवारों और बैनरों से सजाया गया। पीजीए बलों ने इस आयोजन को दुश्मन के संभावित हमले से बचाने के लिए सभी रास्तों पर दिन-रात पहरा लगाया। हालांकि सभास्थल से 25-30 किलोमीटर की दूरी में स्थित नारायणपुर और छोटाडोंगर में तैनात सैकड़ों पुलिस व अर्ध सैनिक बलों ने अपना गश्त अभियान तेज किया था, लेकिन जनता ने पूरी गोपनीयता बरतते हुए दुश्मन को इस आयोजन की जगह के बारे में कुछ भी मालूम न होने दिया। दरअसल यहां की जनता के लिए गोपनीयता बरतना कोई नई बात भी नहीं है। अतीत में हुए विद्रोहों के इतिहास का अध्ययन करने पर यह मालूम पड़ता है कि लोग एक गांव से दूसरा गांव तक बड़ी गोपनीयता के साथ विद्रोह का पैगाम पहुंचाया करते थे। इसी परम्परा को ज्यादा चेतना के साथ आगे बढ़ाते हुए जनता ने पूरी एहतियात बरती ताकि शासक वर्गों और उनके भाड़े के टट्टू बलों को माड़ अंचल में आयोजित अब तक के इस सबसे बड़े कार्यक्रम की भनक तक न लग सके। जन मिलिशिया, जोकि

(शेष पृष्ठ 35 पर ....)